राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 216

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 13 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

बंजर भूमि और सूखे हलक के लिए आस है बूढ़ा-बूढ़ी बांध

औरंगाबाद : बांध का नाम बेशक बूढ़ा-बूढ़ी है, पर इसी की बदौलत आज देव प्रखंड की बंजर भूमि लहलहाने लगी है और सूखे हलक तर हो रहे हैं। यह लोगों की मेहनत का नतीजा है, जिसकी तारीफ कौन बनेगा करोड़पति शो में बिग बी भी कर चुके हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

शरीर में जहां मर्ज, वहीं मार करेगा नैनो कैप्सूल

कानपुर : जहां मर्ज, वहीं मार। जितनी जरूरत, दवा की उतनी ही डिलीवरी। न दूसरे अंगों को नुकसान। यह संभव होगा, नैनो पार्टिकल कैप्सूल से, जिसे आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. प्रणव जोशी और यहां से पोस्ट डॉक्टरेट कर रहीं रिसर्च स्कॉलर ने बनाया है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

दो सौ और लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत

कोलकाता : रक्षा सचिव अजय कुमार का कहना है कि वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने को 200 नए लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोलकाता में कोस्ट गार्ड की निगरानी बोट आइसीजीए अमृत कौर और आसीजीएस एनी बेसेंट के जलावतरण कार्यक्रम में पहुंचे अजय कुमार ने यह जानकारी दी है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

कोच्चि की चारों अवैध बहुमंजिला इमारतें चुटकी में ढेर

कोच्चि : पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोच्चि में समुद्र किनारे आखिरी दो अवैध बहुमंजिला इमारतों को नियंत्रित तरीके से विस्फोट करके कुछ ही सेकेंड में ढहा दिया गया। रविवार को इमारतों को गिराने की मुहिम पूरी हो गई।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने की तैयारी

नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर उद्योग जगत और अर्थविदों से अलग-अलग बैठकें की हैं। शुक्रवार को नीति आयोग के साथ मोदी ने जब कैबिनेट के कई सदस्यों के साथ अर्थव्यवस्था पर बैठक की तो रियल एस्टेट सेक्टर पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा गया।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर फिर आठ रॉकेट दागे गए

बगदाद : खाड़ी में युद्ध जैसे हालात के बीच इराक में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे पर फिर आठ रॉकेट दागे गए हैं। हमले में इराकी वायु सेना के दो अधिकारी और दो सैनिक घायल हुए हैं। इराकी सेना ने कहा है कि बगदाद से 70 किमी उत्तर में स्थित अल-बलाड एयरबेस पर कत्यूशा श्रेणी के आठ रॉकेट गिरे। अल-बलाड अड्डा इराक में अमेरिकी वायु सेना का प्रमुख अड्डा है।

'शिक्षण संस्थानों को वाम विचारधारा के लोगों के उत्पात से बचाएं'

▸ दो सौ से अधिक शिक्षाविदों ने पीएम को पत्र लिख कर कैंपस का माहौल सुधारने के लिए की दखल देने की अपील

▸ चिट्ठी लिखने वालों में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सरदार पटेल और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल

नई दिल्ली, एजेंसियां : 200 से अधिक शिक्षाविदों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में बिगड़ते अकादमिक माहौल के लिए वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक छोटे समूह की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। पत्र लिखने वालों में कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल हैं। इन शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) सहित देशभर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, ताकि जल्द-से-जल्द कैंपस में सौहार्दपूर्ण माहौल बहाल हो सके।

शिक्षाविदों की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है, 'हमारा मानना है कि छात्र राजनीति के नाम पर एक विध्वंसकारी धुर वामपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय (जेएनयू) से लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया तक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से लेकर बंगाल के जाधवपुर विश्वविद्यालय तक परिसरों में हुईं हाल की घटनाएं हमें वामपंथी कार्यकर्ताओं के छोटे से समूह की शरारत के चलते बदतर होते अकादमिक माहौल के प्रति सावधान करती हैं।'

> हम सभी लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होने और अकादमिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विचारों की बहुलता के लिए खड़े होने की अपील करते हैं।
> -शिक्षाविदों के पत्र का अंश

अकादमिक जगत में छिड़ेगी बहस

208 शिक्षाविदों के इस बयान से अकादमिक जगत में नई बहस छिड़ने की उम्मीद है। दरअसल, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और जेएनयू परिसर में हुए हालिया हमले सहित कई मुद्दों के खिलाफ कुछ विश्वविद्यालयों में हुए प्रदर्शनों के चलते सरकार को विद्वानों के एक हिस्से द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

जेएनयू हिंसा के पीछे सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली : जेएनयू प्रकरण पर गठित कांग्रेस की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हिंसा के पीछे सरकार का हाथ बताया है। साथ ही कुलपति एम. जगदीश कुमार को मास्टरमाइंड करार देते हुए उनकी तुरंत बर्खास्तगी की जरूरत बताई है। कमेटी ने कुलपति के सभी फैसलों की समीक्षा करने और हिंसा की अपराधिक जांच की बात भी कही है। (पेज-6)

पत्र में वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले समूहों को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया है कि वामपंथी राजनीति द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के चलते जन संवाद आयोजित करना या स्वतंत्र रूप से बोलना मुश्किल हो गया है। वामपंथियों के गढ़ों में हड़ताल, धरना और बंद आम बात हो गई है।

पत्र में कहा गया है कि वाम विचारधारा के अनुरूप नहीं होने पर लोगों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना, सार्वजनिक छींटाकशी और प्रताड़ना बढ़ रही है। इस तरह की राजनीति से सबसे बुरी तरह से गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इसमें कहा गया है, 'ये छात्र सीखने और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने का अवसर खो देंगे। वे अपने विचारों को प्रकट करने और वैकल्पिक राजनीति की स्वतंत्रता खो देंगे। वे खुद को बहुसंख्यक वाम राजनीति के अनुरूप करने के प्रति सीमित पाएंगे।'

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एचसीएस राठौर और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिरीष कुलकर्णी सहित अन्य शामिल हैं। इसे 'शैक्षणिक संस्थानों में वामपंथी अराजकता के खिलाफ बयान' शीर्षक दिया गया है।

प्रख्यात हस्तियों की संवैधानिक लक्ष्य पूरे करने कही अपील पेज>>5

सीएए से दुनिया ने जाना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन : मोदी

फिर दोहराया ▸ पीएम ने बेलूर मठ में कहा, सीएए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं

कहा, हमने वही किया है जो महात्मा गांधी और अन्य बड़े नेता चाहते थे

जागरण संवाददाता, हावड़ा

स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 'युवा दिवस' पर रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न की लेने के लिए। इसे रातों-रात नहीं बल्कि सोच विचार कर बनाया गया है, लेकिन कुछ सियासी दल इसे जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं और भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर पैदा हुए विवाद ने दुनिया को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन की हकीकत दिखा दी है।

राजभवन की जगह बेलूर मठ में रात गुजारने के बाद रविवार सुबह पूजा-अर्चना के बाद मोदी ने युवाओं की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सीएए को लेकर युवाओं में बड़ी चर्चा है। बहुत से सवाल उनके मन में भर दिए गए हैं। बहुत से युवा अफवाहों के शिकार हुए हैं। उन्हें समझाना और संतुष्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मौजूद युवाओं से पूछा कि क्या सीएए गलत है? जब किसी को नागरिकता दी जाएगी, किसी का छीना नहीं जाएगा तो फिर गलत क्यों? सभा ने करतल ध्वनि से इसका समर्थन किया।

नॉर्थ ईस्ट पर असर नहीं पड़ेगा : मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट हमारा गौरव है। वहां की संस्कृति, रीति-रिवाज, जनसंख्या पर सीएए का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इसका पूरा ख्याल केंद्र सरकार ने रखा है।

दूसरे देश का कोई भी नागरिक नागरिकता ले सकता है : पीएम ने कहा, किसी भी देश या धर्म का व्यक्ति उचित प्रक्रिया से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नया कानून बंटवारे की वजह से दूसरे देशों में प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है। पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर धर्म की वजह से अत्याचार किया जा रहा है। यह कानून लाकर हमने वही किया है जो गांधी जी कहकर गए थे।

युवा जोश से बदलेगा भारत पेज>>3

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में युवाओं को संबोधित किया। एएनआइ

बेलूर मठ को बताया अपना 'घर'

मोदी ने कहा, विवेकानंद की वाणी और उनका व्यक्तित्व बेलूर मठ खींचकर ले आता है। यहां मां शारदा देवी का आंचल मां का प्यार देता है। यहां आना 'घर' आने जैसा है। यहीं से मुझे जनसेवा का रास्ता मिला था और अब मैं 130 करोड़ भारतीयों की सेवा का कर्तव्य निभा रहा हूं।

> यह युवा सोच ही है, जो कहती है कि समस्याओं को टालो नहीं, उनसे टकराओ, उन्हें सुलझाओ। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही भटके लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है।
> -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कितना भी विरोध करें, शरणार्थियों को नागरिकता देकर रहेंगे : शाह

जबलपुर : गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस सीएएस पर देश को गुमराह कर रही है। वह कितना भी विरोध करें, हम भारत में बसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। भारत पर जितना हक मेरा-आपका है, उतना ही उन शरणार्थियों का है। मानवाधिकार के चैंपियनों को पाकिस्तान में दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और प्रताड़ित हो रहे लाखों-करोड़ों लोग दिखाई नहीं देते। (पेज-5)

आईशी घोष समेत तीन से आज होगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ वाट्सएप ग्रुप में शामिल 37 छात्रों को भी भेजा नोटिस

▸ सर्वर रूम में तोड़फोड़ मामले में भी क्राइम ब्रांच शुरू करेगी जांच

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। डीसीपी जॉय टिर्की के नेतृत्व में गठित एसआइटी सोमवार को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े दो अन्य छात्रों से पूछताछ करेगी। तीनों को पूर्वाह्न 11.30 बजे जेएनयू में उपस्थित रहने को कहा गया है।

एसआइटी ने शनिवार को वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े सात और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों से जुड़े दो छात्रों को पूछताछ में शामिल होने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा था। एसआइटी ने शुक्रवार को इन सभी के फोटो जारी करते हुए दावा किया था ये लोग पांच जनवरी को जेएनयू परिसर में हुई हिंसा में शामिल थे। जॉय टिर्की का कहना है कि पूछताछ में अगर नए छात्रों के नाम सामने आते हैं तो उन्हें भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। इस हफ्ते सभी नौ छात्रों से पूछताछ की जाएगी। वाट्सएप ग्रुप में शामिल 37 छात्रों को पूछताछ के लिए अगले रविवार को बुलाया गया है। वाट्सएप ग्रुप में शामिल अन्य की पहचान का सिलसिला जारी है।

जेएनयू के प्रशासनिक भवन के सर्वर रूम में तोड़फोड़ मामले में भी सोमवार से जांच शुरू होगी। अलग टीम मामले की जांच करेगी। इस मामले में भी आईशी शामिल थीं। एक निजी टीवी चैनल द्वारा अक्षत, रोहित और कोमल का स्टिंग दिखाने के मामले में भी एसआइटी ने तीनों से पूछताछ की पर खास जानकारी नहीं मिली। (पेज-7 भी देखें)

शाहीन बाग धरने के विरोध में सड़क पर उतरे स्थानीय लोग

कालिंदी कुंज मार्ग खुलवाने के लिए सरिता विहार से मथुरा रोड पर जाते स्थानीय लोग। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ शाहीन बाग रोड बंद होने के 28वें दिन टूटा लोगों के सब्र का बांध

सीएए के विरोध में गत 28 दिनों से शाहीन बाग में चल रहे धरने के कारण रोड बंद होने से परेशान स्थानीय लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। रविवार सुबह खिजराबाद, तैमूर नगर, सराय जुलैना, भरत नगर, जसोला, मदनपुर खादर, बदरपुर, जैतपुर, मीठापुर, सरिता विहार, जेजे कॉलोनी, तुगलकाबाद और कई अन्य गांवों व कॉलोनियों के लोग सड़क पर उतर आए। दिल्ली पुलिस रोड खुलवाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए भीड़ डीसीपी ऑफिस की तरफ बढ़ी। पुलिस के रोकने पर कहा, धरने के कारण दिल्ली, उप्र व हरियाणा के हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता खुलवाने का आश्वासन देने पर पदयात्री शांत तो हुए लेकिन कालिंदी कुंज-सरिता विहार रोड खोलने की मांग करते हुए मथुरा रोड और फिर मदनपुर खादर मार्ग जाम करने पहुंच गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों जगह से लोगों को खदेड़ा।

डीएसपी और आतंकियों में हुई थी 12 लाख की डील

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▸ आतंकियों को चंडीगढ़ ले जाने वाला था डीएसपी देविंदर सिंह, हथियारों की डील भी करानी थी, सात ठिकानों पर मारे गए छापे, हथियार भी बरामद

▸ आतंकवादियों के साथ पकड़े गए डीएसपी से हो रही है गहन पूछताछ, जांच में पुलिस को कई जानकारियां मिलीं, बड़े मामलों का हो सकता है पर्दाफाश

कश्मीर के कुलगाम में दो आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि डीएसपी की कार में सवार दोनों आतंकियों से कथित तौर पर 12 लाख में डील हुई थी। इसके बदले वह उन आतंकियों को सुरक्षित चंडीगढ़ ले जाने वाला था। इतना ही नहीं अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने बकायदा चार दिन की छुट्टी भी ले ली थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस और आतंकियों के गठजोड़ से सुरक्षा एजेंसियां भी चकरा गई हैं। ऐसे में इनकी साठगांठ की परतें अब आइबी और रॉ जैसी केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त जांच में खुलेंगी।

सूत्रों की मानें तो कुख्यात आतंकियों के लिए हथियारों की डील करवाने का जिम्मा भी डीएसपी के पास ही था। अभी इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस दौरान बड़े मामले खुल सकते हैं। वहीं, पूछताछ के आधार पर सुरक्षाबलों ने श्रीनगर के खमनू और बड़गाम समेत कश्मीर में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। कुख्यात आतंकी नवीद की निशानदेही पर कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अभी इस संबंध में कुछ भी बताने से बच रही हैं। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। रविवार को राज्य पुलिस के महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि देविंदर ने जघन्य अपराध किया है। वह श्रीनगर एयरपोर्ट जैसे अति संवेदनशील जगह पर तैनात था। शनिवार तक अंदाजा भी नहीं था कि वह ऐसे मामले संलिप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी पुलिस को इसके लिए दोषी ठहराना गलत है।

जम्मू के सांबा में होनी थी डील : बताया जा रहा है कि नवीद और उसके साथी के साथ हथियारों की डील संभवतः सांबा में ही होनी थी। इसके बाद दोनों आतंकी कुछ माह चंडीगढ़ में ठहरने वाले थे। अफसरों के अनुसार पूछताछ के आधार पर ही उनके मंसूबों का पता चल सकेगा। वहीं, डीएसपी के आवास से नकदी भी बरामद हुई है।

नवीद ने भाई को किया था फोन : सूत्रों का कहना है कि नवीन ने रवाना होने से पहले अपने भाई को फोन किया था। वह फोन भी पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों ने सर्विलांस पर रखा हुआ था। इसके आधार पर मिली पुख्ता सूचना के बाद ही वाहन को रोका गया था।

शनिवार को पकड़े गए दो आतंकियों में एक पुलिस भगोड़ा भी पेज>>7

डीएसपी देविंदर सिंह। प्रेट्र

रिपोर्ट

उद्योगों के कुल एनपीए के करीब पहुंची कृषि कर्ज माफी

> पिछले एक दशक में माफ हुआ 4.7 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज, 2017 के बाद सबसे ज्यादा दो लाख करोड़ रुपये की हुई कर्ज माफी, कृषि कर्ज माफ करने के मामले में कमोबेश हर राज्य ने दिखाई दरियादिली

मुंबई, प्रेट्र : आर्थिक सुस्ती के वर्तमान दौर में हर उद्योग किसी न किसी रूप में वित्तीय दबाव में है और मदद के लिए सरकार की ओर ताक रहा है। आगामी बजट में इकोनॉमी को गति देने के सभी प्रयासों पर विचार किया जा रहा है। लगभग सभी उद्योग का कहना है कि सरकार अगर थोड़ी भी वित्तीय मदद दे, तो वह इकोनॉमी को मजबूती देने की हालत में आ सकता है। दूसरी तरफ, अक्सर किसानों-खेतिहरों को लेकर सरकारों की राजनीतिक दरियादिली में लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं, लेकिन रोग लाइलाज रहा है। एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न राज्यों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफ किए हैं।

देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की सहयोगी शाखा एसबीआइ रिसर्च ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसके मुताबिक पिछले एक दशक में किसानों को जितनी रकम कर्ज माफी के रूप में बांट दी गई है, वह उद्योग जगत के पूरे फंसे कर्ज (एनपीए) का करीब 82 प्रतिशत है। एसबीआइ रिसर्च की यह रिपोर्ट कहती है कि कृषि कर्ज का एनपीए 2018-19 में बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह इस वक्त देश के सभी वित्तीय संस्थानों के 8.79 लाख करोड़ रुपये के एनपीए का 12.4 प्रतिशत है। चार वर्ष पहले यानी वित्त वर्ष 2015-16 में यह 8.6 प्रतिशत ही था।

रिपोर्ट में साफ कहा गया कि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल एनपीए में कृषि क्षेत्र का हिस्सा महज 1.1 लाख करोड़ रुपये यानी 12.4 प्रतिशत का ही है। लेकिन यदि हम पिछले दशक में 3.14 लाख करोड़ रुपये के माफ किए गए किसानों के कर्ज को जोड़ें तो खजाने पर इनका बोझ 4.2 लाख करोड़ रुपये हो जाता है। यदि महाराष्ट्र में 45-51 हजार करोड़ रुपये की हालिया कर्ज माफी को जोड़ दें तो यह और बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपये हो जाता है, जो उद्योग जगत के एनपीए का 82 प्रतिशत है।'

वित्त वर्ष 2014-15 के बाद 10 बड़े राज्यों ने किसानों के तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज माफ किए हैं। यदि मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 में की गई कर्ज माफी को जोड़ दें तो यह बढ़कर करीब चार लाख करोड़ रुपये हो जाता है। इसमें दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि कर्ज 2017 के बाद माफ किए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समय-समय पर किसानों के कर्ज माफ किए। हालांकि अधिकतर कर्ज माफी धरातल के बजाय कागजों पर ही अधिक हुई हैं। इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक कर्ज माफ नहीं किए जा सके हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

वीआइपी सुरक्षा से हटाई जाएगी एनएसजी

▸ आतंकवाद रोकने और विमान अपहरण के खिलाफ अभियान पर ध्यान देने के लिए मिलेगा ज्यादा समय

▸ सीमित और विशिष्ट क्षमताओं पर बोझ साबित हो रही थी वीआइपी सुरक्षा की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वीआइपी सुरक्षा में व्यापक कटौती करने और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद केंद्र सरकार ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को इस काम से पूरी तरह मुक्त करने का फैसला किया है। करीब दो दशक बाद ऐसा होगा कि आतंकवाद निरोधी विशिष्ट बल के 'ब्लैक कैट' कमांडो को वीआइपी सुरक्षा ड्यूटी से हटाया जाएगा। इस बल का जब गठन हुआ था तब इसके मूल कामों में वीआइपी सुरक्षा शामिल नहीं थी। यह बल 'जेड-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त 13 'उच्च जोखिम' वाले वीआइपी को सुरक्षा देता है। इस सुरक्षा घेरे में अत्याधुनिक हथियारों से लैस करीब दो दर्जन कमांडो हर वीआइपी के साथ होते हैं।

सूत्रों ने कहा, गृह मंत्रालय का मानना है कि एनएसजी को अपना ध्यान मूल काम आतंकवाद को रोकने और विमान अपहरण के खिलाफ अभियान पर केंद्रित करना चाहिए। बंधक बनाने की आपात स्थिति में भी एनएसजी कमांडो कार्रवाई करते हैं। वीआइपी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी सीमित व विशिष्ट क्षमताओं पर बोझ साबित हो रही थी। सुरक्षा संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एनएसजी को आतंकवाद निरोधी और विमान अपहरण विरोधी अपने मूल दायित्वों को देखने के जरूरत है।

अधिकारियों ने कहा, वीआइपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाने से 450 कमांडो मुक्त होंगे, जिनका इस्तेमाल देश में बने इनके पांच ठिकानों में इनकी मौजूदगी को और सुदृढ़ करने में किया जाएगा। एनएसजी सुरक्षा प्राप्त वीआइपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) को सौंपी जा सकती है। सीआरपीएफ को हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व उनकी पत्नी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल व प्रियंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बल के पास लोस अध्यक्ष ओम बिरला की सुरक्षा का भी जिम्मा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआइएसएफ के पास है।

इन्हें मिली है एनएसजी सुरक्षा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनएसजी सुरक्षा प्रदान करता है। पूर्व मुख्यमंत्रियों-मायावती, मुलायम सिंह यादव, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल, फारुक अब्दुल्ला, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी एनएसजी सुरक्षा मिली हुई है।

ऐसे हुई स्थापना पेज>>7

14 जनवरी को जारी होगी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 21 है। 22 को नामांकन के लिए दाखिल आवेदनों की जांच और छंटनी होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 13 जनवरी 2020

हरियाणा के असर से अछूता नहीं रहेगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

दिल्ली के चुनावी रण में हरियाणा के राजनेता ताल ठोकने को तैयार हैं। दिल्ली राज्य की एक तिहाई विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिन पर हरियाणा की भाषा-संस्कृति, माहौल, व्यापारिक कामकाज और राजनीति का सीधा असर पड़ता है। बाहरी दिल्ली की अधिकतर सीटें हरियाणा कनेक्शन की वजह से प्रभावित हैं। इन सीटों पर किसी भी राजनीतिक दल की हार-जीत दिल्ली सरकार के गठन में अहम भूमिका निभा सकती है।

दिल्ली के चुनाव को देखते हुए तमाम दलों ने अपनी-अपनी पार्टी के हरियाणा से जुड़े नेताओं को सक्रिय कर दिया है। भाजपा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद दिल्ली चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। संगठन ने पूर्व मंत्री एवं प्रमुख जाट नेता ओमप्रकाश धनखड़ पर भी भरोसा जताया है। भाजपा हरियाणा के करीब तीन दर्जन नेताओं की दिल्ली के चुनाव में ड्यूटी लगा चुकी है। दिल्ली में इस्तेमाल की जाने वाली पार्टी की रणनीति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार भाजपा हाईकमान के संपर्क में हैं।

मुख्यमंत्री की भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से दो बार मुलाकात हो चुकी है। हरियाणा के दोनों केंद्रीय मंत्रियों कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत, पूर्व मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह और सभी आठ सांसदों को दिल्ली के रण में उतारने की योजना है। हरियाणा में भाजपा की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी इस बार दिल्ली के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। जजपा पहले ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो का ही पार्ट हुआ करती थी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के बाद दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बना ली। दुष्यंत यदि दिल्ली के रण में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उनकी कोशिश भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है।

भाजपा दिल्ली में कई सीटों पर जातीय समीकरण साधने में जुटी है। भाजपा के कई जाट नेता नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में दुष्यंत चौटाला को साथ लिया जाए, लेकिन हाईकमान की रणनीति ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। भाजपा हाईकमान को लगता है कि बाहरी दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं, जहां यदि जाट वोट मिल गए तो पार्टी की जीत संभव है। लिहाजा न चाहते हुए भी भाजपा दिल्ली चुनाव में जजपा को साथ जोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भाजपा के बुलावे के इंतजार में दुष्यंत चौटाला दिल्ली में अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार आरंभ कर चुके हैं।

दिल्ली में आप का सबसे बड़ा हरियाणा कनेक्शन है, क्योंकि मौजूदा सरकार में ही आप के ऐसे दस से अधिक विधायक हैं, जिनकी पृष्ठभूमि हरियाणा से जुड़ी है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की टीम हरियाणा को पूरी मुस्तैदी से चुनावी रण में उतारने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष पंडित नवीन जयहिंद अपनी टीम की बैठक ले चुके हैं। टीमों को आजकल में योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के रण में उतार दिया जाएगा। नवीन जयहिंद दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति जयहिंद के पति हैं।

कांग्रेस हाईकमान भी हरियाणा के प्रमुख नेताओं को दिल्ली के रण में उतारने को तैयार है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 जनवरी को अपने दिल्ली निवास पर लोहड़ी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें कांग्रेस के कई राष्ट्रीय व दिल्ली के नेता शामिल हो सकते हैं। यहां दोपहर के भोज पर दिल्ली के चुनाव की रणनीति को दिशा मिल सकती है। कांग्रेस दिल्ली में सक्रिय रह चुकीं कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी रण में उतारने वाली है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

नवीन जयहिंद।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा

दुष्यंत चौटाला। जागरण आर्काइव

भाजपा का हथियार दुष्यंत, कांग्रेस को हुड्डा से आस

दिल्ली पर हरियाणा का प्रभाव होने की वजह से हर पार्टी की नजर ऐसे नेताओं पर है, जो जाट मतों को अपने पक्ष में करने का कूबत रखते हों। ऐसे में भाजपा दिल्ली में हरियाणा के सहयोगी दुष्यंत चौटाला को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है तो कांग्रेस की आस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप के हरियाणा अध्यक्ष नवीन जयहिंद को बाहरी दिल्ली की सीटों के प्रचार का जिम्मा सौंपा है।

इन सीटों पर हरियाणा का खासा प्रभाव

दिल्ली की बवाना, मुंडका, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, छतरपुर, बदरपुर, नागलोई, मटियाला, बादली, नरेला, बुराड़ी, रिठाला, देवली, किराड़ी और उत्तमनगर सीटें ऐसी हैं, जिन पर हरियाणा के लोगों की अहम भूमिका समझी जाती है। ये विधानसभा सीटें दिल्ली की रिंग रोड के बाहर इलाके में आती हैं। इन सीटों पर प्रत्याशी की हार जीत में हरियाणा के लोगों की अहम भूमिका रहती है।

दिल्ली के विकास के लिए चाहिए नीति और नीयत : दुष्यंत चौटाला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जननायक जनता पार्टी के मुखिया और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दिल्ली का विकास करने के लिए नीति और नीयत चाहिए, जो पांच साल तक दिखाई नहीं दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो विकास कार्यों को छोड़कर पांच साल तक सिर्फ टकराव ही करते रहे। दुष्यंत पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ के सोम बाजार प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे।

दुष्यंत ने कहा कि दिल्ली देहात के स्कूल नहीं बने, कालेजों में कोई नया ग्रेड लागू नहीं हुआ। दिल्ली की सरकार बिल्डरों को कॉलोनी बनाने के लिए जगह दे रही है। लेकिन गांव के लोगों को लालडोरा से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास की बात करते हैं, लेकिन पांच साल में आप सरकार द्वारा कराया गया विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं देता है। पांच साल में मैने भी दिल्ली में कुछ भी बदलते हुए नहीं देखा है।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोशनपुरा गांव के लोगों ने दस एकड़ से ज्यादा जमीन कॉलेज के लिए दी है। लेकिन आज तक यहां पर कॉलेज नहीं बना। नजफगढ़ के लोग लगातार जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका कहीं कोई समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की टकराव की नीति की वजह से नजफगढ़ को मेट्रो भी देर से मिली। इस तरह की विकास की उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। दिल्ली के विकास के लिए नीति और नीयत की जरूरत है। उपमुख्यमंत्री चौटाला ने इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती देने की जरूरत है। इसके लिए कार्यकर्ता हर बूथ और हर घर तक पहुंचें। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय विधायक भरते को जिताने के लिए काम किया था। उसी तरह से चुनाव प्रचार में लग जाएं।

70 सीटों पर उतार सकते हैं प्रत्याशी : चौटाला ने कहा कि पश्चिमी व बाहरी दिल्ली के अधिकांश गांव और कॉलोनियों में रहने वालों का हरियाणा से गहरा संबंध है। प्रमुख तौर पर इन 12 विधानसभा क्षेत्रों सहित दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है। प्रत्याशियों के चयन के लिए पांच समितियों का गठन किया गया है।

चुनावी हलचल

चुनाव हैं, हैदराबाद नहीं जा सका : केजरीवाल

नई दिल्ली : दिल्ली की सत्ता में और अधिक सीटों के साथ वापसी के लिए जुटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि आज आइआइटी खड़गपुर के मेरे साथी हैदराबाद में एकत्रित हो रहे हैं। मुझे भी आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में चुनाव हैं इसलिए मैं नहीं पहुंच सका। इससे पहले केजरीवाल ने आइआइटी के समय के अपने दोस्तों से लाइव बात की। दूसरी ओर जब दूसरे दल अभी तक चुनाव का माहौल भी नहीं बना पाए हैं, आप का थीम सांग लगे रहो केजरीवाल लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। (राब्यू)

कांग्रेस व बसपा के नेता आप में शामिल

नई दिल्ली : कांग्रेस में लंबे समय तक रहे राजपाल बघेल आप में शामिल हो गए। बघेल को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्हें प्रदेश ओबीसी विंग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह कोंडली वार्ड से निगम पार्षद रह चुकीं बहुजन समाज पार्टी की नेता कुमारी प्रियंका गौतम, पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के दुष्यंत यादव, शैक्षिक और कल्याणकारी ट्रस्ट श्रीविजय मेमोरियल राष्ट्रीय शिक्षा समिति के संस्थापक और अध्यक्ष अतुल शर्मा ने भी आप की सदस्यता ली है। (राब्यू)

भाजपा ने केजरीवाल को भेजा 500 करोड़ का नोटिस

आरोप ▶ मनोज तिवारी की फिल्मों के वीडियो का प्रचार में किया उपयोग

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, अपने थीम सांग पर मेरी फोटो लगाकर प्रसारित करने का हक किसने दिया?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की फिल्मों के वीडियो को प्रचार में उपयोग करने का आरोप लगाकर भाजपा ने मानहानि का नोटिस भेजकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम से नोटिस भेजकर 500 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की है।

मनोज तिवारी ने कहा कि कलाकार रहते हुए मैंने जो फिल्में और गाने किए, उनकी क्लीपिंग और तस्वीरों को एडिट करके आम आदमी पार्टी के गाने पर लगाकर केजरीवाल ने अपने ओछेपन का सुबूत दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अपने थीम सांग पर मेरी फोटो लगाकर प्रसारित करने का हक आप (केजरीवाल) को किसने दिया? क्या आपको यह नहीं पता कि व्यावसायिक तौर पर किसी की फोटो को बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं?

मनोज तिवारी। (फाइल)

तिवारी ने कहा कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव में अपनी हार की आशंका को देखते हुए इतने बौखला गए हैं कि विज्ञापन के लिए अब वह बच्चों, मजदूरों, महिलाओं की फोटो और वीडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का समर्थन न मिलने से आप के नेता और कार्यकर्ता हताश हो चुके हैं। केजरीवाल की सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है इसलिए भीड़ जुटाने के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं।

प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी ने कहा कि मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी हैं। उनका नाम और चेहरा अपने आप में एक ब्रांड है। उनकी फिल्मों और गानों की क्लीपिंग का राजनीतिक इस्तेमाल किया और उसका वीडियो बनाकर पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। इसके लिए इन फिल्मों और म्यूजिक वीडियो के निर्माता और निर्देशकों से भी इजाजत नहीं ली गई, जो कि प्रोपराइटर राइट्स का उल्लंघन है। बक्शी ने यह भी कहा कि इस वीडियो को जारी करने से यह भी साबित हो गया कि लोग अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मनोज तिवारी को पंसद करते हैं। इसलिए आप ने उनके फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया।

डीडीए ने फ्लैट देने के नाम पर किया घोटाला : संजय सिंह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गरीबों को फ्लैट देने के नाम पर डीडीए ने बड़ा घोटाला किया है। जिस फ्लैट को 6.90 लाख में देने का वादा किया गया था, उसके दाम केंद्र की सहमति से डीडीए ने तीन गुना बढ़ाकर वसूले हैं। उन्होंने इस बारे में सीबीआइ और केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत कर जांच की मांग की है।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संजय सिंह ने बताया कि डीडीए ने 2014 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में फ्लैट की स्कीम निकाली थी। इसमें 6.90 लाख रुपये में फ्लैट देने का वादा किया गया था। इस स्कीम में एक निजी कंपनी भी शामिल थी। स्कीम उन लोगों के लिए थी, जिनकी आय सालाना एक लाख से कम थी। इस योजना के तहत 772 लोगों को फ्लैट दिया जाना था। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार की सहमति से डीडीए ने गुपचुप तरीके से फ्लैट के रेट 19 से 24 लाख रुपये तक बढ़ा दिए। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर प्रधानमंत्री तक को थी। आरोप लगाया कि इससे साबित होता है कि घोटाला और भ्रष्टाचार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और केंद्र सरकार की सहमति थी।

संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ तो पूरी भाजपा और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी गली-गली घूम कर गरीबों को घर देने का ढोल पीटते हैं, कच्ची कॉलोनियों को नियमित कराने का ढिंढोरा पीटते हैं, गरीबों को मकान की पक्की रजिस्ट्री देने का दावा करते हैं। दूसरी ओर पुरी जी के अधीन आने वाला डीडीए ईडब्ल्यूएस कोटे में आने वाले गरीब लोगों को मिलने वाले फ्लैटों में बड़ा घोटाला करता है।

पत्रकारों से बात करते संजय सिंह। जागरण

फ्लैट तैयार होने के बावजूद डीडीए ने जानबूझकर इस योजना की स्कीम को लटका कर रखा। डीडीए और स्कीम में शामिल एक निजी कंपनी के बीच सांठगांठ से एक समझौता हुआ और जो फ्लैट 6 लाख 90 हजार से लेकर 11 लाख का था। उस फ्लैट के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आने वाले लोगों से 19 लाख से लेकर 24 लाख तक मांगे गए। जब उपराज्यपाल के आवास पर धरना दिया गया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई तो डीडीए ने 19 लाख को घटाकर 15 लाख कर दिया।

भाजपा शासित नगर निगम देश में सबसे भ्रष्ट : सुभाष चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ कहा, निगमों की भ्रष्ट नीतियों के चलते जनता है त्रस्त

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि देश के 205 नगर निगमों में भाजपा शासित दिल्ली के नगर निगम सबसे भ्रष्ट हैं। चोपड़ा रविवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली की तीनों निगमों के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी करते हुए बोल रहे थे।

चोपड़ा ने कहा कि तीनों नगर निगम की भ्रष्ट नीतियों के चलते जनता त्रस्त है। सीलिंग से लाखों लोग प्रभावित हैं और निगम गैरकानूनी सीलिंग करने के साथ-साथ इसे रोकने की आड़ में भी लोगों से अवैध रूप से करोड़ों रुपये वसूल रहा है। चोपड़ा ने भवन विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज दिल्ली में एक भी मकान बिना रिश्वत लिए नहीं बन पा रहा है। चोपड़ा के साथ मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भी आरोप लगाया कि नगर निगम ने महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को भी तीनों सदनों में आज तक नहीं रखा। इससे यह साबित होता है कि गृह कर, भवन विभाग, पेंशन व अन्य मदों में 5000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला है। इसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए।

तीनों नगर निगमों में कांग्रेस के नेता मुकेश गोयल, अभिषेक दत व कुमारी रिंकू ने आंकडों के हवाले से कहा कि 1472 मामलों में से सिर्फ 77 मामलों का ही आंतरिक ऑडिट करवाया गया, जिसमें लगभग 33 लाख रुपये का घोटाला पाया गया। सभी 1472 मामलों का सच सामने आ जाता तो यह राशि 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक होती। रिंकू ने कहा कि पूर्वी दिल्ली में कूड़ा उठाने के नाम पर 215 करोड़ का घोटाला किया गया। सदन की मंजूरी के बिना ऐसी कारों को अनुबंधित किया गया है, जो प्रदूषण फैलाती हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ हैं।

मुकेश शर्मा ने एक सवाल के जवाब में केजरीवाल सरकार के प्रचार अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि सूरते हाल, कर दिया खराब दिल्ली का, अब चले जाओ केजरीवाल। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने अच्छे दिन का नारा दिया व केजरीवाल कह रहे हैं, अच्छे दिन बीते, दोनों ही जुमला साबित हुए हैं। दिल्ली की जनता आगामी चुनाव में इन जुमलों का जवाब कांग्रेस को सत्ता में लाकर देगी।

टिकट देने में जल्दबाजी नहीं, फूंक-फूंककर कदम रख रही कांग्रेस

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने की तिथि सिर पर आ जाने के बावजूद कांग्रेस जल्दबाजी के मूड में नहीं है। टिकट देने में फूंक-फूंककर कदम रखा जा रहा है। हालांकि बहुत से उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और कुछ की टिकट काट भी दी गई है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा करने से पहले पार्टी थोड़ा और चिंतन-मनन करना चाह रही है। इसीलिए सोमवार को दोबारा सभी नामों पर विचार किया जाएगा।

मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 21 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में पार्टी ने शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की केंद्रीय कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद 70 में से 20 सीटों उम्मीदवार घोषित करने की योजना बनाई थी। बैठक में 20 में से 13 नामों पर स्वीकृति की मुहर भी लग गई, लेकिन दैनिक जागरण ने शनिवार के अंक में ही इस सूची के अधिकतर नाम प्रकाशित कर दिए थे। इसके बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में गुटबाजी भी शुरू हो गई थी, अतः इनकी घोषणा रोक दी गई।

इन 13 नामों को मिली स्वीकृति

सीलमपुर से चौ. मतीन अहमद, मुस्तफाबाद से हसन अहमद के बेटे अली मेंहदी, बवाना से सुरेंद्र कुमार, जंगपुरा से तलविंद्र मारवाह, सुल्तानपुर माजरा से जयकिशन, समयपुर बादली से देवेंद्र यादव, वजीरपुर से हरिकिशन जिंदल, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, नांगलोई से डा. विजेंद्र सिंह, बल्लीमारान से हारून यूसुफ, बिजवासन से विजय लोचव, मॉडल टाउन से कुंवर करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला और तिलक नगर से पीएस बावा के नाम पर सीडब्ल्यूसी से स्वीकृति मिलने की बात कही जा रही है।

इन सीटों पर भी उम्मीदवार लगभग तय

गांधी नगर से अरविंदर सिंह लवली, विकासपुरी से मुकेश शर्मा और कालकाजी से शिवानी चोपड़ा का नाम भी तय माना जा रहा है।

इन नामों पर लगी रोक

कृष्णा नगर से डॉ. एके वालिया, तिमारपुर से कप्तान सिंह या प्रेमलता सांगवान, हरि नगर से सुभाष सेतिया और चांदनी चौक से अलका लांबा का नाम तय होने के बाद विरोध के कारण फिलहाल रोक लिया गया है।

कुछ उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, कुछ पर विचार चल रहा है। हमारी कोशिश तो यही है कि सभी नाम एक साथ घोषित कर जाएं। अलबत्ता, पहली सूची बहुत जल्द जारी हो जाएगी। **–सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस**

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को सीडब्ल्यूसी की दोबारा बैठक होगी जिसमें स्वीकृत हुए नामों पर भी फिर विचार किया जाएगा। संभावना है कि सोमवार देर रात तक या मंगलवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी।

नेताओं संग कलाकार भी उतरेंगे मतदाताओं को लुभाने

पार्टियों की रणनीति

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

अगले कुछ दिनों में दिल्ली के चुनावी अखाड़े में भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए भोजपुरी व अन्य कलाकार दिल्ली आएंगे।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य नेता इन दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें चुनाव प्रबंधन की बारीकियां समझा रहे हैं। 14 जनवरी को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके साथ ही उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देगी। उसके बाद चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप देने में लगी हुई है।

भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री से भी चुनावी सभा के लिए समय लिया जा रहा है। कोशिश है कि उनकी तीन से चार रैलियां आयोजित की जाएं। इसी तरह से शाह की सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक-एक रैली कराने का प्रस्ताव है। इनके साथ ही नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।

दिल्ली में सभी राज्यों के लोग रहते हैं। इसे ध्यान में रखकर अलग-अलग राज्यों के नेता भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चुनाव प्रचार करेंगे।

दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व सांसद रवि किशन के साथ ही भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल भी वोट मांगते नजर आएंगे। साथ ही हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी भाजपा के लिए वोट मांगेंगी।

विश्व पुस्तक मेला

मेले के अंतिम दिन पुस्तक प्रेमी की काफी भीड़ रही, साहित्य कार्यक्रमों में भी लोगों का उत्साह दिखा

अंतिम दिन हर स्टाल पर पसंदीदा पुस्तक खोज रहे थे पाठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

28वें विश्व पुस्तक मेले के अंतिम दिन रविवार को भी प्रगति मैदान में पुस्तक प्रेमियों की काफी भीड़ रही। दिन भर मेले के हर मंडप में खासी रौनक दिखी। सुबह से ही पाठकों की भीड़ जुटने लगी। दोपहर तक तो किसी भी हॉल में प्रवेश पाना कठिन हो गया। सभी हॉल में पुस्तक प्रेमी लंबी लाइनों में प्रवेश करते नजर आए। साहित्यिक कार्यक्रमों में भी पुस्तक प्रेमियों का उत्साह दिखा।

रविवार को कमोबेश ज्यादातर स्टालों पर लोग पसंदीदा पुस्तक खोजने में जुटे थे। प्रकाशकों ने भी अंतिम दिन होने के कारण छूट का दायरा बढ़ दिया था। कहीं से 25 से 40 फीसद तक थी तो कहीं 50 फीसद से भी ज्यादा। कई स्टॉलों पर रविवार को किताबों की सेल लगी थी। बच्चे जहां कार्टून चरित्रों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए, वहीं युवक-युवतियां भी कई जगह सेल्फी लेते दिखाई दिए।

विश्व पुस्तक मेले के अंतिम दिन अपनी पसंद की किताब ढूंढ़ते लोग। पारस कुमार

जलसा घर में हुए एक साथ कई लोकार्पण : राजकमल प्रकाशन के जलसा घर में उपन्यास आईना साज का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में लेखिका अनामिका के साथ साहित्यकार प्रभात रंजन शामिल थे। जिन किताबों का लोकार्पण किया गया, उनमें उमा शंकर चौधरी की दिल्ली में नींद, प्रत्यक्षा सिन्हा की ग्लोब के बाहर लड़की और अनुपम मिश्र के लेखों का संग्रह विचार का कपड़ा और बिन पानी सब सून शामिल है। किताबों में साहित्यकार स्वयं प्रकाश की प्रतिनिधि कहानियां भी शामिल हैं।

लोकार्पण एवं परिचर्चा : वाणी प्रकाशन ग्रुप के स्टॉल पर भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक व लेखक अभय कुमार दुबे की समाज विज्ञान पर आधारित पुस्तक 'हिंदू-एकता बनाम ज्ञान की राजनीति' का लोकार्पण व परिचर्चा की गई। कार्यक्रम में लेखिका शीला डागा, लेखक सूर्यनाथ सिंह और प्रकाशक अरुण माहेश्वरी की उपस्थिति रही। लेखक सूर्यनाथ सिंह के कहानी संग्रह 'कोई बात नहीं' और सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखिका शीला डागा की पुस्तक किन्नर गाथा का लोकार्पण भी हुआ।

आलोचना पुस्तक का लोकार्पण : यश प्रकाशन के स्टॉल पर युवा आलोचक दिनेश कुमार माली की पुस्तक 'राधामाधव : एक समग्र चिंतन' का लोकार्पण 'राधामाधव' महाकाव्य के सर्जक कवि उद्भ्रांत, मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ आलोचक डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय एवं आलोचक डॉ. रामप्रकाश कुशवाहा ने किया।

लघुकथा संग्रह 'नमक' भी रहा चर्चा में : युवा लेखिका हिमानी के लघुकथा संग्रह 'नमक' भी पाठकों में चर्चा का केंद्र रहा। ऑथर्स प्राइड से प्रकाशित इस किताब में एक से दो पेज की 80 कहानियां हैं, जो परत दर परत जिंदगी के अनछुए, लेकिन जाने-पहचाने से लम्हों को आंखों के सामने आकार देती नजर आती है।

10 लाख पाठक, करोड़ों का कारोबार

28 वें विश्व पुस्तक मेले ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का रिकार्ड भी तोड़ दिया। मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों की संख्या व्यापार मेला दर्शकों से ज्यादा रही। शनिवार-रविवार को तो मेले में पाठकों को लंबी कतारों से होकर प्रवेश करते देखा गया। मेला आयोजक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुताबिक नौ दिन के मेले में करीब 10 लाख पाठक पहुंचे। पुस्तकों की बिक्री का आंकड़ा भी करोड़ों में रहा। अकेले न्यास की ही करीब एक लाख किताबें बिकीं, जिनकी कीमत करीब 90 लाख रही।

केंद्र सरकार के कामों का श्रेय ले रही आप : लेखी

जासं, नई दिल्ली : भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी (आप) पर झूठ बोलने के साथ ही दूसरे के किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना और दूसरों के अच्छे कामों को अपना बताना ही आप की फितरत है। यही नहीं दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्य कराए, उन्हें भी अपना बताकर आप ने जनता को गुमराह किया।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में लेखी ने कहा कि दिल्ली में जब डेंगू का प्रकोप हुआ तो एमसीडी ने लोगों को डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया। उन्हें जागरूक किया, चालान काटे। दिल्ली सरकार इसका भी श्रेय लेने की होड़ में दिखाई देती रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर किया। केंद्र की भाजपा सरकार ने जब दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल वे बनवाया तो आप ने इसका भी श्रेय लेने की कोशिश की।

3882 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया वर्ष 2018 में। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, इनमें से 2128 विभिन्न अपराधों में शामिल पाए गए। वर्ष 2017 में अपराध में शामिल विदेशियों की संख्या 2242 और वर्ष 2016 में 1,226 थी।

न्यूज गैलरी

आज से संविधान पीठ करेगी सबरीमाला मामले की सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ सोमवार से केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश व मुस्लिम तथा पारसी महिलाओं से भेदभाव के मामलों पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस एसए बोबडे कर रहे हैं। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस एमएम शांतनागौदर, जस्टिस एसए नजीर, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और सूर्य कांत शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के गठन संबंधी नोटिस छह जनवरी को ही जारी किया था। यह पीठ मामलों से संबंधित 60 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने इस विषय में 3:2 से फैसला सुनाया था। इसके बाद नौ सदस्यीय पीठ का गठन किया गया। 28 सितंबर 2018 के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर गौर करते हुए मामले को एक वृहद पीठ को सौंपने का फैसला किया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी थी। (प्रेट्र)

केंद्र ने मंत्रालयों से कर्मचारियों का ब्योरा मांगा

नई दिल्ली : कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी मंत्रालयों से 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का ब्योरा देने को कहा है, ताकि लुटियन दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के तहत इनके लिए स्थान उपलब्ध कराने संबंधी कार्ययोजना तैयार की जा सके। सूत्रों ने बताया कि सचिवों को लिखे पत्र में गौबा ने उनसे जरूरी सूचना एकत्र करने के लिए शीर्ष अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं हो। कैबिनेट सचिव ने पत्र में लिखा है कि सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना के तहत सरकार एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करेगी, जिसमें सभी मंत्रालयों के कार्यालय अवस्थित होंगे। एक अनुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कार्यालयों के किराए के तौर पर सरकार प्रति वर्ष करीब 1000 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों से जरूरतों की सूची, उनके कार्यालयों से जुड़े स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की जानकारी मांगी है। गौबा ने कहा कि इस ब्योरे से शहरी विकास मंत्रालय को स्थान एवं आवास संबंधी कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने अगले महीने प्रत्येक परियोजना के लिए निविदा जारी करने की योजना बनाई है। (प्रेट्र)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर हुआ कोलकाता पोर्ट का नाम

घोषणा ▶ प्रधानमंत्री मोदी ने 150वीं वर्षगांठ पर बदला नाम, आयुष्मान और किसान निधि योजना लागू नहीं करने पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, कोलकाता

दो दिवसीय बंगाल प्रवास के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर करने की घोषणा की।

पोर्ट की 150 वीं वर्षगांठ पर नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पोर्ट के एंथम लांच किया और नेताजी सुभाष ड्राई डाक और मरम्मत केंद्र समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इसके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। आदिवासी बेटियों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास हुआ है। पीएम ने पोर्ट ट्रस्ट से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के लिए 501 करोड़ रुपये का चेक सौंपा और डाक टिकट भी जारी किया।

पीएम ने कहा कि इस वर्ष हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास चल रहा है।

कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में रविवार को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में केपीटी के 105 वर्षीय पूर्व कर्मचारी नगीना भगत को सम्मानित करने के बाद गौर से उनकी बात सुनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण

- बंगाल के दो दिनों के प्रवास पर थे प्रधानमंत्री
- पीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया

मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम, भारत के औद्योगीकरण के प्रणेता, बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश, एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंची ममता : कार्यक्रम में आमंत्रित होने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंचीं। कार्यक्रम में राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। निमंत्रण कार्ड में ममता बनर्जी का नाम भी शामिल था।

कमीशन नहीं मिलता, इसलिए लागू नहीं होती केंद्रीय योजना : प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की योजनाएं यहां पर लागू नहीं की जा रही हैं क्योंकि इन योजनाओं में न तो कट मिल पाता है और न ही कमीशन और सिंडिकेट चल पाता है। मोदी ने तंज कसा कि उन्हें उम्मीद है यहां की भी सरकार आयुष्मान योजना और किसान सम्मान योजना को अपने राज्य में लागू करने की इजाजत दे देगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर नीति निर्धारण करने वाले को सदबुद्धि दें ताकि केंद्र की योजना के लाभ से लोग वंचित न रह सकें।

आंबेडकर के सुझावों पर अमल नहीं किया गया : मोदी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहेब आंबेडकर ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नीतियां दी थीं, नया विजन दिया था। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि उनके के सरकार से हटने के बाद, उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया, जैसा किया जाना चाहिए था।

90 लाख महिलाओं को गैस चूल्हा : केंद्र की योजनाओं को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की 90 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मिला है। इनमें से 35 लाख से ज्यादा महिलाएं दलित और आदिवासी परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में 43000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

100 व 105 वर्ष के दो पूर्व कर्मचारियों को किया सम्मानित : इस दौरान पीएम ने केपीटी के दो पूर्व कर्मचारी नगीना भगत (105 वर्ष) और नरेश चंद्र चक्रवर्ती (100 वर्ष) का सम्मान किया। जब भगत पीएम का पांव छू लिए तो उन्होंने तत्काल उनका हाथ पकड़ लिया और उनके पांव छू लिए।

कांग्रेस ने किया विरोध : बेलूर मठ से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में जाते वक्त कांग्रेस समर्थकों ने पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

स्वामी ने कहा, विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जाए : भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कोलकाता पोर्ट के बाद विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने इसका नाम रानी लक्ष्मी बाई पर रखने का सुझाव दिया है। स्वामी ने कहा कि मैं कोलकाता में नमो के इस कथन का स्वागत करता हूं कि इतिहास की समीक्षा की जानी चाहिए।

मोदी ने युवाओं को दिलाया स्वदेशी का संकल्प, योगी का विपक्ष पर निशाना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अलग-अलग मौकों पर युवाओं को विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नए स्वदेशी अभियान का संकल्प दिलाया। युवाओं को स्वयं की शक्ति पहचानने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही कहा कि आप सभी 2022 तक के लिए ही संकल्प ले लें कि सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे। इससे आप जाने-अनजाने अपने युवा साथियों की मदद कर सकेंगे।

रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में आए युवाओं को प्रधानमंत्री ने डिजिटल संदेश भिजवाया। कहा कि आज ही के दिन देश को स्वामी विवेकानंद के रूप में ऐसी ऊर्जा मिली थी, जिससे हम आज भी ऊर्जावान हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वामी जी कहते थे कि सारी शक्ति आपके अंदर निहित है, आपको स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। 26 हजार नए स्टार्टअप खुलना किसी भी देश के लिए सपना हो सकता है, जो कि भारत में पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 2016 से पहले औसत चार हजार पेटेंट होते थे, जबकि अब 15 हजार से अधिक सालाना हो रहे हैं। यह सब आपकी वजह से हुआ है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया, राम जन्मभूमि का दशकों पुराना विवाद खत्म हो गया। तीन तलाक की कुप्रथा खत्म हो गई। नागरिकता संशोधन कानून एक सच है। अब आप सर्जिकल स्ट्राइक देखते हैं और साथ में एयर स्ट्राइक भी।

इससे पहले पांच दिवसीय राष्ट्रीय युवा उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजिजू ने किया। मुख्यमंत्री ने भारत का यशगान वेद-पुराणों के श्लोकों के साथ किया तो प्रेरणा पुंज महापुरुषों के प्रसंग भी सुनाए। बिना नाम लिए टुकड़े-टुकड़े गैंग, जेएनयू प्रकरण और षड्यंत्रकारी उनके निशाने पर रहे। कहा कि पहले किन्हीं दो देशों में विवाद होता था तो हस्तक्षेप की उम्मीद अमेरिका और रूस जैसे देशों से की जाती थी। आज अमेरिका और ईरान का विवाद निपटाने के लिए भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र से हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लखनऊ में हो रहा युवा महोत्सव अब तक का सबसे भव्य है।

राष्ट्रीय युवा उत्सव

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राष्ट्रीय युवा उत्सव का शुभारंभ
- प्रधानमंत्री ने डिजिटल संदेश के जरिये युवाओं तक पहुंचाई अपनी बात

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

युवा जोश से बदलेगा भारत

प्रथम पृष्ठ से आगे

उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे सौ ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं भारत को बदल दूंगा। यानि परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही आवश्यक है। आज युवाओं को यह मानना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। इसकी सीख हमें स्वामी जी ने दी थी। इसलिए युवा जोश, युवा ऊर्जा ही 21वीं सदी के इस दशक में भारत को बदलने का आधार है।

रामकृष्ण मिशन ने खुद को बताया समावेशी संगठन : बाद में रामकृष्ण मिशन व मठ के महासचिव स्वामी सुविरानंद ने कहा, 'यह संगठन सीएए पर प्रधानमंत्री के भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हम बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है। हम सनातन आह्वानों का जवाब देने के लिए अपना घर छोड़कर यहां आए हैं। हम क्षणिक आह्वानों का जवाब नहीं देते। हम समावेशी संगठन हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के संत हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए नरेंद्र मोदी भारत के नेता हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नेता हैं।'

इंदौर और उज्जैन को काशी से जोड़ेगी निजी ट्रेन

नईदुनिया, इंदौर

- रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ओवरनाइट ट्रेन का एलान

इंदौर और उज्जैन को बाबा विश्वनाथ की धरती काशी (बनारस-उप्र) से जोड़ने के लिए बहुत जल्द निजी ट्रेन चलाई जाएगी। विशेष सुविधाओं वाली इस ओवरनाइट ट्रेन से दो तीर्थनगरियों-उज्जैन व बनारस आने-जाने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी। यह ट्रेन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) चलाएगा। इसी तरह की एक निजी ट्रेन दिल्ली-लखनऊ के बीच चलाई जा रही है। इंदौर-बनारस नई ट्रेन देश में चलने वाली 150 निजी ट्रेनों में शामिल होगी। यह घोषणा रविवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर प्रवास के दौरान की। गोयल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद दिल्ली जाने से पहले मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोशिश यह है कि यह ट्रेन जल्द से जल्द शुरू हो जाए। पर्यटन की दृष्टि से देश-दुनिया के लोग भारत आते हैं। वे उज्जैन भी आना चाहते हैं और देश के सबसे साफ-सुथरे शहर इंदौर को भी देखना चाहते हैं। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर देश की धरोहर और शान होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है जिसे जोड़ते हुए रेलवे नई ट्रेन शुरू कर रहा है। गोयल ने बताया कि उन्होंने रेल अधिकारियों को डिटेल, समय और दिन आदि तय करने को कहा है।

त्योहार शुरू हो रहे हैं, सोचा खुशखबरी दी जाए : रेल मंत्री ने कहा कि इंदौर से उज्जैन होते हुए बनारस तक नई ट्रेन चलाने का फैसला रविवार सुबह ही लिया गया है। लोहड़ी, फिर मकर संक्रांति के साथ अब त्योहारों के दिन शुरू होने वाले हैं। उत्तरायण भी कल है तो मैंने सोचा क्यों न मीडिया के माध्यम से इंदौर और उज्जैन की जनता को यह खुशखबरी दी जाए।

महाशिवरात्रि से चलाने की कोशिश : रतलाम रेल मंडल के प्रबंधक विनीत गुप्ता ने बताया कि इंदौर-बनारस ट्रेन को महाशिवरात्रि से चलाने की कोशिश रहेगी। यह ट्रेन नए कोचों से चलाई जाएगी, लेकिन रैक किस श्रेणी का होगा, अभी तय नहीं है।

'पॉक्सो मामलों के लिए सक्षम वकीलों की जरूरत'

- सुप्रीम कोर्ट ने लोक अभियोजकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया
- इन्हें पता होना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों से सच कैसे सामने लाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत बाल पीड़ितों और गवाहों से सही तरह से बातचीत करने के लिए वकीलों को निश्चित तौर पर प्रशिक्षित होना चाहिए। न्यायालय ने ऐसे मामलों के लोक अभियोजकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बनाने पर भी जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों के लिए अलग से विशेष अभियोजकों की जरूरत है।

जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि लोक अभियोजकों को पता होना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों से सच कैसे सामने लाएं? पॉक्सो मामलों के लिए लोक अभियोजकों को सौंपा गया कार्य बहुत कष्टदायक होता है, जिसपर अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता से काम होना चाहिए। अदालत ने कहा कि न केवल अलग से विशेष लोक अभियोजकों की जरूरत है, बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाने की आवश्यकता है। इन विशेष लोक अभियोजकों को अदालतों में आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। उनके सामने मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे आ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को पॉक्सो मामलों के लिए गठित अदालतों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि राज्य की न्यायिक अकादमी में विशेष कार्यक्रम विकसित किए जाएं। पॉक्सो अदालतों से जुड़े विशेष लोक अभियोजकों को न केवल कानून का प्रशिक्षण मिले, बल्कि बाल मनोविज्ञान, बाल व्यवहार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की भी उन्हें बेहतर जानकारी हो।

लोकपाल के दायरे में नहीं आने वाले मामलों का निपटारा : जस्टिस घोष

कोयंबटूर, प्रेट्र : लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने कहा कि लोकपाल के तहत दायर किए जाने वाले अधिकांश मामलों का निस्तारण इसलिए हो जाता है क्योंकि वह इस दायरे में ही नहीं आते हैं। घोष ने रविवार को कहा कि एक साल पुराने लोकपाल और उसके सदस्यों के पास 1,100 मामले आ चुके हैं। लेकिन जब लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों ने इन पर विचार किया तो पाया कि वह उनके अपने फायदे के लिए सुलझाया गया है।

पिनाकी चंद्र घोष फाइल

घोष ने कहा कि वह अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। लोकपाल का कामकाज नए ऑफिस में जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। यह पूछे जाने पर क्या लोकपाल खुद ब खुद किसी मामले को अपने हाथ में ले सकता है, जैसे कि पुडुचेरी के एक कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उस पर घोष ने कहा कि मामले को अब तक सूत्रबद्ध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोकपाल को लेकर जनता में जागरूकता लाने की जरूरत है। इस काम में मीडिया को भूमिका निभानी चाहिए।

वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए दो सौ और लिड़ाकू विमान खरीदेगा भारत

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1 के लिए अनुबंध इसी साल तय : रक्षा सचिव
- 110 अन्य विमानों के लिए भी जल्द निविदा आमंत्रित करेगी केंद्र सरकार

कोलकाता में कोस्ट गार्ड के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे रक्षा सचिव अजय कुमार। प्रेट्र

रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा है कि वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए जल्द ही 200 नए लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने भारतीय तटरक्षकों (कोस्ट गार्ड्स) के तटीय इलाकों में सामाजिक कार्यों की भी सराहना की।

कोलकाता में कोस्ट गार्ड के निगरानी बोट आइसीजीए अमृत कौर और आसीजीएस एनी बेसेंट के जलावतरण कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा सचिव अजय कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1 के लिए अनुबंध की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 110 अन्य विमानों के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इनट्रेस्ट (ईओआइ) जारी की गई है, जिसके आधार पर जल्द प्रस्ताव के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हल्के लड़ाकू विमान के लिए इस साल अनुबंध पर हस्ताक्षर होना है। हम जितनी जल्दी हो सके, इसे पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि तेजस मार्क 1 विमान के डिजाइन तय हो चुके हैं। अब सरकारी विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) की उत्पादन क्षमता आठ विमान प्रति वर्ष से बढ़ा कर 16 विमान प्रति वर्ष किया जाएगा। जरूरी हुआ तो इसे और बढ़ा जा सकता है।

समुद्री अर्थव्यवस्था बढ़ाने लक्ष्य: रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि भारतीय तटरक्षकों (कोस्ट गार्ड्स) की जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। उन्होंने बताया कि 2024 तक भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था 1750 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी रक्षा का दायित्व जल प्रहरियों पर होगा। इन परिस्थितियों में कोस्ट गार्ड्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि समुद्र में भारत की 7500 किमी लंबी जलसीमा से जुड़े 20 लाख वर्ग किमी विस्तृत समुद्री आर्थिक क्षेत्र है। जल प्रहरियों को मजबूत करने के साथ ही हम जहाज निर्माण में लगातार आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अधिकतर पानी के जहाज 70 फीसद तक स्वदेशी और अत्याधुनिक जहाज 90 फीसद तक स्वदेशी तकनीक से लैस हैं।

भारतीय कोस्ट गार्ड्स के महानिदेशक के नटराजन ने कहा कि मुंबई हमले के बाद तटीय इलाकों में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। हमारे पास 145 निगरानी जहाज हैं। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। कोस्ट गार्ड्स के पास पहले से ही 62 निगरानी निगरानी विमान हैं, साथ ही 16 नए अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर और बेड़े में शामिल किए जाएंगे।

दिल्ली के द्वारका का डिप्लोमेटिक एनक्लेव प्रोजेक्ट अटका

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया है कि दिल्ली के द्वारका स्थित 'डिप्लोमेटिक एनक्लेव' प्रोजेक्ट का निर्माण अटक गया है। चूंकि यहां की भूमि अधिग्रहण का मामला पिछले तीन सालों से कोर्ट में लंबित है।

संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने बताया है कि उसे विभिन्न दूतावासों से नए 'डिप्लोमेटिक एनक्लेव' में भूमि आवंटित किए जाने के आवेदन मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विगत 4 जनवरी, 2017 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 34.87 हेक्टेयर जमीन नगरीय विकास मंत्रालय के प्रस्तावित द्वारका सेक्टर-24 में नया 'डिप्लोमेटिक एनक्लेव' बनाने के लिए दी है।

हालांकि मौजूदा समय में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पहले से ही एक 'डिप्लोमेटिक एनक्लेव' स्थित है। नया 'डिप्लोमेटिक एनक्लेव' द्वारका में बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है। इसमें विभिन्न कूटनीतिक अभियानों के दफ्तरों की इमारतें, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों की इमारतें बनाई जानी हैं।

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है। इसलिए अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए 'डिप्लोमेटिक एनक्लेव' के विस्तार की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने समिति को बताया कि भारत उन देशों में भी अपने नए मिशन स्थापित कर रहा है जहां अब तक उसके रेजिडेंट मिशन नहीं थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अफ्रीका के 18 मिशन को वर्ष 2018 से 21 के बीच स्थापित करने का फैसला लिया था। इसमें से नौ देशों में भारतीय मिशन स्थापित किया जाएगा। इनमें रिपब्लिक ऑफ गुएना, एक्वोटोरियल गुएना, बुर्किना फासो, रवांडा, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया और कैमेरून आदि हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

द्विपक्षीय संबंध

भारत-अमेरिका के रिश्तों में कश्मीर का पेंच

उप विदेश मंत्री ने यात्रा की शुरुआत से पहले ट्वीट कर जाहिर की अपनी मंशा, नई दिल्ली के बाद जाना है पाकिस्तान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अगले हफ्ते अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेल्स भारत आएंगी
- अमेरिका ने कश्मीर से सारे प्रतिबंध हटाने की रखी है मांग

भारत व अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में वैसे तो हर तरह से सुधार हो रहा है लेकिन कश्मीर का पेंच इसमें फंसा हुआ है। ऐसे में अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आने वाली अमेरिका की प्रमुख उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय की होने वाली बैठक में कश्मीर का मुद्दा निश्चित तौर पर उठने वाला है। खुद वेल्स ने यात्रा की शुरुआत से पहले ट्वीट कर अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने हाल ही में भारत सरकार की तरफ से कुछ विदेशी राजनयिकों को कश्मीर ले जाने का स्वागत तो किया लेकिन यह बताने से कोई संकोच नहीं किया कि वहां सरकार के लगाए सारे प्रतिबंधों को भी हटाया जाना चाहिए। वेल्स अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण व केंद्रीय एशिया विभाग की प्रमुख हैं।

अगर 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद-370 हटाने के भारत के फैसले के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया देखें तो वह लगभग भारत का समर्थन करने वाली ही रही है। लेकिन इधर बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कई बार कश्मीर के हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। भारत पिछले हफ्ते जिन विदेशी राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर ले गया था, उनमें अमेरिकी राजदूत सबसे अहम थे। उसके बाद ही वेल्स ने कश्मीर को लेकर ताजी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि हम अमेरिकी राजदूत व अन्य राजनयिकों के कश्मीर दौर पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इसे अहम कदम करार देते हुए लिखा, 'हम कश्मीर में राजनेताओं व निवासियों के बंदी बनाए जाने और इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को लेकर चिंतित भी हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही वहां सामान्य स्थिति बहाल होगी।'

भारत में वेल्स के इस बयान को इसलिए महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वह सोमवार को ही दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा पर आ रही हैं। वह श्रीलंका, भारत और फिर पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगी। वह नई दिल्ली में 15-18 जनवरी तक होने वाले रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह व्यापार जगत के लोगों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली से अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेल्स पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी।

कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक वेल्स की भारतीय विदेश मंत्रालय में होने वाली बातचीत में व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों पर बात होगी लेकिन निश्चित तौर पर कश्मीर का मसला भी उठेगा। लेकिन भारत की उत्सुकता नई दिल्ली में वेल्स के बयान से ज्यादा पाकिस्तान में उनके बयान को लेकर होगी। यह हाल के महीनों में किसी अमेरिकी मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी।

पाकिस्तान सरकार और सेना निश्चित तौर पर वेल्स के साथ होने वाली बातचीत में कश्मीर का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत एक बार फिर अमेरिका के लिए बढ़ गई है। यह देखना होगा कि अमेरिका कश्मीर पर पाकिस्तान को खुश करने वाली कोई बात तो नहीं कहता है।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (MAINS)
से कक्षा प्रारम्भ... 20 JAN 2020 11:30 AM 2:00 PM
GS (प्रारम्भिक परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (PT) 20 JAN 2020 6:15 PM 8:15 PM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
D-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58

2017 व 2018 की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु वाली सिर्फ 10.6 फीसद भारतीय आबादी ही स्नातक की शिक्षा पूरी कर पाई। ग्रामीण भारत में यह आंकड़ा 5.7 फीसदी, तो शहरी इलाकों में 8.3 फीसदी था। इसी वर्ग समूह में 2011 में यह आंकड़ा 8.2 फीसद था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 13 जनवरी 2020

आने से पहले ही मरांडी से तार जोड़ने में जुटे भाजपाई

सियासत ▸ बाबूलाल के औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले हड़कंप

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) प्रमुख बाबूलाल मरांडी भले ही भाजपा में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन संगठन में जमे और प्रभावी नेताओं ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश तेज कर दी है। ये नेता मरांडी के करीबियों से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। पार्टी में हाशिये पर चल रहे नेता भी अपनी बातें बाबूलाल कैंप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दलील है कि उन्हें लंबे अर्से तक उपेक्षित रखा गया। अगर मौका मिला तो वे बेहतर परिणाम दे सकेंगे।

तेजी से होने वाले बदलाव की आहट ने पुराने भाजपाइयों को इस कदर सक्रिय कर दिया है कि वे किसी तरह बाबूलाल मरांडी के गुड बुक में आने को बेकरार हैं। इसमें कई ऐसे नेता भी हैं, जो मरांडी के साथ शुरुआती दिनों में भाजपा छोड़कर गए थे, लेकिन बाद में वापसी कर ली थी। ऐसे लोग भी पुराने संबंधों की दुहाई देते नहीं थक रहे हैं।

चुना जाना है विधायक दल का नेता : विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद से झारखंड में भाजपा पस्त है। अभी तक

बाबूलाल मरांडी। फाइल

विधायक दल की एक भी औपचारिक बैठक नहीं हो पाई है। विधायक दल का नेता भी चुना जाना बाकी है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अब बदले परिप्रेक्ष्य में नए नेता का चयन होगा। ऐसे में इसमें और देरी लगेगी। इस प्रकरण से उन नेताओं को झटका लगा है, जो खुद को इस दौड़ में आगे बता रहे थे। इन नेताओं ने फिलहाल चुप्पी साध ली है और आने वाले दिनों में होने वाली गतिविधियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

नए प्रदेश अध्यक्ष की भी होगी ताजपोशी : विधानसभा चुनाव में हार के बाद झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने इस्तीफा दे दिया था। गिलुवा खुद भी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले मोदी लहर के बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। गिलुवा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है।

फिर दिल्ली गए हेमंत, यूपीए की बैठक में होंगे शामिल

राब्यू, रांची : प्रधानमंत्री से मिलकर लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर नई दिल्ली रवाना हो गए। वह सोमवार को यूपीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे और यूपीए के दलों की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। सोरेन वहां मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 16-17 जनवरी तक उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में झामुमो से पांच और कांग्रेस से तीन विधायकों को शामिल किया जाना है। इससे पहले 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस कोटे से विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जल्द ही कांग्रेस भी अपने मंत्रियों की सूची फाइनल करेगी।

शिवसेना के 56 में से 35 विधायक असंतुष्ट : राणे

ठाणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना के 56 में से 35 विधायक पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। हालांकि, भाजपा व राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच गठबंधन के मुद्दे पर टिप्पणी से इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर भाजपा ही बात करेगी।

एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार रात यहां मीडिया से बात करते हुए राणे ने कहा कि राज्य सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता में भाजपा की वापसी का भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा के 105 विधायक हैं, जबकि शिवसेना के सिर्फ 56 हैं और उनमें से भी 35 विधायक असंतुष्ट हैं। ठाकरे सरकार ने किसान कर्जमाफी की घोषणा की है। वह भी खोखली साबित हो रही है, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि इस वादे का कब क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने गत गुरुवार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि वह बिना किसी योजना या क्षेत्र के लिए राशि की घोषणा के ही वापस लौट गए। राणे ने कहा, 'हम ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वे सरकार चलाना नहीं जानते। उन्हें सरकार बनाने में ही पांच सप्ताह से ज्यादा लग गए। इससे जाहिर होता है कि वे सरकार किस तरह चलाएंगे।' उल्लेखनीय है कि कभी शिवसेना और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राणे ने गत वर्ष 15 अक्टूबर को अपनी पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष का भाजपा में विलय कर दिया था।

पंजाब में महंगी बिजली पर श्वेत पत्र लाने की तैयारी में कांग्रेस सरकार

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- अकाली दल व आप के मोर्चा खोलने के बाद बढ़ी सरकार की चिंता
- अगले चुनाव में बाजी फिसलने का डर, पार्टी नेताओं में भी बढ़ रहा गुस्सा
- सुप्रीम कोर्ट में केस हारने का ठीकरा भी कांग्रेस सरकार पर ही फोड़ा गया

महंगी बिजली की आग अब तेजी से राज्य में फैलने लगी है। विपक्षी दल लोगों के बढ़ते गुस्से को भुनाने के लिए जहां मैदान में उतर आए हैं वहीं, कांग्रेस सरकार ने खुद ही इस मुद्दे को विधानसभा में ले जाने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि 16 जनवरी को शुरू होने वाले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान यह मुद्दा उठ सकता है। सरकार सदन में श्वेत पत्र ला सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि महंगी बिजली के पीछे कारण क्या है।

अकाली दल द्वारा महंगी बिजली के मुद्दे पर मोर्चा खोलने से कांग्रेस सरकार घिर गई है। तीन साल तक शांत रहने वाली सरकार अब विधानसभा में इसका जवाब देने की रणनीति अपना रही है। शिअद-भाजपा सरकार के दौरान भले ही निजी थर्मल प्लांटों की वजह से लोगों पर महंगी बिजली का बोझ पड़ा हो, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी बिजली दरें कम करने के लिए करीब तीन वर्षों में कोई भी प्रयास नहीं किए। इसके विपरीत कोयले की ढुलाई का केस सुप्रीम कोर्ट में हारने का ठीकरा भी कांग्रेस सरकार पर ही फोड़ा गया है। कांग्रेस नेताओं में भी महंगी बिजली को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है और पार्टी को डर है कि कहीं बाजी फिसल न जाए।

आम आदमी पार्टी द्वारा शुक्रवार को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने के बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई है। उसे पता है कि बिजली एक मात्र ऐसा मुद्दा है जो राज्य के 96 लाख घरों से सीधे जुड़ा है। अगर जल्द ही इस पर सरकार आक्रामक न हुई तो यह मुद्दा बड़े आंदोलन में बदल सकता है जिसका सीधा असर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर पड़ सकता है।

शिअद 15 को मिलेगा राज्यपाल से : दूसरी तरफ अकाली दल ने सरकार को घेरते हुए 15 जनवरी को इस संबंध में राज्यपाल को मांग पत्र सौंपने का फैसला लिया है। उसकी मांग है कि इस बात की जांच हो कि कोयले की धुलाई के मामले में रेगुलेटरी अथॉरिटी में दो बार केस जीतने के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार कैसे हार गई?

जाखड़ तैयार कर रहे हैं रूपरेखा : कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ विपक्ष में रहते हुए एक मात्र ऐसे नेता थे जो सरकार को इस मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर घेरते रहते थे, लेकिन इस समय वह खुद को अलग रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि महंगी बिजली के मुद्दे पर वह कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। राज्य में अपनी सरकार होने के कारण वह यह लड़ाई इस तरह से लड़ना चाहते हैं कि सरकार को नुकसान भी न हो और पूर्व की बादल सरकार को घेरा भी जा सके।

2017 में सरकार लाई थी श्वेत पत्र

अगर कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र लाती है तो तीन साल में यह दूसरा मौका होगा। इससे पहले 2017 में कांग्रेस सरकार वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र लाई थी।

कैबिनेट बैठक में उठा था मुद्दा

दरअसल पार्टी के अंदर से भी सरकार पर बिजली दरें कम करने का खासा दबाव बन रहा है। नौ जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। मंत्रियों का कहना था कि जनता पर बढ़ते महंगी बिजली के बोझ से चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मंत्रियों ने सुझाव दिया था कि प्राइवेट बिजली कंपनियां अदालती लड़ाई लड़कर करोड़ों रुपये ले रही हैं तो क्या सरकार अदालती में नहीं लड़ सकती? कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से एडवोकेट जनरल पंजाब और अन्य सीनियर अधिकारियों की कमेटी बनाकर इस पर कोई कदम उठाने की बात की। मुख्यमंत्री जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे।

न्यूज गैलरी

आजम के बेटे अब्दुल्ला के मामले में कार्रवाई के आदेश

रामपुर : हाई कोर्ट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद किए जाने के मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिव को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने नवेद मियां को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 17 दिसंबर को नवेद मियां ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र भेजकर अब्दुल्ला पर दस साल के लिए प्रतिबंध लगाने, वेतन-भत्तों और सुविधाओं पर व्यय की वसूली और विधायक निधि की रिकवरी किए जाने की मांग की थी। (जासं)

छग में एक दिवसीय विस सत्र का भाजपा ने किया विरोध

रायपुर : भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने 16 जनवरी को बुलाए गए एक दिवसीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का विरोध किया है। भाजपा विधायकों का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपरा से अलग कार्य कर रही है, जो अनुचित है। विशेष सत्र के दिन कृतज्ञता प्रस्ताव का अनुमोदन और 126वें सविधान संशोधन को पारित होना है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बताया कि भाजपा विधायकों की आपत्ति इस बात पर है कि संसदीय इतिहास में एक दिन में ही ऐसा नहीं हुआ है। संशोधन देना विपक्ष का अधिकार है, ऐसे में उसी दिन संशोधन होना, सचिवालय द्वारा चेक करना और संशोधन प्रिंट होने के बाद सदस्यों में वितरण होता है। इसके बाद संशोधन प्रस्ताव और अभिभाषण पर चर्चा होती है, लेकिन एक दिन के सत्र में यह संभव नहीं है। (नईदुनिया)

रामकृष्ण मठ से मोदी ने की सियासत : अधीर

कोलकाता : लोकसभा में नेता विपक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बेलूर मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकता संशोधन कानून को ले की गई टिप्पणी पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मठ से सियासी टिप्पणी कर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। भाजपा हमेशा आम लोगों को आंदोलित करने को इस तरह की हरकतें किया करती है और मोदी ने भी यही काम किया है। रामकृष्ण मिशन एक अध्यात्म स्थल है यहां लोग शांति को जाते हैं, न कि सियासी टिका-टिप्पणी को। (जासं)

जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 15 को

राज्य ब्यूरो, जम्मू : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई है। चुनाव पंद्रह जनवरी को होगा। 14 जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। पांच बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। 15 जनवरी को पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में सुबह 11 बजे चुनाव होगा। चुनाव प्रभारी वीरेंद्रजीत सिंह ने कहा कि अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव सुचारू रूप से करवाने के लिए प्रबंध किए गए है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार रविंद्र रैना का फिर से सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय है। प्रधान का कार्यकाल तीन साल का होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जिला प्रधानों, पूर्व जिला प्रधानों, वार्ड प्रधानों से 15 जनवरी को सुबह 11 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पार्टी के नेताओं, संघ के नेताओं की राय ली गई थी। गत दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बैठक हुई।

घाघरा का नाम बदल कर सरयू करने की तैयारी, कैबिनेट में लग सकती मुहर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए हो सकता फैसला

योगी सरकार घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू करने की पक्षधर है। इसके लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। सरकार के इस कदम को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जोड़कर देखा जा रहा है। गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से एक घाघरा को अयोध्या में सरयू कहा जाता है।

फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का प्रयागराज करने के बाद योगी सरकार अब घाघरा नदी का नामकरण सरयू करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी इस मंशा का इजहार कर चुके हैं। अब सरकार के इस इरादे को औपचारिकता का जामा पहनाते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। गौरतलब है कि तिब्बत में हिमालय की उच्च पर्वतमाला से निकलने वाली घाघरा अपने उद्गम क्षेत्र में

योगी आदित्यनाथ। फाइल

करनाली के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यह नेपाल से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उप्र में दक्षिण-पूर्व दिशा में बहते हुए यह बिहार में छपरा के पास गंगा में समाहित हो जाती है। चूंकि यह अंतरराज्यीय नदी है, इसके लिए इसका नाम केंद्र सरकार ही बदल सकती है।

पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर उसे मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के नाम से संचालित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था। नए नामकरण के साथ शुरू की जाने वाली इस योजना का लाभ किसान और उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ ही बटाईदार को भी मिलेगा। इस योजना में बीमा कंपनियों का हस्तक्षेप खत्म कर उसे जिलाधिकारियों की देखरेख में संचालित करने का इरादा है।

वहीं कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था में नए बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर तैनात करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों जैसे अधिकार मिल जाएंगे।

मुजफ्फरनगर दंगे के चार और मुकदमे वापस लेगी उप्र सरकार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े चार और मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार 76 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के न्याय विभाग ने जिला प्रशासन से दंगों से जुड़े मुकदमों के संबंध में 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई।

सात सितंबर 2013 को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव नगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत के बाद जनपद में सांप्रदायिक दंगा फैल गया था। दंगे में 60 से अधिक लोगों की जान गई थी और 40 हजार से अधिक लोग पलायन कर गए थे। जिसके बाद थाना सिखेड़ा, फुगाना, व शाहपुर में हजारों लोगों के विरुद्ध सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने खाप चौधरियों के साथ मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर फर्जी मुकदमों की वापसी कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के न्याय विभाग ने जिला प्रशासन से मुकदमों के संबंध में 13 बिंदुओं पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। जिला प्रशासन ने सभी मामलों की रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी थी। जिसके बाद प्रदेश शासन ने 76 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। जिला प्रशासन की ओर से सभी मामलों का परीक्षण कर उन्हें अभियोजन विभाग को भेज दिया था। जिनमें से कुछ मुकदमों की वापसी के लिए कोर्ट में आवेदन किया गया था। इसी दौरान प्रदेश शासन ने दंगे से जुड़े चार और मुकदमों को वापस लेने की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन को इस संबंध में पत्र लिखा है। उक्त मुकदमों को वापस लेने के लिए संबंधित कोर्ट में आवेदन करने को कहा गया है। इन मुकदमों में भोराकलां थाना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 155ई/2013 राज्य बनाम सन्नी आदि, फुगाना थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 332/2013 राज्य बनाम राकी उर्फ डान तथा मुकदमा अपराध संख्या 484/2013 तथा मुकदमा अपराध संख्या 297/2013 शामिल हैं।

छग में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए फोन पर ली जा रही राय

नईदुनिया, रायपुर

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अब पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फोन पर राय मांगी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की गई है। इससे पहले प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव करना है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एक दौर की चर्चा कर चुके हैं। अब अध्यक्ष का नाम फाइनल करने से पहले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की राय जानी जा रही है।

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो केंद्रीय संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है। अब तक सांसदों, विधायकों और आला पदाधिकारियों से राय ले ली गई है। इसके साथ ही सीएए पर चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश खन्ना और महेश गिरी ने वन टू वन पदाधिकारियों से चर्चा की। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों ने अपनी राय संगठन के आला नेताओं के सामने रख भी दी है। अब जातिगत समीकरण के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव करना है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए आदिवासी या ओबीसी वर्ग के किसी नेता को चुना जा सकता है। केंद्रीय संगठन की पसंद सांसद विजय बघेल और संतोष पांडेय हैं। बघेल ओबीसी हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं। वहीं, आदिवासी नेताओं की ओर से अब तक एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है।

15 दिसंबर तक चुन लेना था प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा संगठन चुनाव की शुरुआत 11 सितंबर से हुई। 11 से 30 सितंबर तक बूथ कमेटी, 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मंडल और 11 नवंबर से 30 नवंबर तक जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ। अभी प्रदेश के 11 जिलों में जिलाध्यक्षों का चुनाव नहीं हो पाया है। 15 दिसंबर तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी कर लेना था, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कारण देर हो गई।

राजद में घमासान, रघुवंश ने जगदानंद की कार्यप्रणाली पर फिर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना

राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की कार्यशैली पर वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद के सवालों के बाद पार्टी बेदम है। किंतु रघुवंश के तेवर में थोड़ी भी नरमी नहीं आई है। दूसरे दिन भी अपने स्टैंड पर अड़े रहे। कहा, उन्होंने संगठन के हित में पत्र लिखा है। सुधार नहीं होगा तो आगे भी लिखेंगे।

रघुवंश के पत्र के जवाब में सबसे पहली प्रतिक्रिया जगदानंद की आई। पत्र को तरजीह नहीं देते हुए संक्षेप में उन्होंने जवाब दिया कि राजद बड़ी पार्टी है और ऐसे पत्र आते रहते हैं। उन्होंने इसे राजद का अंदरुनी मामला करार दिया। हालांकि रघुवंश सिंह ने दूसरे दिन भी हमला जारी रखा। एक दिन पहले के स्टैंड को ही आगे बढ़ाते हुए कहा कि जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मालिक नहीं हैं। मैंने पत्र में कोई गलत बात नहीं लिखी। पार्टी और संगठन है, तो हम हैं। मैं जयकारा टीम का सदस्य नहीं हो सकता। रघुवंश ने यह भी दावा किया कि

रघुवंश प्रसाद। फाइल

उनकी सलाह पर लालू प्रसाद जरूर अमल करेंगे।

दो वरिष्ठ नेताओं की भिड़ंत से पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति है। लालू प्रसाद को पत्र लिखकर रघुवंश ने जो मुद्दे उठाए हैं, उसे न खारिज करते बन रहा है, न स्वीकार करते। अंदर हलचल है। किंतु बाहर सामान्य बताने की कोशिश है। कुछ रघुवंश का समर्थन कर रहे तो कुछ प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में खड़े हैं। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।

रघुवंश के समर्थन में शिवानंद : रघुवंश के समर्थन में वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी खुलकर आ गए हैं। ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने पार्टी में संवादहीनता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यकीनन संवादहीनता है। तभी तो रघुवंश बाबू को पत्र लिखकर अपनी बात रखनी पड़ी। हालांकि शिवानंद ने यह भी कहा कि रघुवंश बाबू की चिट्ठी में कुछ भी गलत नहीं है। पत्र में राजद के हित के बारे में ही लिखा गया है। जगदानंद के अनुशासन पर सवाल उठाते हुए शिवानंद ने कहा कि अनुशासन के नाम पर इतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए कि पार्टी के अंदर का लोकतंत्र ही खत्म हो जाए। शिवानंद दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच विचारधारा का फर्क भी मानते हैं। यह भी जोड़ते हैं कि दोनों लालू प्रसाद के मजबूत स्तंभ हैं। साथ बैठेंगे तो कटुता खत्म हो जाएगी। उन्होंने सलाह दी कि दोनों बात करके मामला सुलझा लें या रांची जाकर राजद प्रमुख के सामने बैठ जाएं तो दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा।

कांग्रेस विधायक ने कहा, गाय को छूने से दूर होती है नकारात्मकता

मुंबई, प्रेट्र : अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली महाराष्ट्र की मंत्री और कांग्रेस विधायक यशोमति ठाकुर ने अब कहा है कि गाय को छूने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। इससे पहले यशोमति ठाकुर ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अभी पैसा कमाना शुरू नहीं किया है। वह टियोसा से विधायक हैं और कांग्रेस कोटे से उद्धव सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अमरावती में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति कहती है कि अगर आप गाय को छुएंगे, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। यशोमति ठाकुर ने रविवार को पीटीआइ से कहा, 'गाय पवित्र जानवर है। इसके अतिरिक्त, चाहें गाय हो या कोई अन्य जानवर, उनको छूने से हमारे अंदर प्रेम का भाव पैदा होता है। मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है?' इससे पहले वाशिम जिला परिषद चुनावों के प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि हम बस अभी पावर में आए हैं, अभी हमारी जेबें गर्म नहीं हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता चाहें तो विपक्ष से पैसा ले सकते हैं, लेकिन वोट कांग्रेस को ही दें।

हालात

2017 में जहां तेजाब हमले के 244 मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्ष 2018 में इनकी संख्या मामूली गिरावट के साथ 228 रही, बंगाल में सामने आए सबसे ज्यादा मामले

पिछले साल तेजाब हमले के मामलों में आई कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2018 के दौरान देश भर में तेजाब हमले के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2017 में जहां तेजाब हमले के 244 मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्ष 2018 में इनकी संख्या मामूली गिरावट के साथ 228 रही।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में तेजाब हमले के सबसे ज्यादा 36 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश (32) व तेलंगाना (10) का नंबर है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के 44 मामलों के मुकाबले वर्ष 2018 में कमी आई है।

उल्लेखनीय है कि तेजाब हमले के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए जुर्माने के साथ सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। यौन अपराधों पर संशोधित कानून के साथ ऐसे मामलों में सजा के प्रावधान वाला एक अलग कानून भी पारित किया गया है।

रोजाना 109 बच्चे हुए यौन शोषण के शिकार

गत वर्ष देश के रोजाना 109 बच्चे यौन शोषण के शिकार हुए। ऐसे में मामलों में पिछले साल के मुकाबले 22 फीसद का उछाल आया है।

एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (पॉक्सो) के तहत 32,608 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 39,827 रही। गत वर्ष 21,605 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ितों में 21,401 बालिकाओं केस साथ-साथ 204 बालक भी शामिल रहे। महाराष्ट्र में बच्चों से दुष्कर्म के सबसे ज्यादा 2,832 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश (2,023) व तमिलनाडु (1,457) क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2008-18 के बीच बच्चों के साथ समग्र अपराध के मामले छह गुना बढ़ गए हैं।

वर्ष 2008 में जहां 22,500 मामले दर्ज हुए, वहीं वर्ष 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 1,41,764 हो गई। क्राइम राइट एंड यू (सीआरवाई) की निदेशक (पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी) प्रीति मेहरा का मानना है कि एक तरफ ये आंकड़े जहां खतरनाक स्थितियों को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्था के प्रति लोगों में बढ़ते विश्वास का भी संकेत देते हैं।

22 फीसद की बढ़ोतरी हुई है बच्चों से यौन शोषण के मामलों में पिछले साल के मुकाबलों में

दोषियों को बचाने के लिए कहानी पलट रही सीबीआइ : तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो हफ्ते की चुप्पी के बाद रविवार को राज्य सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने सीबीआइ पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की कहानी पलटने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा भाजपा के मंत्रियों को बचाने के लिए किया गया है। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 29 दिसंबर को शिरकत करने के बाद तेजस्वी का यह पहला बयान है। कहा कि दुष्कर्म पीड़ित 34 बच्चियों ने बताया था कि उनकी कुछ साथियों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव वहीं उसी परिसर में गाड़ दिए गए थे। खोदने पर उनके कंकाल भी मिले, किंतु दोषियों को बचाने के लिए अब सीबीआइ कहानी पलट रही है। कहा कि अदालत ने जांच अधिकारी के ट्रांसफर के लिए मना किया था। किंतु सीबीआइ ने अफसर को बदल दिया।

एससी-एसटी आरक्षण के लिए बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र

जासं, पटना

▸ विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और विधान परिषद की दोपहर ढाई बजे से

अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) को अगले दस साल तक आरक्षण का लाभ देने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए सोमवार को बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और विधान परिषद की दोपहर ढाई बजे से।

राजकीय संकल्प के रूप में संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार दोनों सदनों में संविधान के 126वें संशोधन विधेयक के समर्थन का प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे, जिसपर चर्चा के बाद सदस्य अपनी सहमति प्रदान करेंगे। विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के प्रारंभिक संबोधन से कार्यवाही की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के बाद सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे।

बता दें कि संसद के दोनों सदनों से 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। इस विधेयक को 25 जनवरी 2020 से प्रभावी होना है।

संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत आधे से अधिक राज्यों की विधायिका द्वारा इसे पास कराना जरूरी है। अगर पास नहीं कराया गया तो विधानसभा चुनाव में एससी-एसटी आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में एससी-एसटी के लिए स्

2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बेंगलुरु में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता वरुण पर हमला करने के मामले में। पुलिस के मुताबिक दोनों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है।

'अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे'

बोले शाह ▸ ह्यूमन राइट चैंपियनों को पाक के अत्याचार नहीं दिखते

जबलपुर की सभा में सीएए पर केंद्रीय गृहमंत्री की दो टूक

नईदुनिया, जबलपुर

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। वह कितना भी विरोध कर ले, हम भारत में बसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। भारत पर जितना हक मेरा-आपका है, उतना ही उन शरणार्थियों का है। वे भारत के बेटे हैं। ह्यूमन राइट के चैंपियनों को पाकिस्तान में दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और प्रताड़ित हो रहे लाखों-करोड़ों लोग दिखाई नहीं देते। वह रविवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित गैरीसन ग्रांउड में सभा को संबोधित कर रहे थे।

गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विरोध करने के बजाए देश की नब्ज समझे। जनता की इच्छा जाने, वरना जितने है-उतने भी नहीं बचेंगे। अनुसूचित जाति, सिंधी, जैन, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में कांग्रेस और ममता को क्या समस्या है? भाजपा वोट बैंक की नहीं, देश हित की राजनीति करती है।

नेहरू-गांधी की भी नहीं सुनते राहुल : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि वह महात्मा गांधी की भी नहीं मानते। 12 जुलाई 1947 को गांधीजी ने कहा था कि जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं, वे भारत के नागरिक हैं। वे जब आना चाहें, उनका स्वागत है। राहुल गांधी अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी की भी नहीं सुनते, जिन्होंने शरणार्थियों को अपनाने की बात कही थी।

कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल फैला रहे भ्रम : शाह ने कहा कि सीएए को लेकर जनजागरण इसलिए करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस, राहुल बाबा एंड कंपनी, कम्युनिस्ट, केजरीवाल और ममता बनर्जी यह भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में लिखा था कि जो हिंदू, सिख पाक से आए हैं, उन्हें नागरिकता देंगे।

जबलपुर में सभा को संबोधित करते गृह मंत्री अमित शाह। नईदुनिया

जो देश विरोधी नारा लगाएगा, उसकी जगह जेल में

गृहमंत्री ने कहा कि जेएनयू में कुछ लड़के भारत विरोधी नारे लगाते हैं, राहुल बाबा और केजरीवाल उन्हें बचा रहे हैं। जो देश विरोधी नारा लगाएगा, उनकी जगह जेल की सलाखें होंगी।

मैडम के सामने सीआर सुधारने में जुटे कमलनाथ

मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रदेश में सीएए लागू नहीं करने की घोषणा पर शाह ने कहा कि वह दिल्ली में मैडम (सोनिया गांधी) के सामने सीआर (गोपनीय चरित्रावली) सुधारना चाहते हैं, इसलिए जोर से बोलते हैं। कहा कि कमलनाथजी, आपकी जोर से बोलने की आयु नहीं है, सेहत बिगड़ सकती है।

सिंधी परिवार को 56 साल बाद मिली भारत की नागरिकता

नईदुनिया, जबलपुर

1964 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आकर मध्य प्रदेश के बालाघाट में रह रहे गोपाल दास प्रियानी के परिवार को अब वीसा की अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन नहीं देना पड़ेगा। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालाघाट में प्रियानी सहित पांच लोगों को मंच से भारत की नागरिकता देने की घोषणा की।

प्रियानी के परिवार के पाकिस्तान से आने के बाद 1991 में श्रीचंद गुरुनानी का परिवार आया। इसके बाद पाकिस्तान से आने वाले सिंधी परिवारों की संख्या बढ़ती गई और 2019 में कुल 47 सदस्य हो गए। इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। वे वीसा की अवधि बढ़वाकर बालाघाट में रह रहे हैं। हाल में उन्होंने एक बार फिर गृह मंत्रालय को आवेदन देकर वीसा अवधि 2024 तक बढ़वा ली थी। सीएए लागू होने के बाद इन परिवारों को भी भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद बंधी। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास किए और आखिरकार रविवार को जबलपुर में आयोजित अमित शाह की सभा में उन्हें भारतीय होने का अधिकार मिल गया। नागरिकता मिलने के बाद सिंधी परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। सिंधी परिवार ने कहा कि वे सालों से अपने ही देश में परायों की तरह रह रहे थे। वीसा के आधार पर उन्हें यहां रहने और गुजर-बसर करने का अवसर तो मिल रहा था, लेकिन देश के नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, उनसे वे वंचित रहे। अब ऐसा नहीं होगा।

पाकिस्तान से आकर बालाघाट में बसे सिंधी समाज के इन्हीं लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में एक कार्यक्रम में नागरिकता देने की घोषणा की। नईदुनिया

इन्हें मिली नागरिकता

नाम	भारत आने का वर्ष
राजकुमार खत्री	1991
श्रीचंद गुरुनानी	1991
गोपालदास प्रियानी	1964
अजीत नागदेव	2011
करमचंद नागदेव	2011

कई सदस्य अभी भी पाकिस्तान में : बालाघाट के इन परिवारों के कई सदस्य अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही हैं और दोयम दर्जे की जीने को मजबूर हैं। 2011 में पाकिस्तान से आकर बालाघाट में रह रहे करमचंद नागदेव ने कहा कि वहां अन्याय होने के बाद भी वे आवाज नहीं उठा सकते। व्यापार की भी उतनी छूट नहीं है। बंदूक के दम पर लूट लिया जाता है। भारत आने से लोग सिर्फ इसलिए हिचकते रहे थे कि उन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिलती थी। अब कानून में संशोधन हो गया है। ऐसे कई परिवार हैं, जो अपने देश लौट सकेंगे।

कुछ लोगों को चिढ़ है हिंदू शब्द से : वेंकैया

चेन्नई, आइएएनएस : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही चिढ़ है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का बेजा विरोध किया जा रहा है। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए है।

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुत्व के प्रति कुछ लोगों का रवैया यद्यपि सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी महसूस करते हैं कि उन्हें अपना नजरिया रखने का अधिकार है। सेक्युलरिज्म का मतलब अन्य धर्मों को अपमानित करना नहीं है। सेक्युलर संस्कृति तो भारतीय मूल्यों का हिस्सा है।

नायडू ने कहा, भारत ने दमन और उत्पीड़न का शिकार रहे लोगों को हमेशा आश्रय उपलब्ध कराया है। स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने हिंदुत्व का परिचय पश्चिमी जगत से कराया। खुद विवेकानंद ने कहा था कि वह एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसने तमाम देशों के शरणार्थियों को अपने बीच जगह दी।

'बंगाल को भी लागू करना होगा नागरिकता संशोधन कानून'

हैदराबाद में रविवार को हुनर हाट के उद्घाटन के मौके पर ड्रम बजाते अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (बाएं से दूसरे)। प्रेट्र

हैदराबाद, एजेंसियां : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बंगाल भी भारत का हिस्सा है। इसलिए, उसे देश की संसद से पारित सीएए को लागू करना ही होगा। कानून के क्रियान्वयन पर सरकार अटल है और इसे कतई वापस नहीं लिया जाएगा। कुछ लोग 'सुपारी' लेकर देश में भ्रम और 'हॉरर शो' जैसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं।

इतिहास पढ़ें, संविधान की जानकारी हासिल करें ममता बनर्जी : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी ने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा, 'संसद से पारित किसी भी कानून को सभी राज्यों को स्वीकार करना चाहिए। बंगाल भी देश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतिहास पढ़ना चाहिए और भारतीय संविधान के बारे में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए।' सीएए वापस लिए जाने संबंधी केरल विधानसभा के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह असंवैधानिक और असंभव है कि संसद से पारित किसी कानून का कोई राज्य उल्लंघन करे।' उन्होंने कहा, 'सीएए के जरिये उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिनका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया गया है। इससे किसी की नागरिकता कतई नहीं छीनी जाएगी।'

भ्रम फैलाने वाले देश व अल्पसंख्यकों के दुश्मन : केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि सीएए को लेकर जो लोग समाज के किसी वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं वे देश और समाज की एकता तथा सौहार्द के दुश्मन हैं। ऐसे लोग अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के दुश्मन हैं। कुछ राजनीतिक दल एक साजिश के तहत भ्रम फैला रहे हैं।' नकवी ने कहा, 'भारत में मुसलमान मजबूती के साथ रह रहा है, न कि मजबूरी के साथ। मैं भारतीय मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व संवैधानिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे सुरक्षित जगह है।'

संसद में सीएए का समर्थन करने वाले अब क्यों कर रहे विरोध : नकवी ने कहा, 'जिन्होंने संसद में सीसीए का समर्थन किया वह भी अब विरोध कर रहे हैं। इससे साफ है कि इसके जरिये समाज के एक वर्ग विशेष को भ्रमित करने के लिए 'हॉरर शो' की स्थिति पैदा की जा रही है।' उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 600 से अधिक मुसलमानों व अन्य धर्मावलंबी विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। आगे भी नियमानुसार यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

युवा व छात्र देशद्रोही नहीं, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है

सीएए के विरोध के सवाल पर नकवी ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे देश के युवा व छात्र देशद्रोही नहीं हैं... वे अराजक भी नहीं हैं। उन्हें कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए भ्रमित कर रहे हैं।

प्रख्यात हस्तियों ने पूछा क्या संविधान महज प्रशासनिक नियमावली

नई दिल्ली, एजेंसियां : पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ.एसवाई कुरैशी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे.चेलमेश्वर समेत आठ प्रख्यात हस्तियों ने एक खुला पत्र लिखा है। इसमें भारत के गणतंत्र की 70वीं वर्षगांठ पर नागरिकों से अपील की है कि संविधान को केवल प्रशासनिक दस्तावेज न समझें और भविष्य में उसका आत्मविश्लेषण और समीक्षा करें। वह डॉ.भीमराव अंबेडकर के संविधान के लक्ष्यों को पूरा करें।

इन हस्तियों ने रविवार को जनता से पूछा है कि क्या संविधान महज प्रशासनिक नियमावली है। जिससे निर्वाचित सरकार को सत्ता का दुरुपयोग करने की छूट मिल जाती है। क्या यह साधारण लेखन है जिसे स्याही से लिखा गया है? या फिर यह पवित्र ग्रंथ है जिसे अनगिनत शहीदों के खून से लिखा गया है।

इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, प्राचीनता और भाषा की सीमाओं को खत्म किया गया है? इन हस्तियों ने जनता से यह अपील ऐसे समय में की है जब नए नागरिकता कानून के विरोध में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून के आलोचकों का कहना है कि यह धर्म के आधार पर किया गया भेदभाव है जो संविधान का उल्लंघन है।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में उतरे लोग

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए भाजपा व अन्य संगठनों ने रविवार को भी जगह-जगह प्रदर्शन किए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में रैलियां और सभाएं की गईं। झारखंड के गिरिडीह में निकली तिरंगा यात्रा पर पथराव के बाद मची भगदड़ में एक पुलिसकर्मी समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं।

गिरिडीह के मौलाना आजाद चौक के पास पथराव की इस घटना के बाद दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देर तक बवाल होता रहा। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर अश्रुगैस के गोले दागे। बड़ी मुश्किल से पुलिस-प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाया। उपद्रव और तनाव को देखते हुए पूरे शहर में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। शहर में बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं व कासगंज, बागपत, शामली के बाद मुजफ्फरनगर में भी सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। अलीगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। बसपा पर कुछ नरमी बरती। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की कब्र खोदने की बात करने वाले एएमयू छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रम एवं सन्निर्माण समिति के अध्यक्ष ठा. रघुराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की कब्र खोदने वाले को वो जिंदा दफन कर देंगे। 10 के बदले 20 मारेंगे।

भारत सुरक्षा मंच के आहान पर मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित रैली में हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा था। सशर्त अनुमति के कारण नेताओं के भाषण नहीं कराए गए। मंच पर धर्मगुरुओं के साथ सेना के सेवानिवृत्त अफसर, सेवानिवृत्त जज, डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार, खिलाड़ियों को जगह मिली थी। मुस्लिम महिलाओं का एक समूह भी समर्थन में पहुंचा था। राज्य के मंदसौर, मुरैना और नीमच में भी सीएए के समर्थन में आयोजन हुए। पंजाब में जगह-जगह भाजपा व अन्य संगठनों ने कानून के समर्थन में मार्च और तिरंगा यात्राएं निकालीं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अफगानिस्तान से 70 हजार सिख यहां पर आकर बसे हैं, जिनके पास देश की नागरिकता नहीं है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि यह सिख फिर से वापस अफगानिस्तान चले जाएं?

नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग से सीएए के समर्थन में मार्च निकालती सांसद मीनाक्षी लेखी (बीच में तिरंगे के रंग की पगड़ी पहने) व भाजपा कार्यकर्ता। जागरण

शाहीन बाग में 28वें दिन टूटा सब्र का बांध, निकाली पदयात्रा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में शाहीन बाग में चल रहे धरने से परेशान लोगों के सब्र का बांध 28वें दिन टूट गया। रविवार सुबह 11 बजे के आसपास लगभग दो दर्जन कॉलोनियों के लोग सरिता विहार जल बोर्ड कार्यालय के बाहर जमा हो गए। पदयात्रा आगे बढ़ी तो संख्या देख पुलिस के हाथ-पांव फूल गए।

मालूम हो कि कालिंदी कुंज-सरिता विहार रोड जाम किए जाने से दिल्ली, उप्र और हरियाणा के हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस इलाके के ज्यादातर बच्चे नोएडा में पढ़ते हैं। एक माह से उनका स्कूल जाना बंद है। रविवार को लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। लोगों के सरिता विहार जल बोर्ड से आगे बढ़ते ही पहली बैरिकेड पर दक्षिणी-पूर्वी जिले एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश सहित कई अधिकारियों ने समझाया, लेकिन लोग नहीं माने और बैरिकेडिंग हटाकर डीसीपी ऑफिस की तरफ बढ़ गए। 'दिल्ली पुलिस रोड खुलवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारे लगाते लोग आगे बढ़े तो सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया। भीड़ का गुस्सा देख डीसीपी चिन्मय बिश्वाल खुद पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि रोड खुलवाने को लेकर लगातार शाहीन बाग के लोगों से बात कर रहे हैं। सोमवार को फिर बातचीत होनी है। पुलिस एक तरफ से रोड खुलवाने का पूरा प्रयास करेगी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। कहना था कि 27 दिन तक रोड खुलने का इंतजार किया, अब कोई आश्वासन नहीं चाहिए। डीसीपी के देर तक समझाने के बाद लोगों ने पदयात्रा तो खत्म कर दी, लेकिन आक्रोश कम नहीं हुआ और लोग मथुरा रोड को जाम करने पहुंच गए।

पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़ा : मथुरा रोड पर पहुंचकर लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। समझाने पर नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इससे गुस्साए लोगों ने मदनपुर खादर गांव और मदनपुर खादर एक्स्टेंशन को जोड़ने वाले पुल पर जाकर रास्ता जाम कर दिया। यहां भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

इन कॉलोनियों के लोग हुए शामिल : पदयात्रा में खिजराबाद, तैमूर नगर, सराय जुलैना, भरत नगर, जसोला, मदनपुर खादर, आली गांव, आली विस्तार, बदरपुर, जैतपुर, मीठापुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी, गौतमपुरी, मोलड़बंद, मोहन एस्टेट, तुगलकाबाद, तेहखंड गांव, हरि नगर, ओम विहार आदि गांवों व आसपास की कॉलोनियों के लोग शामिल हुए।

नई दिल्ली में कालिंदी कुंज मार्ग खुलवाने के लिए सरिता विहार में बैरिकेडिंग तोड़ कर मथुरा रोड पर जाने का प्रयास करते प्रदर्शनकारी। विपिन शर्मा

करीब एक महीने से रोड बंद है जिससे स्कूल बसें आना बंद हैं। इलाके के जो बच्चे नोएडा के स्कूलों में पढ़ते हैं उनका स्कूल जाना बंद है। अब बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक आ रहीं हैं। इसलिए हमें मजबूर होकर रोड खुलवाने के लिए सड़क पर आना पड़ा।

– राजेंद्र अवाना, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ सरिता विहार आरडब्ल्यूए

मदनपुर खादर से अधिकांश लोग मजदूरी के लिए वसंत कुंज, नेहरू प्लेस, साकेत सहित दिल्ली के अन्य इलाकों में जाते हैं। रोड बंद होने से ये लोग समय से न काम पर पहुंच पा रहे हैं और न ही घर आ पा रहे हैं।

– अशोक बिधूड़ी, अध्यक्ष आरडब्ल्यूए मदनपुर खादर।

विवाद

सीएए के खिलाफ केरल विधानसभा के प्रस्ताव को करना होगा खारिज, केंद्रीय कानून का पालन करना राज्यों का कर्तव्य

राजनीतिक दांवपेच में उलझा संवैधानिक अधिकार

माला दीक्षित, नई दिल्ली

राजनीतिक दांवपेच में केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का कई राज्य खुलेआम विरोध कर रहे हैं। इस राजनीतिक खींचतान में संविधान के तार भी उलझ रहे हैं। हालांकि सीएए समेत दूसरे केंद्रीय कानून को मानना राज्यों का कर्तव्य है और इसका पालन न करना संवैधानिक तंत्र का फेल होना माना जाएगा। लेकिन इसी संविधान के अनुसार अब यह भी जरूरी हो गया है कि अदालत केरल के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देकर खारिज करे।

सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह का साफ मानना है कि केंद्रीय कानून को लागू करने से राज्य सरकारें मना नहीं कर सकतीं। लेकिन केरल के मामले में संवैधानिक अधिकारों का बहुत घालमेल हो गया है। विधानसभा के प्रस्ताव पारित करने के मायने अलग हो जाते हैं। जबतक कि अदालत से उसे असंवैधानिक न घोषित किया जाए तब तक कानून की निगाह में वह प्रस्ताव कानूनी ही माना जाएगा।

इस मामले में केरल विधानसभा के प्रस्ताव को केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी होगी और वहां बताना होगा कि राज्य विधानसभा को ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है इसलिए उसे रद किया जाए। इसके अलावा राज्यसभा अगर केरल विधानसभा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित करती है तो भी दूसरा पक्ष कोर्ट जा सकता है।

जहां तक एनपीआर की बात है तो संविधान के जानकार कहते हैं कि राज्य एनपीआर लागू करने से मना नहीं कर सकते।

इतना ही नहीं एनपीआर लागू न करने वाले राज्य के निवासी इसे लागू कराने के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं।

केरल पहला राज्य है जिसने सीएए के खिलाफ सदन से प्रस्ताव पारित किया है। इतना ही नहीं उसने हाल ही में सीएए के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन भी दिया है जिसको वहीं के राज्यपाल और जानेमाने कानूनविद आरिफ मोहम्मद खान ने अवांछनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि संसद के कानून के खिलाफ सरकारी विज्ञापन हैरान करने वाला है। दूसरी बानगी पश्चिम बंगाल की है जहां राज्य में सीएए के खिलाफ लगे सरकारी पोस्टरों और विज्ञापनों को हटाने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था।

सीएए, एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तीनों ही चीजें नागरिकता और जनसंख्या गणना से जुड़ी हैं। संविधान के मुताबिक इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और दोनों ही केंद्रीय कानून हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एसआर सिंह कहते हैं कि नागरिकता संविधान में केंद्रीय सूची का विषय है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से राज्य आखिर कैसे मना कर सकते हैं।

ऐसा करना राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना माना जाएगा और इस आधार पर राज्य की सरकारें बर्खास्त हो सकती हैं। एनपीआर के मुद्दे पर भी उनका कहना है कि यह जनगणना से जुड़ा मुद्दा है। इस बारे में केंद्रीय कानून है और राज्य उसे लागू करने से मना नहीं कर सकते। अगर राज्य ऐसा करते हैं तो केंद्र उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एनपीआर के प्रश्न तय करना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है।

जस्टिस सिंह कहते हैं कि वैसे तो उन्हें नहीं मालूम कि एनपीआर में क्या प्रश्नावली तय की गई है लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न व्यक्ति के माता पिता और उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है तो उसमें गलत क्या है। यह भारत देश के नागरिकों की जनगणना हो रही है ऐसे में पता होना चाहिए कि व्यक्ति इस देश का नागरिक है या विदेशी घुसपैठिया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) न लागू होने पर नागरिकों के अधिकारों पर जस्टिस एसआर सिंह और वकील ज्ञानंत सिंह दोनों का मत है कि इससे प्रभावित होने वाले नागरिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राज्य के लोग योजनाओं में विशिष्ट लाभ से वंचित रहने की आशंका जताते हुए एनपीआर लागू करने की मांग कर सकते हैं।

संसद से पास कानून के खिलाफ धारणा बनाना गलत : आरिफ

वडोदरा, एजेंसियां : केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने रविवार को यहां कहा कि संसद से पास कानून के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर एक धारणा बनाना अनुचित है। सीएए के खिलाफ केरल सरकार द्वारा अखबारों में दिए गए विज्ञापनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह बात कही।

आरिफ मुहम्मद ने कहा कि सीएए के खिलाफ अभियान को आगे नहीं ले जाया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'मैं अपनी संवैधानिक व्यवस्था में यकीन करता हूं। केंद्र और राज्य के बीच किसी तरह के झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। देश की प्रगति के लिए संतुलन आवश्यक है।' उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अगस्त, 1947 में, जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को और राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि विभाजन के चलते जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, अगर उन्हें वहां बराबर का अधिकार नहीं मिलता है तो उन्हें लौटने का पूरा हक है। इस नैतिक जिम्मेदारी को सीएए के जरिए कानूनी रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित होने वाले लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में हैं, केरल में नहीं। केरल में कोई विदेशी नागरिक नहीं रहता है।

वहीं, नागपुर में रविवार को सीएए के खिलाफ आयोजित रैली में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उसे लागू करने का काम राज्य सरकारों का है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। इस कानून को लागू किया जाएगा या नहीं इसका फैसला राज्य सरकार को करना है। रैली में मौजूद राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। बता दें कि सीएए को 10 जनवरी से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

1.5 लाख लोगों की मौत हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है, जबकि 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल देश के जीडीपी को दो फीसदी का नुकसान होता है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 13 जनवरी 2020

मुठभेड़ में हिजबुल के तीन आतंकी ढेर

कार्रवाई ▸ त्राल से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद, तलाशी अभियान जारी

मुठभेड़स्थल पर राष्ट्र विरोधी तत्वों ने सुरक्षाबलों के जवानों पर किया पथराव

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कश्मीर में सुरक्षाबलों ने पुलवामा के त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के तीन कुख्यात आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। वहीं, मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों के मौजूद होने की आशंका पर पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इसके अलावा मुठभेड़स्थल पर किसी को भी नहीं जाने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह सुरक्षाबलों को त्राल के गुलशनपोरा क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दस्ते ने गांव को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों को देख उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ कई घंटे तक चली। दोपहर दो बजे गोलीबारी बंद हुई तो सुरक्षाबलों ने सतर्कता बरतते हुए मुठभेड़स्थल की तलाशी ली। इस दौरान यहां अलग-अलग जगहों पर आतंकियों के शव पड़े थे। इनकी पहचान सीर गांव के उमर फियाज लोन उर्फ हमाद खान, मोंगहामा के आदिल बशीर मीर उर्फ अबु दुजाना और फैजान हमीद के रूप में हुई है। मुठभेड़स्थल से सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान काफी संख्या में शरारती तत्व इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे थे। ताकि सुरक्षाबलों का ध्यान भटके और आतंकी बचकर निकल सकें। हालांकि पुलिस की चेतावनी के बावजूद शरारती तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर कार्रवाई कर सभी को मुठभेड़स्थल से तितर-बितर कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार लोन साल 2016 से ही सक्रिय था। वह कई वारदातों में संलिप्त रहा है। त्राल के पुलिस कर्मी हलीम कोहली और आम नागरिक मेहराज दीन जरगर की हत्या करने में भी लोन का हाथ रहा था। पुलिस स्टेशन त्राल में 17 और दो एफआइआर अवंतीपोरा में दर्ज हैं। आदिल बशीर 24 अप्रैल 2018 से और फैजान हमीद निवासी मंडूरा 17 अप्रैल 2019 से सक्रिय थे। इन दोनों के खिलाफ भी आतंकी घटनाओं के कई मामले दर्ज हैं।

शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इसी ठिकाने को रविवार को ध्वस्त कर दिया। एएनआइ

शोपियां में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त

दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है। गांव उरपोरा में आतंकवादियों ने एक बाग में ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस को आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

पाकिस्तान सेना ने हीरानगर और पुंछ में दागे गोले

संवाद सहयोगी हीरानगर : पाकिस्तान रेंजरों ने शनिवार की रात को भी संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी की। पाकिस्तानी रेंजरों ने करोल कृष्णा, करोल माथरियां, चक चंगा गांवों को निशाना बनाते हुए छोटे हथियारों और मोर्टार के गोले दागे। गोले गांवों के बाहर खेतों में फटे। बीएसएफ ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रविवार की सुबह चौकी प्रभारी चकडा नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी से प्रभावित गांवों में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी शामिल हुए।

पुंछ में रातभर दागे गोले : पाकिस्तान पिछले तीन दिन से लगातार पुंछ के खड़ी करमाड़ा, देगवार कोसलिया, मालटी इलाकों में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के अलावा रिहायशी क्षेत्रों में पाक सेना ने मोर्टार शेल के साथ तोप के गोले भी दागे। शनिवार मध्य रात से रविवार तड़के तक गोलाबारी चलती रही। नियंत्रण रेखा के नजदीकी भारतीय गांवों में दहशत का माहौल रहा। गोलाबारी की आवाज पुंछ नगर तक साफ सुनाई दे रही थी। भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। किसी प्रकार के जानी नुकसान की जानकारी नहीं हुई।

कोर्ट के आदेश पर कोच्चि की चारों अवैध बहुमंजिला इमारतें चुटकी में ढेर

▸ केरल सरकार ने उच्च सतर्कता से दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंजाम

▸ मराडु स्थित इमारतें गिराने के लिए 750 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल

कोच्चि, प्रेट्र : पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समुद्र किनारे आखिरी दो अवैध बहुमंजिला इमारतों को नियंत्रित तरीके से विस्फोट करके कुछ ही सेकेंड में ढहा दिया गया। रविवार को इसी के साथ अवैध रिहायशी इमारतों को गिराने की मुहिम पूरी हो गई।

केरल के तटीय शहर कोच्चि के मलाडु स्थित समुद्र तट पर बनाई गई कई आलीशान रिहायशी इमारतों को गिराने की यह अपने आप में अनूठी प्रक्रिया थी। 350 फ्लैट वाली चार हाईराइज इमारतों को गिराने की मुहिम पिछले दो दिनों से जारी थी। कंक्रीट की इन इमारतों को बम विस्फोट करके गिराया गया लेकिन इससे आसपास की अन्य इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

महीनों में बनाई गए महंगी इमारतें कुछ ही सेकेंड में मलबे का ढेर बन गईं। ढहाई गई 55 मीटर ऊंची इमारत 'गोल्डन कायोलरम' चारों इमारतों में सबसे नीची थी। इससे पहले रविवार को दिन में 'जैन कोरल कोव' को ढहाया गया। शनिवार को दो इमारतें 'एच2ओ होली फेथ' और 'एल्फा सेरीना' के ट्विन टावर को गिराया गया था।

इर्नाकुलम जिला कलेक्टर एस.सुहास और कोच्चि पुलिस कमिश्नर विजय सखारे ने कहा कि अवैध इमारतें गिराने की मुहिम सफल रही। मराडु में सुनियोजित तरीके से अपनाई गई प्रक्रिया में करीब 750 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। आठ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नार्म का उल्लंघन करने वाली इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। केरल सरकार ने 138 दिनों की समयसीमा का पालन करते हुए कड़ी सुरक्षा और एहतियात के साथ इस काम को अंजाम दिया। एहतियातन धारा 144 लगाकर सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक शनिवार और रविवार को 200 मीटर के दायरे को खाली करा लिया गया था। इसके बावजूद पास ही स्थित आंगनवाड़ी की खिड़कियों का कांच तक नहीं चटका।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने प्रदर्शनकर रहे फ्लैट मालिकों से इमारत खाली करवा ली थी। इन फ्लैट मालिकों का कहना था कि यह फ्लैट खरीदने में अपनी खून-पसीने की कमाई लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन फ्लैट मालिकों को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। इमारतें गिराए जाने से एक दिन पहले एक फ्लैट मालिक ने कहा था कि सरकार का अपने नागरिकों के प्रति यह अन्याय है। इन हालात के लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार है।

केरल के कोच्चि में मलाडु समुद्र तट के समीप पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करके बनाए गए जैन कोरल कोव अपार्टमेंट को विस्फोटकों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। प्रेट्र

न्यूज गैलरी

एक लाख का इनामी नक्सली पकड़ा गया

दंतेवाड़ा : किरंदुल थाना क्षेत्र के आलनार पटेलपारा गांव से एक लाख रपये का इनामी नक्सली देवा मुचाकी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार वह नक्सल संगठन में जनमिलिशिया कमांडर है। उसे किरंदुल थाना बल और डीआरजी के जवानों ने सर्चिंग के दौरान सटीक मुखबिरी पर पकड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुमियापाल-अलनार इलाके के सरपंच की हत्या में शामिल रहा है। (नईदुनिया)

छऊ कलाकारों को ले जा रहे वाहन में टक्कर, दो की मौत

सांकतोड़िया (आसनसोल) : विवेक उत्सव में भाग लेने सारबेड़िया से जा रहे छऊ नृत्य कलाकारों के वाहन में रघुनाथपुर के पास एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में दो कलाकारों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए। बताया गया कि रविवार को पुरुलिया जिले के पाड़ा थाना क्षेत्र के सारबेड़िया से छऊ नृत्य कलाकारों को लेकर वाहन 407 रघुनाथपुर में होने वाले उत्सव में जा रहा था। रघुनाथपुर के करीब पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में तपन महतो (50) और निखिल महतो (45) की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। अनाड़ा फांडी की पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को रघुनाथपुर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मरने वाले दोनों कलाकार पाड़ा थाना क्षेत्र के सुरुलिया गांव के रहने वाले थे। (जासं)

महाराष्ट्र को तीन-चार हिस्सों में बांटा जा सकता है : वैद्य

नागपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक एमजी वैद्य ने कहा है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार महाराष्ट्र को तीन से चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए वैद्य ने यह बात कही। आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता वैद्य ने कहा, 'मेरी राय है कि यदि महाराष्ट्र की आबादी करीब 11-12 करोड़ है, तो इसे तीन से चार हिस्सों में बांटा जा सकता है।' उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.2 करोड़ है। (प्रेट्र)

पतियों ने ही रची थी अपनी पत्नियों की हत्या की साजिश

जयपुर दोहरा हत्याकांड

▸ दोनों आरोपित अपनी पत्नियों की हत्या कर करना चाहते थे दूसरी शादी

जागरण संवाददाता, जयपुर

जयपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। दो पतियों ने मिलकर अपनी पत्नियों की हत्या की साजिश रची और इसमें एक दूसरे का सहयोग करने का वादा भी किया था। आरोपितों का नाम रोहित तिवारी और सौरभ है। सौरभ रोहित की पत्नी व बेटे को ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया लेकिन रोहित शर्त के हिसाब से सौरभ की पत्नी की हत्या करता, इससे पहले ही मामले का पर्दाफाश हो गया। जयपुर के पुलिस उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में हरि सिंह नामक एक व्यक्ति को रविवार दोपहर गिरफ्तार किया गया है। हरि सिंह सौरभ का जीजा है।

इसके साथ ही पुलिस को रोहित तिवारी की मृतक पत्नी श्वेता के मोबाइल की सिम भी मिल गई। श्वेता की हत्या कर उसका मोबाइल अपने साथ ले गए सौरभ ने इस सिम को अपने पास ही रखा था। पूछताछ में रोहित व सौरभ ने माना कि दोनों की ही अपनी पत्नियों से अनबन चल रही थी। दोनों अपने परिवार की हर बात एक-दूसरे से शेयर करते थे। दोनों अपनी पत्नियों को मारने के बाद दूसरी शादी करना चाहते थे। रोहित दिल्ली का रहने वाला है जबकि श्वेता का मायका कानपुर में है।

यह है मामला

सात जनवरी को जयपुर के जगतपुरा इलाके में स्थित यूनिक टॉवर में रोहित तिवारी की पत्नी श्वेता की हत्या कर उसके 21 माह के बेटे श्रेयम का अपहरण कर लिया गया था। तीन दिन तक 150 पुलिसकर्मियों ने जांच कर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता रोहित तिवारी ही निकला। रोहित से हुई पूछताछ के बाद उसके परिचित सौरभ को पकड़ा गया। सौरभ ने श्वेता और श्रेयम की हत्या की थी।

माघ मेले में तय हो जाएगी राममंदिर निर्माण की तिथि

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा इस माघ मेला में तय हो जाएगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। माघ मेला में लगे विहिप के शिविर में 20 जनवरी को केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक होगी। उसमें राम मंदिर के निर्माण की तिथि और ट्रस्ट से जुड़े मामले पर फैसला होगा। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देशभर के संत महात्मा शामिल हो सकते हैं। मंथन के बाद अगले दिन इसकी घोषणा होगी।

माघ मेला क्षेत्र में विहिप के शिविर में अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। इस मॉडल का अनावरण रविवार को विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस मॉडल को 1989 में कुंभ के दौरान प्रयाग में रखा गया था, उसी मॉडल का यह स्वरूप है। इसी मॉडल के आधार पर भव्य मंदिर का निर्माण होना है। उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पत्थर 20 वर्ष से तराशे जा रहे हैं। यहां पर रखे गए मॉडल का निर्माण सीतापुर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने तैयार किया है। मेले तक यहां आने वाले श्रद्धालु इसका दीदार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसी मेले में 20 जनवरी को केंद्रीय मार्ग दर्शक मंडल की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, साध्वी ऋतंभरा, बाबा रामदेव सहित देशभर के संत महात्मा शामिल होंगे। बैठक में ही राम मंदिर निर्माण की तिथि तय की जाएगी। मंदिर के ट्रस्ट की रूपरेखा भी तय होगी कि उसमें किसे शामिल किया जाएगा। 21 जनवरी को संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। उसमें मंदिर पर हुए निर्णय को सार्वजनिक किया जाएगा।

अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल प्रयागराज में चल रहे माघ मेला के दौरान आकर्षण का सबब बन चला है। रविवार को परेड ग्राउंड स्थित विश्व हिंदू परिषद के शिविर में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल का अनावरण किया गया। इसके बाद इसे सभी के दर्शनार्थ खोल दिया गया। जागरण

चैत्र प्रतिपदा से हनुमान जयंती तक गांव-गांव में होंगे राम महोत्सव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : माघ मेला में विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत की दो दिवसीय बैठक में आगे की रूपरेखा तय की गई। रविवार को बैठक के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि संगठन की स्थापना जिन उद्देश्यों से हुई, उसकी प्राप्ति के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए 490 वर्ष से चल रही लड़ाई का समापन हुआ है। अब राम मंदिर बन सकेगा और हिंदुओं को गर्व की अनुभूति होगी। कहा कि इस राष्ट्र की आध्यात्मिक सत्ता को पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। हमारी कामना सबके सुख की है, इसी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। संगठन के नेटवर्क के बल पर जिन गांव में राम शिला का पूजन हुआ था, उन गांव में हम चैत्र वर्ष प्रतिपदा से हनुमान जयंती तक बड़े-बड़े राम महोत्सव के कार्यक्रम करेंगे।

बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में 24 की गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, पटना

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से रविवार को राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने व वायरल होने की अफवाह दिनभर उड़ती रही। हालांकि परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने पर परीक्षार्थियों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा में राज्यभर के 6.50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। जबकि इस परीक्षा के लिए 12.65 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राज्यभर में 550 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 24 मुन्नाभाई गिरफ्तार किए गए। 20 जनवरी को अब दूसरे चरण की परीक्षा होगी। केंद्रीय चयन पर्षद के ओएसडी केके प्रसाद ने बताया कि विभिन्न जिलों से 24 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।

प्रश्न पत्र लीक होने की परीक्षा केंद्रों पर उड़ती रही अफवाह : परीक्षा को लेकर सुबह से ही प्रश्न पत्र वायरल होने की चर्चा से गहमागहमी की स्थिति रही। परीक्षार्थी तथा अभिभावक दिनभर परेशान रहे। लेकिन परीक्षा हॉल से निकलने के बाद परीक्षार्थियों ने वायरल प्रश्न पत्र को फर्जी बताते हुए महज अफवाह बताया।

वायरल नहीं हुआ प्रश्न पत्र : केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के ओएसडी केके प्रसाद ने बताया कि कहीं से कोई प्रश्न पत्र लीक या वायरल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि 24 सेट में प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। अगर किसी केंद्र पर कोई केंद्राधीक्षक पेपर आउट करने की कोशिश भी करें, तब भी हेराफेरी आसान नहीं है।

बिहार के सुलतानगंज थाना में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए छह लोग। जागरण

ब्लूटूथ से कर रहा था नकल, कान के अंदर घुसा यंत्र

जासं, मुजफ्फरपुर : मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जिला स्कूल केंद्र से ब्लूटूथ से नकल कर रहे एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान पटना के दुल्हिन बाजार इलाके के धनंजय कुमार के रूप में हुई है। परीक्षा के क्रम में धनंजय की गतिविधि पर वीक्षक को संदेह हुआ। वीक्षक की नजर उसके कान में लगे ब्लूटूथ पर पड़ी। उससे पूछताछ की जाने लगी। पकड़े जाने के डर से धनंजय ने ब्लूटूथ को छिपाने के क्रम में उसे कान के काफी अंदर घुसा लिया। इसके बाद वह दर्द से कराहने लगा। वीक्षक ने फौरन इसकी सूचना मजिस्ट्रेट व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके कान के अंदर से ब्लूटूथ को निकालने के लिए सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन प्रारंभिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति देख श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

तेजस ने विमान वाहक पोत से सफलतापूर्वक उड़ान भरी

▸ तेजस ने शनिवार को आइएनएस विक्रमादित्य पर पहली बार की थी लैंडिंग

▸ विमानवाही पोत से संचालित होने वाले विमान बनाने वाले देशों में भारत भी शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण ने रविवार को विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य के 'स्की-जंप' डेक से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह इस विमान के विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

स्की-जंप विमानवाहक पोत के डेक पर हलका घुमावदार अग्र छोर होता है जो लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त लिफ्ट प्रदान करता है।

नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, 'तेजस के नौसैनिक संस्करण ने आइएनएस विक्रमादित्य से सफलतापूर्वक पहला स्की-जंप टेकऑफ कर आज एक और मील का पत्थर हासिल किया।'

विमान ने शनिवार को आइएनएस विक्रमादित्य पर पहली बार लैंडिंग की थी, वह भी एक अहम कदम था। विमानवाहक पोत पर विमान की सफल लैंडिंग और टेकऑफ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो ऐसे लड़ाकू विमानों की डिजाइन में सक्षम हैं जिनका संचालन विमानवाही पोत से किया जा सकता है।

तेजस के नौसैनिक संस्करण का विकास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्रॉफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टीफिकेशन और सीएसआईआर समेत कई दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया है।

फाइल

अनूठी मिसाल

नेयाज सहेज रहे गुरु ग्रंथ साहिब के दुर्लभ अंग, 17वीं सदी में लिखा गया है पवित्र ग्रंथ का स्वरूप

इस्लाम का मुरीद यूनुस बना श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मुहाफिज

विनय कोछड़, बटाला (गुरदासपुर)

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जयपुर जिले के बगरू निवासी डॉ. फिरोज खान के सहायक प्रोफेसर पद पर चयन को लेकर जहां बीते समय में हंगामा बरपा हुआ था, वहीं पंजाब में सर्वधर्म सद्भाव की एक अनूठी कहानी लिखी जा रही है। भारत-पाकिस्तान की सीमा से सटे गुरदासपुर जिले के ऐतिहासिक कस्बे बटाला में 17वीं सदी में लिखे गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दुर्लभ स्वरूप के अंगों को इस्लाम धर्म के उपासक मोहम्मद नेयाज यूनुस सहेज रहे हैं। यूनुस भारतीय पुराततत्व सर्वेक्षण में आर्ट रिस्टोरर रह चुके हैं। वह इस कार्य में चार साल से लगे हैं। 60 फीसद काम हो चुका है। सभी अंगों को सहेजने में चार साल और लगेंगे। बटाला के उमरपुरा में बाबा अजीत सिंह के आवास पर स्थित श्री सच्चखंड में दुर्लभ स्वरूप को सहेजने का काम चल रहा है। यूनुस रोज आठ घंटे इस काम में जुटे रहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दुर्लभ स्वरूप खराब हो चुके थे। कुछ पेज तो पाउडर की तरह हो गए थे। इन स्वरूपों को पहले तो प्राकृतिक पदार्थों के द्रव्य और पानी से स्नान करवाया गया। स्वरूप के अंग इतने पुराने हो चुके हैं कि इनका एक-एक शब्द दोबारा जोड़ना पड़ रहा है। यूनुस का कहना है कि जिस लिपि का श्री गुरु ग्रंथ साहिब के इस स्वरूप में इस्तेमाल किया गया है, वह 17वीं सदी में लिखी जाती रही है।

1.30 करोड़ आया अब तक खर्च, जर्मनी से मंगवाया पेपर : श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सहेजने पर अब तक एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। यह खर्च जत्थेदार अजीत सिंह (यूके वाले) और नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट बटाला उठा रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग भी इस काम में उनकी वित्तीय मदद कर रहे हैं। स्वरूप में लिखे शब्दों को दोबारा पिरोने के लिए पेपर जर्मनी से मंगवाया गया है।

मोहम्मद नेयाज यूनुस, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दुर्लभ स्वरूप को संभाल रहे हैं। जागरण

▸ चार साल में 60 फीसद काम हुआ पूरा, चार साल और लगेंगे

▸ हाथ लगाने पर झड़ने लगते हैं स्वरूप के अंग, सहेजना पड़ रहा एक-एक शब्द

जांच के लिए राष्ट्रपति भवन से भी आए अधिकारी

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दुर्लभ स्वरूप की जांच के लिए राष्ट्रपति भवन से भी अधिकारी आ चुके हैं। टीम के सदस्य डॉ. एसपी सिंह भी इस काम की सराहना कर चुके हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और एसजीपीसी के पदाधिकारी भी बटाला आकर यूनुस का काम देख चुके हैं।

श्री अकाल तख्त साहिब ने दी थी स्वरूप को सहेजने की अनुमति

जत्थेदार अजीत सिंह (यूके वाले) को वर्ष 2015 में दिल्ली के एक सिंधी परिवार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का यह दुर्लभ स्वरूप सौंपा था। स्वरूप को सहेजने के लिए उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब से संपर्क किया। यहां पांच जत्थेदारों ने उन्हें इन दुर्लभ स्वरूपों को सहेजने की अनुमति दे दी।

पवित्र ग्रंथ के स्वरूप को सहेजना मेरे लिए सौभाग्य की बात

नेयाज युनूस का कहना है कि जत्थेदार अजीत सिंह ने उनके सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दुर्लभ स्वरूप को सहेजने का प्रस्ताव रखा। पवित्र ग्रंथ के दुर्लभ स्वरूप को सहेजना मेरे लिए सौभाग्य है। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। स्वरूप के अंगों को हाथ लगाने पर झड़ जाते हैं। शब्दों को फिर से उसी क्रम में सही से लगाना बहुत मुश्किल है।

बिहार का हत्यारोपित रॉ अफसर बन पुलिस को दे रहा था झांसा

पुणे, प्रेट्र : बिहार के औरंगाबाद निवासी हत्यारोपित को महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में गिरफ्तार कर लिया। वह खुद को खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का अधिकारी बताते हुए पुलिस अधिकारियों को झांसा देने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपित सोनू सूरज तिवारी की गिरफ्तारी शनिवार को पुणे के कोंढवा थाना पुलिस ने की। उन्होंने बताया, 'आरोपित सोनू शनिवार को कोंढवा थाने के आसपास घूम रहा था। पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की तो अपना नाम अखंड कुमार शुक्ला बताते हुए कहा कि वह रॉ का एएसपी स्तर का अधिकारी है और उसे पटना से पुणे आने वाली ट्रेन में हथियार तस्करी की सूचना मिली है। इसी सिलसिले में उसे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना है।' पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी सही पहचान जाहिर की।

512 फीसद बढ़ गई है सबरीमाला रेल परियोजना की लागत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के असहयोग के कारण 111 किलोमीटर लंबी अंगामाली-सबरीमाला परियोजना प्रभावित हुई है।

नहीं होता है विश्वास हिमालय पर उग रही है घास

दुनिया में सबसे ठंडे स्थानों में से एक हिमालय के शिखर धीरे-धीरे गर्म हो रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आसपास भी इसका काफी असर हुआ है। एवरेस्ट के आसपास और कभी पूरी तरह से बर्फ से ढके रहने वाले हिमालय के बर्फीले इलाकों में घास और झाड़ियां पनप रही हैं। ब्रिटेन की एक्सटर विश्वविद्यालय के अध्ययन में यह बात सामने आई है।

एक्सटर विश्वविद्यालय का अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर बुरा असर हो रहा है। ● फाइल फोटो

पनप रहीं है वनस्पतियां

ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में सामने आया है कि हिमालय में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति पैदा नहीं होती थी और साल में कोई ऐसा वक्त नहीं होता था जब यहां पर बर्फ न हो। हालांकि यह अध्ययन बताता है कि इन स्थानों पर पानी की ज्यादा आवक से वनस्पतियों के पनपने में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

पानी की पूर्ति भले ही कम हो लेकिन वनस्पतियों में बढोतरी के कारण यह हिमालय क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकती है। यहां मौसमी बर्फ होती है और जब यह गर्म होती है तो इनके पिघलने की दर बढ़ जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही यहां से एशिया की बड़ी नदियों में से 10 नदियां निकलती हैं, जो कि एक अरब 40 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है।

दुर्गम इलाकों में पनप रही घास

इस अध्ययन में सैटेलाइट से प्राप्त डाटा का उपयोग कर घास और छोटी झाड़ियों के पनपने का पता लगाया है। इसके मुताबिक ऊंचाई को चार वर्गों में बांटकर के निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा 16 हजार से 18 हजार फीट के बीच वनस्पतियां सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। वहीं अन्य तीन वर्गों में भी बढोतरी दर्ज की गई है।

दोगुनी तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर

हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार इस सदी में दोगुनी हो चुकी है। पिछले चार दशकों में करीब एक चौथाई से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। शोधकर्ता केरेन एंडरसन के मुताबिक, यहां का पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। बर्फ के पिघलने पर बहुत सारे शोध किए गए हैं, जिसमें एक अध्ययन में बताया है कि 2000 और 2016 के बीच बर्फ के नुकसान की दर दोगुनी हो गई है।

नजर रखी जानी चाहिए

एंडरसन का कहना है कि घास और छोटे पौधे हिमालय के बड़े हिस्से को घेर रहे हैं। मुख्य पहाड़ों पर से बर्फ गायब हो रही है। यह काफी चिंताजनक है, जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। हालांकि यह बहुत बड़ा इलाका है।

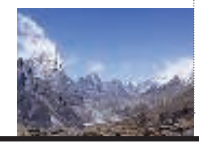

यहां नहीं उगते पौधे

माना जाता है कि नए पौधों के लिए 20 हजार फीट की ऊंचाई पर उगना संभव नहीं होता है। इसका कारण है कि इस ऊंचाई पर बर्फ के कारण पौधे उग नहीं पाते हैं।

गर्म होते इलाकों में से एक

यह इलाका दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहे इलाकों में से एक हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से दुनिया जूझ रही है। हालांकि इन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ग्लेशियरों का पिघलना है।

आर्कटिक में भी बढ़ी वनस्पति

आर्कटिक में वनस्पति बढ़ने पर हुए अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि वनस्पति बढ़ने से आसपास के परिदृश्य में गर्म प्रभाव पाया गया। पौधे अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और मिट्टी को गर्म करते हैं।

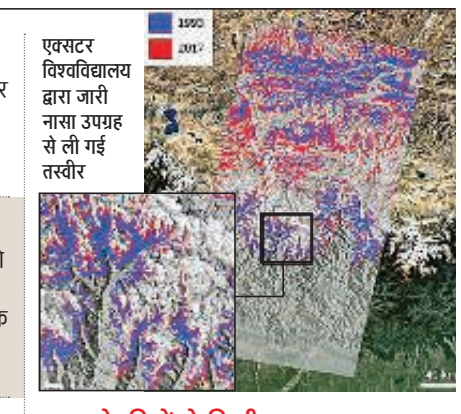

एक्सटर विश्वविद्यालय द्वारा जारी नासा उपग्रह से ली गई तस्वीर

नासा के चित्रों से मिली मदद

नासा के उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारी काफी उपयोगी रही है। नासा उपग्रहों द्वारा 1993 से 2018 के बीच खींचे चित्रों के अध्ययन के बाद एक्सटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समुद्र तल से करीब 13 हजार फीट से 18 हजार फीट तक वाले इलाकों में वनस्पति के प्रसार को मापा है।

न्यूज गैलरी

लद्दाख में 5.3 तीव्रता का भूकंप

जम्मू : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रविवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, इस भूकंप से अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कहीं से खबर नहीं आई है। सुबह 10 :54 बजे आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 .3 आंकी गई। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप के झटके कुछ सेकंड के लिए ही रहे। इस भूकंप का केंद्र गुलाम कश्मीर था। जैसे ही भूकंप के झटके आए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पिछले कुछ महीनों से जम्मू-कश्मीर में भी भूकंप के झटके कई बार महसूस किए गए हैं, लेकिन लद्दाख में कई दिनों बाद भूकंप आया है। (राब्यू)

खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह सिद्धू गिरफ्तार

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा ने शहर में छुपे खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। वह पंजाब से फरार था और शहर में पनाह लिए हुए था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पंजाब पुलिस के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग ने जरनैल सिंह के खिलाफ गत वर्ष फरवरी में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। वह बेंगलुरु के बागमाने टेक पार्क में काम कर रहा था और पिछले चार महीने से एक घर में बतौर पेइंग गेस्ट रह रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पंजाब पुलिस ने जरनैल सिंह को वांछित बताते हुए हमसे संपर्क किया था। हमने उसे खोज निकाला और पंजाब पुलिस को सौंप दिया।' (प्रेट्र)

हाईवे पर तैरती रही ग्लेशियर की 10 फीट ऊंची दीवार

बर्फबारी ▸ पहाड़ों पर भारी हिमपात से मैदानी इलाकों में ठंड बरकरार

चार धाम में हिमपात, निचले इलाकों में आज बारिश के आसार

जागरण टीम, देहरादून

उत्तर भारत में भीषण बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक तरफ जहां रास्ते बंद हैं और आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, भीषण ठंड से पाइप में पानी जम गया है। इसके अलावा झीलें भी जम गई हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ग्लेशियर का एक टुकड़ा 10 फीट ऊंची दीवार की तरह हाईवे पर तैरता हुआ दिखाई दिया था।

उत्तराखंड में 100 से ज्यादा गांवों में बिजली और संपर्क कटा : उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदलने लगा है। सुबह बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही उच्च हिमालय में रुक-रुक कर हिमपात हुआ। वहीं निचले इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश में मौसम की दुश्वारियों से अभी निजात नहीं मिली है। सौ से ज्यादा गांवों में बिजली की आपूर्ति अब भी बहाल नहीं हो पाई है। इसके अलावा करीब डेढ़ सौ गांव अब जिला मुख्यालयों से कटे हैं और डेढ़ दर्जन सड़कों पर आवागमन बाधित है।

वीडियो वायरल : हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पांच पर टिंकू नाला के पास ग्लेशियर की 10 फीट ऊंची दीवार ने वाहन चालकों के पसीने छुड़ा दिए। सोशल मीडिया पर आठ जनवरी की घटना से जुड़ा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हर कोई वीडियो देखकर हैरान है कि ग्लेशियर की 10 फीट ऊंची दीवार अपने आप ही करीब 200 मीटर तक खिसकती रही। ग्लेशियर को सड़क पर चलते देख पर्यटक और स्थानीय लोग पीछे की ओर भागने की बात कहते भी सुने गए। एक टैंपो ट्रैवलर पर्यटकों से भरकर किन्नौर की ओर जा रही थी, लेकिन ग्लेशियर आता देख चालक और सभी पर्यटक पीछे की ओर भागे।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पांच पर टिंकू नाला के पास ग्लेशियर की 10 फीट की दीवार ने वाहन चालकों के पसीने छुड़ा दिए। सोशल मीडिया पर आठ जनवरी की घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पांच पर टिंकू नाला के पास ग्लेशियर की चपेट में आया वाहन (वीडियो ग्रैब)। वाट्सएप

ऐसे हुई स्थापना

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्र सरकार ने 1984 में आपात स्थिति से निपटने के लिए एक केंद्रीय बल के गठन का निर्णय लिया। सरकार ने ऐसे विशेष बल की परिकल्पना की जो विशेष हथियारों से युक्त और बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित हों। साथ ही इन जवानों को आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाए। जून 1984 में एनएसजी के डायरेक्टर जनरल और इससे जुड़े अन्य मामलों में सरकार की स्वीकृति मिली। इस बल को अस्तित्व में लाने के लिए अगस्त 1986 में संसद में विधेयक लाया गया। इस विधेयक को 22 सितंबर, 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह सुरक्षाबल औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया।

यह है मूल सिद्धांत : एनएसजी के जवान तीव्र हमला करते हैं और अपना काम पूरा करके तुरंत निकल जाते हैं। इसे सभी तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय आपात बल के तौर पर गठित किया गया था। इसका गठन ब्रिटेन की एसएएस और जर्मनी की जीएसजी-9 की तर्ज पर किया गया है। एनएसजी एक लक्ष्य आधारित बल है।

इससे जानते हैं एनएसजी को: यह एक विश्वस्तरीय जीरो एरर फोर्स है। इसे विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसकी प्रकृति को इन चार बातों से जाना जाता है।

- उत्कृष्टता की खोज
- सबसे आगे रहना
- कोई गलती नहीं करना
- तेजी, आश्चर्य, चुपके से, यथार्थता और सटीकता

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ भी था डीएसपी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित डीएसपी देविंदर सिंह अति सुरक्षित विदेशी प्रतिनिधिमंडल (15 देशों के राजनयिकों) के साथ गुरुवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर था। इसके बाद शनिवार को एयरपोर्ट पर ड्यूटी से नदारद था। इस दौरान उसने दिल्ली जाने के लिए चार दिन की छुट्टी के लिए भी आवेदन दिया था।

श्रीनगर में रविवार को दक्षिण कश्मीर के आइजी विजय कुमार ने बताया कि उन्हें शनिवार को शोपियां के एसपी ने इनपुट दिया था कि कुछ आतंकी छिपने के ठिकाने से एक कार में भाग निकले हैं। यह ठिकाना जमीन के आठ फीट नीचे था और वहां जरूरत का सभी सामान था। सूचना मिलने के बाद उन्होंने डीआइजी कश्मीर को विशेष नाके लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद कुलगाम के मीर बाजार में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष नाके के दौरान वाहन को पकड़ लिया गया। यह अभियान डीआइजी अतुल गोयल के नेतृत्व में चलाया गया। कार में से दो एके-47 राइफल बरामद हुईं। इसके बाद श्रीनगर में डीएसपी के आवास से तलाशी के दौरान एक एके 47 राइफल व एक पिस्टल बरामद हुई। उसे आर्म्स एक्ट व गैर कानूनी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ दो आतंकियों के अलावा एक वकील भी था, जो आतंकियों का ओवर ग्राउंड वर्कर है। इनके पकड़े जाने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षाबलों ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। जिस कार में आतंकी डीएसपी के साथ भाग रहे थे, उसके मालिक का पता लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।

पकड़े गए दो आतंकियों में एक पुलिस भगोड़ा भी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

आतंकी नवीद पुलिस का भगोड़ा था, जो कि 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। सूत्रों के अनुसार डीएसपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों की स्क्रीनिंग होगी। क्योंकि गृह मंत्रालय भी चाहता है कि ऐसी काली भेड़ों की पहचान की जाए जो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलीजेंस ब्यूरो और रॉ भी जांच में सहयोग करेगा।

संसद हमले के दौरान भी चर्चा में आया था नाम : पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह का नाम संसद हमले के बाद भी चर्चा में आया था। अफजल ने यह दावा किया था कि कार देविंदर सिंह ने ही उपलब्ध करवाई थी। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने इससे इन्कार किया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि हमारे पास इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। इससे पूर्व भी डीएसपी कई बार आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। इसमें वूसली के आरोप भी शामिल हैं।

ट्रेन में छोड़ने वाली मां से मांगा मुआवजा

- फिल्मों में काम करने के लिए दो साल के बेटे को बेसहारा छोड़ा था
- भिखारियों सी जिंदगी और मानसिक आघात के लिए मांगे 1.5 करोड़
- श्रीकांत ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि मां को उसे अपना बेटा घोषित करने का निर्देश दे

मेकअप आर्टिस्ट श्रीकांत सबनीस(दाएं)फाइल फोटो। फेसबुक से

मुंबई, प्रेट्र : देश की आर्थिक राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो शायद अपनी तरह का देश का पहला मामला होगा। एक बेटे ने अपनी मां से 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। 40 साल के बेटे ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस एके मेनन की अदालत में सोमवार को उस पर सुनवाई होगी।

पेशे से मेक-अप आर्टिस्ट याचिकाकर्ता श्रीकांत सबनीस ने कहा है कि 38 साल पहले उसकी मां ने अनजान शहर में दो साल की उम्र में उसे जानबूझकर छोड़ दिया था। मां के छोड़े जाने के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसने काफी मानसिक आघात सहे और परेशानियों का सामना किया। सबनीस ने कहा है कि वो जिस खराब हालात से गुजरा है उसके लिए उसकी मां आरती महास्कर और उसके सौतेले पिता उदय महास्कर उसे मुआवजा दें।

याचिका के मुताबिक आरती महास्कर की शादी पहले दीपक सबनीस से हुई थी। वो दोनों पुणे में रहते थे, जहां फरवरी, 1979 में श्रीकांत सबनीस का जन्म हुआ था। आरती बहुत महत्वाकांक्षी थी और मुंबई फिल्म उद्योग में काम करना चाहती थी। सितंबर, 1981 में वह अपने बच्चे को लेकर मुंबई चली आई। लेकिन मुंबई पहुंचने पर वह दो साल के श्रीकांत को ट्रेन में अकेला छोड़कर चली गई। ट्रेन में रेलवे के अधिकारी की नजर उस पर पड़ी और उसने बाल गृह में उसे भेज दिया था।

बाद में उसकी कस्टडी को लेकर लड़ाई चली और 1986 में फैसला उसकी नानी के हक में आया और उसके बाद वह अपनी नानी के साथ रहने लगा। पहले वह अपनी दादी के साथ रहता था। लेकिन बाद में वह नानी के यहां पला-बढ़ा। श्रीकांत ने अपनी याचिका में कहा है कि साल 2017 में उसे जन्म देने वाली अपनी मां के बारे में पता चला। किसी तरह उसने अपनी मां का फोन नंबर हासिल किया और सिंतबर 2018 में फोन पर उसकी अपनी मां से बात हुई। श्रीकांत के मुताबिक उसकी मां ने यह तो माना कि वह उसका बेटा है। लेकिन यह भी बताया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते उसे उसको छोड़ना पड़ा था।

बाद में श्रीकांत ने अपनी मां और अपने सौतेले पिता से मुलाकात की। लेकिन वह उस वक्त हैरान रह गया, जब उसकी मां और उसके दूसरे पति ने उससे आग्रह किया कि उनके बच्चों के सामने वह अपनी सच्चाई नहीं बताए। अपनी मां और सौतेले पिता की यह शर्त सुनकर पहले से ही मानसिक रूप से परेशान श्रीकांत सबनीस और परेशान हो गया। कम उम्र में ही रिश्तेदारों के यहां शरण लेने और माता-पिता का साया नहीं होने से दर-दर भटकने के चलते वह पहले से ही बहुत परेशान था।

श्रीकांत सबनीस ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह उसकी मां को उसे अपना बेटा घोषित करने और यह एलान करने का निर्देश दे कि उसने दो साल की उम्र में उसे छोड़ दिया था। याचिका में कहा गया है कि आरती और उदय महास्कर ने श्रीकांत को मानसिक परेशानी दी है, जिसके लिए वो मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं।

याचिका में कहा गया है कि वादी ने पीड़ा भरा जीवन गुजारा है। उसने मानसिक आघात सहा है और असुविधाओं को झेला है। माता-पिता होते हुए भी वह अनाथों की तरह रहा है। वादी को तब तक भिखारी की तरह जीना पड़ा, जब तक वह अपनी नानी के पास नहीं पहुंच गया।

भोपाल में गिरफ्तार विंग कमांडर की एयर फोर्स ने शुरू की जांच

नईदुनिया, भोपाल : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को फोन लगाकर अपने मित्र को कुलपति बनाने की सिफारिश करने वाले गिरफ्तार विंग कमांडर कुलदीप वाघेला की एयर फोर्स ने भी जांच शुरू कर दी है। एयर फोर्स की एक टीम भोपाल आई थी, जिसने मध्य प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से वाघेला के खिलाफ दर्ज एफआइआर, गिरफ्तारी और अन्य जानकारियां जुटाईं।

सूत्रों के मुताबिक विंग कमांडर कुलदीप वाघेला के पकड़े जाने के बाद एयर फोर्स की टीम शनिवार को भोपाल आई थी। टीम ने एसटीएफ से वाघेला के खिलाफ सुबूतों के बाबत जानकारी ली है। इसके आधार पर वाघेला की रिपोर्ट एयर फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। उसके आधार पर ही वाघेला के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी। बताया जाता है कि राज्यपाल के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करने वाले विंग कमांडर वाघेला तथा डेंटल सर्जन डॉ. चंद्रेश कुमार शुक्ला से एसटीएफ द्वारा इसी तरह की दूसरी किसी धोखाधड़ी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपितों से एसटीएफ ने पूछा है कि उन्होंने इसके पहले किसी दूसरे मंत्री या अधिकारी से अमित शाह या अन्य किसी केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार के किसी मंत्री का नाम लेकर सिफारिशी फोन तो नहीं किया। मगर दोनों आरोपितों ने इससे इन्कार कर दिया है।

जेएनयू हिंसा के पीछे सरकार : कांग्रेस

- जेएनयू पर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
- आपराधिक जांच समेत फीस बढ़ोत्तरी वापस लेने की जरूरत बताई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जेएनयू हिंसा को लेकर गठित कांग्रेस की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पूरी हिंसा के पीछे सरकार का हाथ बताया है। साथ ही इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति एम. जगदीश कुमार को मास्टरमाइंड करार देते हुए उनकी तुरंत बर्खास्तगी की जरूरत बताई है। कमेटी ने कुलपति के अब तक के सभी वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा करने और पांच जनवरी को हुई हिंसा की अपराधिक जांच कराने की बात भी कही है।

जेएनयू हिंसा को लेकर कांग्रेस की ओर से गठित इस कमेटी ने शनिवार शाम को ही अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी थी। इसे रविवार को मीडिया के साथ साझा किया गया। इस कमेटी में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन, एनएसयूआइ के पूर्व अध्यक्ष हिबी ईडेन और अमृता धवन शामिल थीं। कमेटी ने इस दौरान जेएनयू पहुंचकर पांच जनवरी को हुई हिंसा के कारणों को लेकर छात्रों के अलग-अलग गुटों से बातचीत की थी। कमेटी में शामिल सुष्मिता देव के मुताबिक उन्होंने एबीवीपी से जुड़े छात्रों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन उनकी ओर से जांच का हवाला देते हुए बयान देने से इंकार किया गया। इसी तरह उन्होंने इस मामले में कुलपति का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

कमेटी ने इस दौरान पुलिस की भूमिका को भी संदेहास्पद बताया और कहा कि जब विवि के भीतर यह हिंसा हो रही थी, उस समय पुलिस विवि परिसर के बाहर ही खड़ी थी। कमेटी ने कुल पांच जरूरत बताई है, जिसमें विवि के कुलपति को बर्खास्त करने और उनके कार्यकाल में अब तक लिए गए सभी फैसलों की जांच करने, विवि के कुलपति, सुरक्षा कर्मियों और हिंसा में शामिल शिक्षकों की क्रिमिनल इंक्वायरी कराने, पूरे घटनाक्रम की एक विस्तृत न्यायिक जांच कराने, दिल्ली पुलिस आयुक्त की जवाबदेही तय करने सहित फीस बढ़ोत्तरी को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की बात शामिल है।

दिल्ली पुलिस की जांच में पकड़े जाएंगे जेएनयू हिंसा के आरोपित : ईरानी

सूरत, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच में शिक्षण संस्थान में हिंसा के आरोपित पकड़े जाएंगे।

वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर एक जनसभा में हिस्सा लेने गुजरात के सूरत आई थीं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पांच जनवरी को हुई हिंसा के सवाल पर ईरानी ने संवाददाताओं से कहा, 'किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी अगर सर्वर तोड़ता है या बाधा खड़ी करता है तो उसे समझना चाहिए कि वह संस्थान भारतीय करदाताओं के पैसे से चलता है। उसकी इन हरकतों से संस्थान के हितों को नुकसान पहुंचता है।'

स्मृति ईरानी। फाइल

उन्होंने कहा, 'ऐसी हरकतों से तीन हजार से ज्यादा छात्रों के हितों का भी नुकसान होता है, जिन्होंने पंजीकरण करवाया है। उन शिक्षकों का भी नुकसान होता है, जिनका राजनीति से कोई लेनादेना नहीं। विपक्षी दलों ने उनकी ओर से नहीं बोला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जांच के बाद इंसाफ होगा।'

पहल

केंद्रीय विद्यालयों में 'क्रोध मुक्त' परिसर बनाने की तैयारी, दिनचर्या में तन-मन और बुद्धि साधकर संतुलित करेंगे व्यवहार

गुस्सा न आए अब ऐसा पाठ पढ़ाएंगे स्कूल

बृजेश दुबे, कानपुर

कानपुर में स्कूली बच्चों के खुदकशी के ऐसे एक दो नहीं कई मामले हैं। बीते दो सालों में दसवीं कक्षा से नीचे के आधा दर्जन से अधिक छात्रों के खुदकशी या खुदकशी के प्रयास के मामले सामने आ चुके हैं। कारण, गुस्सा और तनाव। खुद को संयमित रख पाने की इच्छाशक्ति न होना। शिक्षक भी पीछे नहीं हैं। कुछ शिक्षकों पर छात्रों को बेरहमी से मारने के मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कुछ ने तनाव में खुदकशी की है। ऐसी घटनाएं देखकर ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में 'क्रोध मुक्त क्षेत्र' बनाने की पहल की थी।

सीबीएसई की इस पहल को मजबूत करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कदम बढ़ाया है। केंद्रीय विद्यालय कक्षाओं और पाठ्यक्रम का ऐसा संयोजन करेंगे, जिससे तन-मन और बुद्धि, तीनों को साधकर छात्र गुस्से पर काबू पा सकें। इसके लिए संगठन ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से फरवरी तक विस्तृत योजना मांगी है, ताकि अगले सत्र से इसे अमल में लाया जा सके। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल के अनुसार पूरा विद्यालय परिसर क्रोध मुक्त होगा। खेलकूद, संगीत शिक्षा, योग-व्यायाम, प्रार्थना सभा जैसी बालचर गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। काउंसलर नियुक्त होंगे। छात्र-शिक्षक-कर्मचारियों के लिए भी कई गतिविधियां आयोजित होंगी।

ऐसी होगी बच्चों की दिनचर्या

संतुलित आहार और पर्याप्त नींद
शारीरिक और मानसिक स्वच्छता
शारीरिक श्रम, खेलकूद अनिवार्य
सुबह एवं शाम अनुलोम-विलोम
प्राणायाम के साथ ध्यान
लचीलेपन के लिए योगासन
रोजाना पर्याप्त जलग्रहण
किसी से तुलना नहीं
स्व उत्थान का संकल्प और कार्य
घमंड छोड़कर विनम्रता
संयम व शिष्टाचार का पालन
शांति और सद्भाव का प्रोत्साहन

केस स्टडी

डेढ़ वर्ष पहले बर्रा के एक स्कूल के सातवीं के छात्र ने खुदकशी कर ली, उसके अधूरे होमवर्क पर शिक्षक ने डांट दिया था।

एक वर्ष पूर्व कल्याणपुर के स्कूल के छात्र ने डाई पी ली थी। कारण, मारपीट करने की शिकायत पर उसके अभिभावक बुलाए गए थे।

बार-बार क्रोध करने से शरीर का तंत्रिका तंत्र और मेटाबॉलिज्म (पाचन प्रक्रिया) प्रभावित होता है। इससे मानसिक अवसाद, निराशा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्मृति भ्रम, हृदय रोग जैसी बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। आंख और ब्रेन में हैमरेज हो सकता है।

- डॉ. एलसी अग्रवाल, सेवानिवृत मुख्य परामर्शदाता, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

उप्र के डीजीपी ओपी सिंह को तीन माह सेवा विस्तार के लिए केंद्र को भेजा पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र सरकार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह को तीन महीने का सेवा विस्तार देना चाहती है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद गृह विभाग ने इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। आइपीएस अफसर ओपी सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेंगे। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को प्रदेश पुलिस के मुखिया की कमान संभाली थी। डीजीपी पद पर करीब दो साल तैनात रह चुके ओपी सिंह को प्रदेश की कानून व्यवस्था में प्रस्तावित बड़े ढांचागत बदलाव के कारण सेवा विस्तार देने की चर्चा है। हालांकि वह मुख्य सूचना आयुक्त के पद की रेस में भी आगे बताये जा रहे थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रही है। इस प्रणाली के पर्यवेक्षण और उसे सुचारु रूप से जमीन पर उतारने के मकसद से ओपी सिंह को सेवा विस्तार देने के तर्क पुलिस महकमे में दिए जा रहे हैं।

महिला के शरीर में बम बंधे होने की धमकी पर उतारा विमान

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच एक महिला यात्री ने शरीर पर बम बंधा होने की बात कहकर विमान को उड़ाने की धमकी देकर सनसनी फैला दी। आनन फानन में विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। जांच में कुछ संदेहजनक नहीं मिलने के बाद मोहिनी मंडल नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआइ) हवाई अड्डे से 114 यात्रियों को लेकर एयर एशिया के विमान ने शनिवार रात 10 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। विमान के बीच आसमान में पहुंचते मोहिनी चीखते लगी कि उसके शरीर में बम बंधा है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। यह सुनते ही यात्री शोर मचाने लगे। पायलट ने तुरंत कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया और आपात लैंडिंग की इजाजत मांगी। कुछ देर बाद विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। विमान को आइसोलेशन वे पर विमान को ले जाया गया। वहां एक-एक कर सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। मोहिनी को अन्य यात्रियों से दूर ले जाकर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद विमान की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद मोहिनी को छोड़ बाकी यात्रियों को विमान में चढ़ाया गया और विमान रात 11 बजे मुंबई के लिए दोबारा उड़ान भरी।

रातभर हुई पूछताछ : मोहिनी को गिरफ्तार करने के बाद एयरपोर्ट पुलिस रातभर उससे थाने में पूछताछ करती रही। रविवार को उसे बैरकपुर अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की मानें तो मोहिनी के आसपास 1डी और 1ई नंबर सीट भी बुक की गई थी, लेकिन उस पर यात्री नहीं आया। पुलिस उनके बारे में भी पता लगाने में जुटी है।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 13 जनवरी 2020

दैनिक जागरण

जिसमें सबकी भलाई हो उस काम को अविलंब शुरू किया जाए

आतंक के साथी

कश्मीर के कुलगाम में डीएसपी देविंदर सिंह के साथ दो आतंकियों की गिरफ्तारी राज्य के सुरक्षा तंत्र की गंभीर खामी को ही उजागर करती है। इस अफसर की गाड़ी में चंडीगढ़ जा रहे दोनों आतंकी खूंखार किस्म के हैं और एक तो उन कई लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार है जो राज्य के बाहर से कश्मीर अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए गए थे। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप है और एके-47 राइफल लूटने का भी। यह अकल्पनीय है कि ऐसे खतरनाक आतंकी का साथी एक पुलिस उपाधीक्षक निकला। चूंकि इस पुलिस अफसर को पिछले वर्ष 15 अगस्त को ही राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आतंकियों के मददगार इस पुलिस अफसर को इतना बड़ा सम्मान कैसे मिल गया? किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि जब इस पुलिस अफसर का नाम संसद पर हमले के सिलसिले में भी उछला था और फिरौती मांगने के एक अन्य मामले में भी तब फिर उसे सम्मानित करने का काम किस आधार पर किया गया? यह एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब सामने आना ही चाहिए।

अब इसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर पुलिस में देविंदर सिंह सरीखी और भी काली भेड़ें तो नहीं हैं? सच्चाई जो भी हो, इस अफसर ने अपनी वर्दी को दागदार बनाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के बहादुर पुलिसकर्मियों की शान में बट्टा लगाया है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस तरह के निकृष्ट तत्वों के कारण ही कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का सफाया करने में मुश्किल हो रही है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देविंदर सिंह और उसके साथ गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में कई जगहों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। इससे तो यही संकेत मिलता है कि देविंदर सिंह दरअसल पुलिस की वर्दी पहनने वाला एक आतंकी ही है। देविंदर सिंह का कुत्सित आचरण यह भी बताता है कि कश्मीर में फैला आतंकवाद किस तरह एक कारोबार का रूप ले चुका है। आम धारणा है कि इस कारोबार को कुछ नेता और व्यापारी ही परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन देविंदर सिंह की गिरफ्तारी ने एक और गंभीर खतरे की ओर संकेत किया है। अब जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर का प्रशासनिक स्तर पर नए सिरे से कायाकल्प किया जा रहा है तब फिर इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्य पुलिस और अधिक समर्थ कैसे बने? अब हर उस शख्स की पड़ताल होनी चाहिए जिसे लेकर तनिक भी यह संदेह हो कि वह आतंकियों का हमदर्द है।

चूड़ा-दही और सियासत

मकर संक्रांति के मौके पर अपने शुभचिंतकों को चूड़ा-दही और तिलकुट खिलाने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसी बहाने यह मौका एक-दूसरे का कुशल-क्षेम जानने का भी होता है। यह मौका खरमास की वजह से रुके पड़े कई कार्यों की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन पर विमर्श का भी होता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि विशेषकर बिहार में चूड़ा-दही के भोज ने धीरे-धीरे सियासत में घुसपैठ कर ली। इस भोज की पकड़ अब इतनी मजबूत है कि भविष्य की सियासत की तस्वीर को भी उकेरता दिखता है। सियासी गलियारे में मकर संक्रांति के मौके पर गिने-चुने राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं को अपने घर या निर्धारित जगह पर बुलाकर उन्हें सम्मान देने की परंपरा शुरू की। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का यह अच्छा मौका बन गया। इस परंपरा में परस्पर सहयोग की एक नई परिपाटी भी शुरू हुई। खाने पर बुलाए गए कार्यकर्ता ही आयोजन को ताकत देने लगे। कोई दही तो कोई चूड़ा तो कोई तिलकुट लेकर नेता के घर पहुंचने लगा। परस्पर सहयोग से सामूहिक भोज ने धीरे-धीरे प्रायः राजनीतिक दलों को आकर्षित किया। इसका तेजी से फैलाव हुआ। विशेषकर राज्य की राजधानी पटना में होने वाले इन आयोजनों को देखकर इस बात को समझा जा सकता है। अब कार्यकर्ताओं से ज्यादा इस बात पर गौर किया जाने लगा कि दल या नेता के आयोजन में किसने शिरकत की। सियासी ताने-बाने के धागों को समझने-परखने का यह विशेष अवसर बन गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार की मकर संक्रांति भी कई मैसेज देगी। किस राजनीतिक दल के नेता ने किस आयोजन में जाना पसंद किया और किस आयोजन से दूरी बनाए रखी, इससे भावी राजनीतिक समीकरण भी उभरकर सामने आएगा। यह चर्चा का विषय होगा और इसके निहितार्थ भी निकाले जाएंगे। इस सियासी भोज में यदि नेता राज्य के विकास में बाधक बने ग्रहों के निवारण की चर्चा करें तो जनता की मकर संक्रांति मन जाएगी। अटकी पड़ीं योजनाओं-परियोजनाओं पर उनके विमर्श आमजन के बीच आने लगे तो इस आयोजन का महत्व और बढ़ जाएगा। जो कार्यकर्ता दही-चूड़ा लेकर पहुंचते हैं, अपने साथ जनता का मांग पत्र भी लेकर जाने लगें तो ऐसे आयोजन की लोकप्रियता और बढ़ेगी।

मकर संक्रांति पर नेताओं कार्यक्रम की महत्ता तब और बढ़ी जाएगी जब जनता के लिए अच्छे मैसेज निकलकर आएं। सिर्फ नेताओं की नजदीकी और दूरी की खबरों में जनता खुद को ढूंढती हुई निराश होती है।

संवैधानिक मूल्यों की घातक अनदेखी

जगमोहन सिंह राजपूत

देश के प्रमुख राजनीतिक दल जनता को यह विश्वास दिलाएं कि वे किसी भी सूरत में संविधान का मखौल उड़ाए जाने की अनुमति नहीं देंगे

इन दिनों कई घटनाएं संभवतः संविधान के प्रति असम्मान का प्रदर्शन करने के लिए ही अंजाम दी जा रही हैं। इसी कड़ी में केरल विधानसभा ने नागरिकता कानून के विरोध में एक पहल की है। केरल विधानसभा को इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए कि संविधान में संघ, राज्य तथा समवर्ती जैसी तीन सूचियां हैं। इनमें नागरिकता का विषय संघ सूची में आता है। ऐसे में नागरिकता के मामले में राज्य के पास कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना क्या वैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसे एक वाक्य में स्पष्ट कर दिया कि 'यह असंवैधानिक है।'

केरल के इस घटनाक्रम से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में संवैधानिक गरिमा पर प्रहार होता दिखा। वहां शपथ लेने वाले मंत्रियों ने अपने राजनेताओं के नाम लेकर उनके प्रति अनुग्रह प्रकट कर शपथ विधि की प्रक्रिया पूरी की। यह देश की राजनीति में मूल्यों के क्षरण तथा उससे उपजे पतन की एक और मिसाल थी। यह संविधान का, उसे बनाने वालों मनीषियों का सार्वजनिक अपमान था। स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इस पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने समारोह में एक मंत्री को दोबारा शपथ लेने के लिए बाध्य किया। क्या देश के वरिष्ठ नेताओं को यह दिखाई नहीं देता कि यह तो उनकी वरिष्ठता का भी अपमान है। भारत के प्रजातंत्र का इतिहास इस पतन के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानेगा। अभी भी समय है कि देश के बड़े राजनीतिक दल जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से कहें कि वे सभी सामूहिक रूप से संविधान के इस प्रकार मखौल उड़ाए जाने की अनुमति नहीं देंगे। संविधान के प्रति सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को निष्पक्ष होकर सम्मान प्रकट करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र और केरल में जो कुछ हुआ वह जनतंत्र की जड़ों पर आघात करता है। इसे हर हालत में रोका जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में दोनों राज्यों के राज्यपालों ने जिस गरिमा, समझ एवं सूझबूझ का परिचय दिया, वह सराहनीय है। यह एक बार फिर स्थापित करता है कि राज्यपाल का पद कितना महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की तो बात ही निराली है। वहां विश्वविद्यालय के कुलाधिपति-राज्यपाल को प्रांगण में जाने पर द्वार बंद मिलता है। किसी जिले में जाने का कार्यक्रम बनाने पर जिला अधिकारी कहता है कि पहले राज्य सरकार की अनुमति लाएं। ऐसे माहौल में विद्यार्थियों का अशिष्ट हो जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या यह सब राष्ट्रहित में है? उससे ही जुड़ा प्रश्न है कि क्या यह व्यवहार नई पीढ़ी के हित में है? एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर विरोध के स्वर उठना जनता में अनपेक्षित नहीं है, मगर बसों का जलाना, हिंसा भड़काना, रेलगाड़ियों को रोकना किस सभ्य समाज में स्वीकृत हैं? क्या एक उत्तरदायी विपक्ष का कर्तव्य इसे रोकना नहीं था? कहां गए वे प्रकांड बुद्धिजीवी जो देश में सेक्युलरिज्म के लिए केवल स्वयं को ही योग्य और जिम्मेदार मानते हैं? वे खुद दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं।

अवधेश राजपूत

इस देश ने जिस मूल्य आधारित शासन व्यवस्था की अपेक्षा के साथ प्रजातंत्र में प्रवेश किया था, वह कहीं खो गया है। इस देश ने तमाम ऐसे लोगों को भी देखा है जो सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी मूल्य आधारित राजनीति से नहीं डिगे हैं। क्या कोई पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को भुला सकता है? वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ध्येय वाक्य 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' जीवनपर्यंत उन पर लागू रहा। वहीं देश ने उन नेताओं को भी देखा है जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से अपने और अपने परिवार की संपन्नता के लिए नए शिखर छुए। जनता ने आपातकाल का अनुभव भी किया, अपनी तथा अपने मत की शक्ति को पहचाना और सत्ता को पारिवारिक अधिकार मानने वालों को धूल-धूसरित करने में कोई कोताही नहीं की। इस समय जो कुछ देश में एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर हो रहा है, वह कुछ और नहीं, बल्कि सत्ता से बाहर हुए, अपनी स्थिति से निराश तथा असुरक्षित भविष्य की आशंका से डरे हुए लोगों का एक अंतिम प्रयास ही माना जा सकता है। वे यह क्यों नहीं याद करते हैं कि जनता संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनके अनादर, जनता से कटे हुए, उनकी स्वार्थवश राजनीतिक पैंतरेबाजी को नहीं भूली है। अब ऐसा लगता है कि सत्ता से बाहर जाने पर नेताओं की आंख से शर्म भी कहीं न कहीं पूरी तरह तिरोहित हो जाती है।

बीते दिनों सीएए के विरोध में कई जगह हिंसा फैली। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हिंसक वारदातें देखने को मिलीं। इसमें जान-माल का नुकसान भी हुआ। देश के अति महत्वाकांक्षी और जनता द्वारा तिरस्कृत नेताओं की राज्य में कोई कमी नहीं है। सूबे के तमाम जिले संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और हताश नेता इस तथ्य का दुरुपयोग करने में कभी हिचकते नहीं। राज्य से आने वाले नेताओं में मुलायम सिंह और मायावती दोनों ही स्वयं को प्रधानमंत्री पद के करीब मानते रहे। मुलायम सिंह को उनके सुपुत्र ने ही बड़ी 'शालीनता' से दल में किनारे लगा दिया। वहीं मायावती को जनता ने हाशिये पर पहुंचा दिया। ऐसे में निराशा और हताशा का घर करना स्वाभाविक है। केवल इन्हीं नहीं, बल्कि अन्य दलों में भी यह भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परिवर्तन की अपेक्षा में ही उत्तर प्रदेश की जनता से अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाया। उन पर विश्वास किया, मगर मूल्यों की क्षरणता में कमी नहीं आई। अखिलेश ने बारी-बारी से कांग्रेस तथा बसपा से गठबंधन करके समाजवादी अवधारणा को अशक्त किया। उनके ऐसे दांव को कोई समझ नहीं पाया। तमाम गठबंधन लोगों की समझ से परे रहे हैं और अपने स्वाभाविक अंत की गति को प्राप्त होते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी का गठजोड़ भी इसी श्रेणी में आता था। सत्ता में आने के लिए जब सिद्धांतों से दूरी बनाई जाती है तब मूल्य आधारित व्यवस्था बेमानी हो जाती है।

जहां तक संविधान की बात है तो उसमें केंद्र शब्द ही नहीं है। उसके लिए संघ शब्द का प्रयोग बहुत सोच-समझकर किया गया है। इस भावना को बनाए रखना आवश्यक है। इन संबंधों की एक गरिमामयी संवैधानिक सीमा निर्धारित है। उसका पालन हर स्थिति में होना ही चाहिए। सिद्धांतविहीन राजनीति को गांधी जी सामजिक पाप मानते थे। उनका नाम लेने वालों और उनकी विरासत पर दावा करने वालों को यह याद रखना चाहिए।

(लेखक शिक्षा एवं सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

गहन मंथन का होगा यह साल

आशुतोष झा

2019 में जो बीज पड़े उनकी असल परीक्षा 2021 में होगी। देश की राजनीतिक दिशा वहीं से तय होगी

आजादी के बाद के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो गुजरे साल को भारत के लिहाज से सबसे अधिक घटनाप्रधान वर्ष कहा जा सकता है। दरअसल पिछले सात-आठ महीनों के अंदर ही कुछ इतने बड़े फैसले और प्रयोग हुए जिनमें भारत का नया स्वरूप, नया रुख, नई दिशा-दशा तय करने की क्षमता है। हालांकि समाज खासकर विश्वविद्यालयों एवं राजनीति में तत्काल इसका अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगा है, लेकिन ये फैसले इतने बड़े हैं कि उनके व्यापक असर की छाप लंबे वक्त के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वक्त ही तय करेगा कि अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, एनपीआर एवं एनआरसी और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर आक्रामक दिख रहे विपक्ष का आंदोलन सिर्फ बुलबुला है या फिर जमीन पर इसका कोई स्थायी प्रभाव भी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष जिसके जरिये अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है, वह सत्तापक्ष की ताकत बनने वाला है। ऐसा इसलिए, क्योंकि विपक्ष और विपक्षी सरकारों द्वारा जिस तरह संविधान की दुहाई देते हुए संवैधानिक प्रक्रिया को ही कमजोर किया जा रहा है, वह दोधारी तलवार बन सकता है। विपक्ष जिसे सांप्रदायिक बता रहा, कहीं जनता उसे जरूरत तो नहीं मान रही है, खासकर ननकाना साहिब की घटना के बाद। नया साल मंथन का साल होगा। जो बीज 2019 में पड़े हैं उसकी असली परीक्षा 2021 में होगी और बहुत कुछ वहीं से तय होगा कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

फिलहाल राजनीति बहुत गर्म है। इतनी तपिश उस वक्त भी नहीं थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। विरोध जारी था, लेकिन वह कभी मजबूत शक्ल नहीं ले पाया। बुलबुले की तरह विरोध की हवा उठी और गायब हो गई, लेकिन इस बार दो चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ बड़े बहुमत के साथ दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी घोषित और जनमत से पारित विचारधारा को शक्ल देना शुरू किया। वहीं लगभग उसी वक्त में महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और उसने विपक्ष को एकबारगी जिंदा कर दिया। महाराष्ट्र में जिस तरह भाजपा को अलग-थलग किया गया और झारखंड में बिखरे हुए विपक्ष ने इकट्ठा होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल किया उसने उत्प्रेरक का काम किया। अगर राज्यों में ये घटनाएं नहीं होतीं तो कहा जा सकता है कि सीएए, एनपीआर, एनआरसी को लेकर विरोध उग्र नहीं दिखता। खैर, लंबे अरसे के बाद पहली बार विपक्ष एकजुट दिख रहा है। दरअसल यह विपक्ष की कुलबुलाहट है और कुछ हद तक हताशा है, जिसके कारण वह यह अवसर गंवाना नहीं चाहता। राजनीति में जिस तरह कड़वाहट घुली है और गैर भाजपा शासित राज्यों में संवैधानिक संकट खड़ा होने की स्थिति आ गई है, वह इसी का सुबूत है। केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले और संसद से पारित कानून तक को राज्य सरकारें अंगूठा दिखा रही हैं। केरल से प्रस्ताव पारित कर नागरिकता कानून को निरस्त करने की अपील हो रही है। यह कितना घातक हो सकता है इसकी केवल कल्पना की जा सकती है।

अगर इस तरह विधानसभाएं संसद पर अंगुली उठाने लगें तो फिर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक राज्य की विधानसभा दूसरे राज्य की विधानसभा के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने लगेगी। यह घोर अराजकता की स्थिति होगी, लेकिन विपक्ष को इसकी चिंता नहीं है। राजनीतिक कड़वाहट कितनी अधिक है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एनपीआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पर अंगुली उठाकर विपक्षी दलों ने जनगणना पर भी विवाद का साया डाल दिया है। कुछ राज्यों में सत्ताधारी दल राज्यपाल को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। केरल में तो हद ही हो गई जब राज्यपाल को बोलने से भी रोकने की कोशिश हुई। इस तरह के अनुचित विरोध और राजनीतिक हित के लिए संवैधानिक प्रक्रिया पर विवाद देश की जनता को रास आएंगे, यह मानना मुश्किल है, पर विपक्ष फिलहाल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, भले ही इसकी कीमत बाद में चुकानी पड़े।

फैसला जनता को करना है। दरअसल फैसला वही माना जाता है जिस पर जनता मुहर लगाती है और उसके साथ ही राजनीति की दिशा तय होती है। इस साल दिल्ली और बिहार में चुनाव हैं। वहीं 2021 में असम, केरल, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं जहां भाजपा अपने लिए संभावना तलाश रही है। ध्यान रहे कि असम, बंगाल और केरल ही वे राज्य हैं जहां विरोध सबसे ज्यादा तीव्र है। असम में भाजपा की सरकार है और बंगाल तथा केरल में सत्ताधारी दल भाजपा की धमक से आशंकित हैं, जबकि तमिलनाडु में 2021 में पहला विधानसभा चुनाव करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में होगा। भाजपा के पर फैलाने के लिए यह उचित अवसर होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि पूर्व में हुए चुनाव के अनुसार जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा का काल 2021 में ही खत्म होता। हालांकि अब राज्य का स्वरूप बदल गया है। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यदि वहां चुनाव की स्थिति बनती है तो अनुच्छेद 370 की भी जमीन पर परख होगी। इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड ने भाजपा के सामने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। भाजपा के इतिहास में पहली बार संगठन के ही एक सिपाही ने पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर उसे हरा दिया। वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ चेहरे स्थानीय नेतृत्व को सीधी चुनौती देते दिखे। यह अंतर्द्वंद्व भाजपा नेतृत्व के लिए एक प्रश्न है।

भाजपा की विचारधारा से जुड़े मुद्दे लगभग पूरे हो चुके हैं। यह गौरव पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को जाता है। जिस राम मंदिर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी के काल में भाजपा मजबूत कदम बढ़ाने में सफल रही थी, उस मंदिर की आधारशिला भी 2020 में ही रखी जानी है। वहीं विपक्ष का एक धड़ा अभी भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में यह मानकर चलना चाहिए कि 2020 गहन मंथन का साल होगा।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख-दुख

सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के अपने कर्मों के फल होते हैं। सुख के लिए वह भरपूर प्रयास करता है और दुख जाने-अनजाने किए पापों के कारण उसके सिर का बोझ बनते जाते हैं। अपने कर्मों का सुख भोगना उसका अधिकार है। यदि वह सुख अन्य के साथ बांटता है तब भी अपने सुख पर उसका अधिकार वैसा ही अक्षुण्ण रहता है। इसी तरह दुख जिस सघनता से आया है वैसा ही रहेगा चाहें जितने लोगों से चर्चा कर ली जाए। सुख का बढ़ जाना और दुख का कम हो जाना मात्र एक भ्रम है। यह अवश्य होता है कि जब मनुष्य अपने सुख की अभिव्यक्ति करता है तो उसका अहम संतुष्ट होता है। उसे अन्य की अपेक्षा ऊपर उठे होने की अनुभूति होती है। दुख में प्राप्त होने वाली संवेदनाएं भी एक तरह से उसके अहम को संबल देने का कार्य करती हैं जिससे अपने पाप कर्मों, अवगुणों का पश्चाताप कम होता लगता है।

दुख और सुख वास्तव में अंतर की अवस्था हैं। इन्हें अंतर तल पर ही भोगना श्रेयस्कर होता है। सुख की अनुभूति को यदि पूर्ण रूप से अंतर ग्राह्य किया जाए तो सद्कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। दुख की सघनता को यदि पूर्णता में आत्मसात किया जाए तो पश्चाताप पूर्ण होता है और मन सचेत होता है। सुख और दुख दोनों ईश्वर ने दिए हैं। यह मनुष्य और ईश्वर के मध्य का आदान-प्रदान है। इसे सार्वजनिक करना ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप करना है। समझना होगा कि आपका सुख न कोई अन्य भोग सकता है न कोई आपके हिस्से का दुख वहन कर सकता है।

आज जीवन में अंतरंग कुछ रह ही नहीं गया है। मन की भावनाएं जिन्हें मन की शक्ति बननी चाहिए अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बनती जा रही हैं। इसे खुलेपन का नाम दे दिया गया है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोग टूट रहे हैं। हताश, निराश हो रहे हैं। इससे बचना है तो मन की भावनाओं को आत्मसात करना आना चाहिए। भावनाओं को किससे और किस स्तर पर बांटना है यह विवेक होना चाहिए।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

रोजगार और कृषि का संकट

शिवांशु राय

सरकार को रोजगार और कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े भयावह स्थिति को बयां कर रहे हैं

एनसीआरबी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वे वाकई चिंताजनक हैं। साल 2018 में 12 हजार 936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की थी, जबकि इसी अवधि में खेती-किसानी से जुड़े 10 हजार 349 लोगों ने आत्महत्या की थी। अर्थव्यवस्था में व्याप्त सुस्ती में एक बड़ा कारक बेरोजगारी का होना है। इसका भयावह परिणाम एनसीआरबी के डाटा में दिखने लगा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दिसंबर में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.7 फीसद तक पहुंच गई है जो नवंबर 2019 में 7.48 फीसद थी। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी उनकी आर्थिक क्रियाओं को संकुचित करती जा रही है।

ऐसे में आने वाले बजट में सरकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में जॉब देने वाले ऑटो, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कृषि और एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर लगातार दबाव में होने के कारण खपत और निवेश दोनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा को हमें रोजगारपरक बनाने के साथ-साथ गुणवत्ता से भी लैस करने की जरूरत है जिससे हमें दीर्घकाल में इसका फायदा मिल सकता है। इसी तरह निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है और यह तब होगा जब उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ खपत में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में छूट दिया था, पर अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मामला खपत पर जाकर अटक जा रहा है। इसलिए सरकार इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के उपायों पर रुख कर सकती है। कॉरपोरेट की सेहत तभी सुधरेगी जब ग्रामीणों की जेब में पैसा होगा। वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने से पहले हमें मौजूदा कृषि संकट को देखने की जरूरत है, क्योंकि दोगुनी आय का मार्ग इसी से प्रशस्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कार्यबल का 64 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि कार्यबल कृषि पर एक सीमा से अधिक निर्भर है, क्योंकि रोजगार के अन्य विकल्प नहीं हैं। इससे कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच प्रति श्रमिक उत्पादकता में व्यापक अंतर का भी पता चलता है। कार्यबल को कृषि से इतर कार्यों में लगाकर किसानों की आय में काफी वृद्धि की जा सकती है।

किसानों की आय का बड़ा जरिया पशुधन भी है। इस साल 20वीं पशुधन गणना भी संपन्न कराई गई थी जिसमें कुल पशुधन में 4.6 फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए नस्ल संवर्द्धन, बेहतर चारा और पोषाहार, पशु स्वास्थ्य की नीतियों पर बल देने की आवश्यकता है। इसी तरह रोजगार संवर्द्धन और कृषि क्षेत्र में सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े भयावह स्थिति को बयां कर रहे हैं जिसमें उत्पादक पीढ़ी (किसान और युवा) मौत को गले लगा रही है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

युवाओं में भटकाव

बेजा विरोध से मजबूत होती मोदी सरकार शीर्षक से लिखे अपने लेख संजय गुप्त ने हाल ही में जेएनयू में जो हिंसा हुई, उसका नरेंद्र मोदी के विरोधी जिस तरह राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के बारे में कहा था, 'मेरा विश्वास युवा शक्ति पर है। इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे, जो अपने पराक्रम से विश्व को बदल देंगे।' युवा वर्ग का देश और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्र और समाज को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए युवाओं की सोच अहम होती है। हालांकि यह तभी संभव है जब युवाओं की सोच अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अनुकूल हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज देश के कुछ युवा राजनेताओं और धर्म के ठेकेदारों के प्रलोभनों या बहकावे में आकर स्वार्थ के वशीभूत होकर राष्ट्र-समाज की सेवा की भावना का परित्याग कर रहे हैं। जेएनयू में हिंसा की घटना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इस घटना के लिए मोदी सरकार पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है। आखिर मोदी सरकार इसके लिए कैसे और क्यों जिम्मेदार हो सकती है? इससे पहले जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे थे, क्या वे भी मोदी सरकार ने करवाए? नहीं। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने सत्ता में इसलिए नहीं बैठाया है कि वे जेएनयू के मसलों में ही उलझे रहें।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

प्रचार का फंडा

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के जेएनयू में चल रहे विरोध में भागीदारी के बाद बिना मतलब का विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म कलाकार भी हम सब की तरह एक नागरिक हैं और उनको भी उतना ही हक है किसी मुद्दे का साथ देना और विरोध करना। परंतु इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि यह सब उनकी एक फिल्म छपाक के रिलीज होने से पहले ही किया गया। क्या इसका समय अपने आप एक बड़ा सवाल नहीं उठाता है? उन्होंने जामिया एवं एएमयू के मामले पर अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उस समय उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही थी।

बाल गोविंद, नोएडा

शांति का मार्ग उचित

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अगर इन दोनों मुल्कों में युद्ध हुआ तो इसकी आग से अन्य अनेक देशों को भी झुलसना पड़ सकता है। युद्ध की स्थिति में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि सहित अनेक तरह की समस्याओं का जन्म होगा, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज पूरी दुनिया को गांधी जी द्वारा बताए अहिंसा के मार्ग पर चलने की जरूरत है। शांति ही उन्नति का मार्ग है। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा गतिरोध को रोकने के लिए अन्य मुल्कों को भी साथ आकर शांति स्थापना के प्रयास करने चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

उपद्रवियों को प्रोत्साहन

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अनेक स्थानों पर ऐसे प्रदर्शन हुए जहां पर पत्थर बाजी हुई, आगजनी की गई, सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट किया गया एवं बड़ी संख्या में पुलिस वाले घायल हुए। इस मामले में एक तरफ प्रदेश सरकार तोड़फोड़ में शामिल अराजक तत्वों की पहचान कर उनसे नष्ट की गई संपत्ति की भरपाई करने का निर्देश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा उनको रुपयों से मदद देकर अराजक तत्वों को प्रोत्साहित कर रही हैं। यह एक जिम्मेदार विपक्ष का कार्य नहीं है।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

विश्वविद्यालयों में अशांति

चाणक्य और स्वामी विवेकानंद की इस धरा पर आज विश्वविद्यालयों में जैसी अशांति व अराजकता व्याप्त है, वह हमारे शैक्षणिक व चारित्रिक पतन का प्रतीक है। कुछ चुनिंदा लोगों के स्वार्थ पूर्ति के लिए शतरंज के मोहरे बने छात्र क्या अपना विवेक खो चुके हैं? आज हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के अतिरिक्त न जाने क्या-क्या गतिविधियां होती रहती हैं, यह चिंता की बात है।

डॉ. हेमा मनोज शर्मा, स्याना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सं

368 वें अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के संशोधन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने अनेक संशोधनों पर विचार करने हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था।

पीयूष द्विवेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आजकल

वैचारिक असहिष्णुता से ग्रस्त वामपंथी

यह सही है कि लोकतंत्र में सबको अपने विचार व्यक्त करने और सरकार के निर्णयों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसका भी एक सलीका होता है। विरोध की एक भाषाई मर्यादा होती है, जिसका ध्यान रखने की अपेक्षा किसी भी सजग नागरिक से की जाती है। उस पर भी यदि आप बौद्धिक रूप से एक विशिष्ट पहचान रखते हैं तब आपका दायित्व और बढ़ जाता है। लिहाजा विरोध का तरीका शालीन और मर्यादा के दायरे में होना चाहिए

प्रतीकात्मक

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पिछले लगभग दो-तीन माह से निरंतर चर्चा में है। पिछले दिनों कुछ नकाबपोश लोगों के विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट करने की खबर आई और उसके बाद से इस मामले में बवाल मचा हुआ है। इसके लिए एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों के बीच तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इस बारे में पुलिस की जांच जारी है, फिर भी यह विडंबना ही है कि देश का यह विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक उपलब्धियों के कारण कम, बेमतलब विवादों के कारण अधिक चर्चा में रहता है। बहरहाल, पुलिस ने अपनी आरंभिक जांच में नकाबपोश उपद्रवियों की पहचान करने का दावा जरूर किया है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों के प्रति समर्थन व्यक्त करने में जुटे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का रवैया किसी न्यायाधीश की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पीड़ित और पीड़क का निर्णय कर लिया है और उसी के आधार पर अभियान चलाने में लगे हैं।

बुद्धिजीवियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे बेहद शालीनता से किसी मामले पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस दल और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके प्रति इस देश के वामपंथी बुद्धिजीवियों का विरोध घृणा के स्तर तक जा पहुंचा है, जिसका प्रकटीकरण इनकी भाषा से लेकर कुतर्कों तक में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लेखक और शायर जावेद अख्तर ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्षा आईशी घोष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर तंज करते हुए ट्वीट किया कि 'जेएनयूएसयू अध्यक्ष के खिलाफ एफआइआर पूरी तरह से समझ में आती है। उसने अपने सिर से एक राष्ट्रवादी, देश प्रेमी लोहे की छड़ को रोकने की हिम्मत कैसे की।' सवाल यह है कि जावेद अख्तर इसमें 'राष्ट्रवादी' शब्द का प्रयोग किस आधार पर कर रहे हैं? अभी जब इस हमले की जांच चल रही है, ऐसे में वे कैसे कह सकते हैं कि हमला राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने किया है। ऐसी क्या अधीरता है जो वे जांच पूरी होने तक का इंतजार करने की बजाय खुद ही दोषी तय करने में लगे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इनके पुत्र फरहान अख्तर सीएए के विरोध में सड़क पर उतर पड़े थे, लेकिन जब पूछा गया कि क्यों विरोध कर रहे हैं तो बगलें झांकने लगे और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे में यही प्रतीत होता है कि इन लोगों के विरोध के पीछे कोई व्यावहारिक आधार नहीं, केवल और केवल वैचारिक असहिष्णुता है। यह असहिष्णुता फिल्म जगत से जुड़े तमाम और लोगों में भी है और इस कदर है कि वे प्रधानमंत्री के प्रति तू-तड़ाक की भाषा के इस्तेमाल करने पर तक उतर चुके हैं।

इससे पूर्व सीएए के विरोध के दौरान भी हमें बुद्धिजीवी वर्ग का यही असहिष्णु चरित्र दिखाई दिया था। बीते दिनों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस में अपना वक्तव्य देते हुए सीएए का जिक्र करना शुरू किया तो वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब बौखला गए और राज्यपाल को रोकने के लिए बढ़ने लगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना था कि अगर उनके एडीसी ने नहीं रोका होता तो ये उन पर हमला कर देते। जो व्यक्ति राज्यपाल के प्रति सार्वजनिक रूप से इतनी आक्रामकता दिखा सकता है उसमें विपरीत विचारों के लिए कितनी असहिष्णुता होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

इन बुद्धिजीवियों की असहिष्णुता का एक और उदाहरण पिछले वर्ष तब भी दिखा जब जेएनयू में बतौर प्रोफेसर एमिरेट्स जुड़ीं रोमिला थापर विश्वविद्यालय प्रशासन के बायोडाटा मांगने पर बिगड़ गईं। इसे वामपंथियों ने सरकार द्वारा बुद्धिजीवियों को दबाने की कोशिश करार दिया। आखिर यह कैसी बुद्धिजीविता है जो मन से दंभ और असहिष्णुता को खत्म नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, अपने अंधविरोध में इन बुद्धिजीवियों की भाषा का स्तर भी एकदम सतही होता जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान ही लेखिका अरुंधती राय दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विरोध प्रदर्शन में छात्रों के बीच पहुंचीं। वहां उन्होंने कहा कि एनपीआर में जब नाम-पता पूछा जाए तो वे रंगा-बिल्ला और सात रेसकोर्स बताएं। उनका इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ था। अरुंधती राय को बताना चाहिए कि देश की जनता द्वारा बहुमत से निर्वाचित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके कौन-सी बौद्धिकता का परिचय दिया है?

आश्चर्य है कि इसके बाद भी ये लोग कहते फिरते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और सरकार तानाशाही कर रही है। रामचंद्र गुहा, अमर्त्य सेन से लेकर साहित्य जगत के भी अनेक नाम हैं जो वर्ष 2014 के बाद से सत्ता-विरोध की आड़ में किसी न किसी बहाने से अपने मोदी विरोध के एकसूत्रीय एजेंडे को हवा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। बुद्धिजीवी होने का अर्थ होता है कि आप की बौद्धिक चेतना किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और वैचारिक संकीर्णता से मुक्त, बुद्धि और ज्ञान के विस्तृत धरातल पर प्रतिष्ठित हो। बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की जाती है कि वे देश को दिशा दिखाएंगे। लेकिन क्या हमारे इन बुद्धिजीवियों से ऐसी कोई अपेक्षा की जा सकती है। एक आयातित विचारधारा के संकीर्ण दायरे में बैठकर इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने दूसरी विचारधारा को निशाने पर लेने को ही अपना शगल बना लिया है। विपरीत विचार के विरोध में ये घृणा के स्तर तक जा पहुंचते हैं, लेकिन जब उसी स्वर में इनका प्रतिवाद होता है तो तानाशाही और अभिव्यक्ति की आजादी का विलाप भी करने लगते हैं। इनकी सारी बौद्धिकता केवल एक विचारधारा का विरोध करने मात्र के लिए समर्पित लगती है, उसके अलावा इन्हें देश में कोई और समस्या व चुनौती नहीं नजर आती। इनकी इस हालत पर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की यह पंक्ति बिल्कुल सटीक लगती है :

इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं।

जेएनयू : वाद-विवाद बनाम हिंसा

डॉ. खुशबू गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो उच्च अकादमिक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहां प्रवेश पाना बहुत मुश्किल माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां हर किसी को अपना मत रखने तथा विरोध करने, वाद-विवाद और विचारों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता रहा है। एक ऐसा परिवेश जहां अध्ययन के लिए मध्यरात्रि में भी छात्राएं पुस्तकालय जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं। इस जगह से ही शिक्षा ग्रहण करके निकले छात्र आज देश के उच्च पदों पर कार्यरत हैं।

इसी संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, 'हमारे समय में यह विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था। यह बहस और विचारों के लिए जाना जाता था, हिंसा के लिए नहीं।' पिछले करीब चार वर्षों से यह विश्वविद्यालय विवादित स्थान बना हुआ है। आखिर ऐसी गतिविधियां इस शैक्षणिक संस्थान में क्यों घटित हो रही हैं? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे लग रहे हैं, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति को देख बहुत दुख होता है। संयोगवश मुझे भी वहां पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जेएनयू के बारे में यही जाना कि ऐसा गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान, ऐसा वातावरण भारत में कहीं नहीं है। हमें गर्व होता था कि हम ऐसे संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

बीते कुछ समय से वहां फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था जिसके चलते सभी प्रशासनिक अकादमिक कार्य ठप है। चूंकि वहां सेमेस्टर सत्र चलता है जिसके लिए हर छह महीने में छात्रों को पंजीकरण करना पड़ता है ताकि वो अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकृत हो सकें। धरना-प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा यह भी कहा गया कि हम सड़कों पर इसलिए उतरे हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी वर्गों को है और अगर फीस बढ़ा दी जाएगी तो ऐसे लोग शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे, जो बढ़ी हुई फीस देने में सक्षम नहीं हैं और जब आम छात्र आगे की पढ़ाई के लिए पंजीकरण करने के लिए अकादमिक बिल्डिंग गए तो वामपंथी छात्रों द्वारा उन्हीं छात्रों को मारा-पीटा गया जिनके लिए वो धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना के दो दिन पहले से इंटरनेट सुविधा को भी बाधित किया गया ताकि पंजीकरण न हो सके और प्रशासनिक कार्य ठप रहे। असहिष्णुता और इस तरह की तानाशाही से पूरे कैंपस का वातावरण खराब किया जा रहा है और शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।

जो भी हिंसात्मक और बर्बरतापूर्ण घटना कैंपस में बीते दिनों हुई, उसे नहीं होना चाहिए था। अपने हितों के लिए आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर अपनी बात मनवाना अक्षम्य है। ऐसी घटनाएं देश के अन्य विश्वविद्यालयों को टारगेट करके विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकीं जा रही हैं। मामला जेएनयू में बढ़े फीस का था, लेकिन इस घटना के बाद देश के अन्य इलाकों में छात्रों द्वारा देश विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। ये मुद्दे कहां से आ गए? क्या वे अलगाववादियों को अवसर प्रदान कर रहे हैं? जहां भारत को वैश्विक पटल पर एक महान शक्ति के रूप में जाना जाने लगा, विकास के पथ पर लाया जा रहा, वहीं अन्य राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति में पक्ष-विपक्ष, सहमति-असहमति, विरोध में बयानबाजी सही है, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना या शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को बरगलाना, ये किस स्तर की राजनीति है? देश की राजनीति को किस तरफ ले जाया जा रहा है? राष्ट्रीय हितों जैसे मुद्दों जिससे भारत का विकास हो सके, उनसे ध्यान हटाया जा रहा है, देश निर्माण के बजाय देश को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है जो दुखद और निंदनीय है।

खरी-खरी

ईमानदार होने की उलझन

शांतिलाल जैन

एक उलझन में पड़ गया हूं मैं। एक छोटी-सी बेईमानी करने से एक बड़ा लाभ मिलने का अवसर सामने है। बचपन में स्कूल में बालसभा में 'ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी' पर जो भाषण मैंने दिया था, वो बार-बार प्रतिध्वनित होकर मेरे विवेक से टकरा रहा है। ऐसे में मेरी मदद को सिन्हा सर आगे आए। बोले, 'ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, मगर तुम्हारे लिए है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। जो कहा गया है, उससे कहीं ज्यादा अनकहा है। कहा गया है- द बेस्ट पॉलिसी, अनकहा है- फॉर अदर्स। इसे एक साथ पढ़ो यार। जो नीति वाक्य मंच से कहे जाते हैं, वे सुनने वालों के लिए हुआ करते हैं, वक्ताओं के लिए नहीं। होते तो ये नायक, कथावाचक, मुल्ला-मौलवी, पादरी, जीवन-प्रबंधन गुरु, उपदेशक आदि इतने धनी नहीं होते।'

'लेकिन सर, मैं तो हमेशा ही ईमानदार...' मैंने टोका।

'हमेशा के लिए किसने बोला है तुम्हें? कहां लिखा है- ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर एवर? स्कूल में हम भी पढ़े हैं यार और ठीक-ठाक ही पढ़े हैं। हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। ईमानदारी हर पल बदलने वाली शै है। जब तक आप आम नागरिक हैं, तब तक ये बेस्ट पॉलिसी है, जब अफसर हैं तब नहीं है। जब तक आप मंच के ऊपर हैं तब तक है, नीचे आए तब नहीं है। जब आप विपक्ष में हैं तब है, जब आप सत्ता में हैं तब नहीं है। जब तक आप ग्राहक हैं तब तक है, जब आप विक्रेता हैं तब नहीं है। जब आप वादी के वकील हैं तो ईमानदार तकरीरें अलग हैं, जब आप प्रतिवादी के हैं तब की ईमानदार तकरीरें अलग हैं।

और सर, जो बचपन में पढ़ा वो?

'तुमने बालसभा में भाषण दिया, शील्ड मिली, प्रमाण पत्र मिला, फोटू खिंचा, ऑनेस्टी ओवर! अब भूल जाओ उसको। नैतिक शिक्षाएं ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं, उनके सबक भी जीवन में ऑप्शनल होते हैं। एक छोटे स्टेप से बड़े फायदे की मंजिल तक पहुंचने का ऑप्शन अभी है तुम्हारे पास। ये राह तुम नहीं चुनोगे तो कोई और चुनेगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल पर न पहुंच जाओ। जब वहां पहुंचोगे, दुनियादारी में सफल बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें। ऑल द बेस्ट। मैं अब भी उलझन में हूं।

ट्वीट-ट्वीट

दिल्ली के शाहीन बाग में आज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वे बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। उनका कहना है कि सीएए विरोध के नाम पर कुछ लोग वहां रोज सड़क पर जाम लगा रहे हैं। खुद तो बिरयानी उड़ा रहे हैं, पिकनिक टाइप माहौल है और स्थानीय लोग परेशान हैं।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम सही कहा कि इतिहास वह नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। हमारे इतिहासकार भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के खिलाफ आम लोगों के संघर्ष को कलमबद्ध कर पाने में नाकाम रहे। आम भारतीयों को इतिहास की किताबों से जानबूझकर विलुप्त कर दिया गया। राहुल कौशिक@kaushkrahul

जल्द ही दो महत्वपूर्ण तारीखें दस्तक देने वाली हैं। एक फरवरी को पेश होने वाला बजट दर्शाएगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर हम कितने गंभीर हैं। वहीं 11 फरवरी को आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ हालिया राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव को बताएंगे। भारत भले ही कैसा देश हो, लेकिन यह कभी बोर नहीं होने देता।
चेतन भगत@chetan_bhagat

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर विचार करना चाहिए?

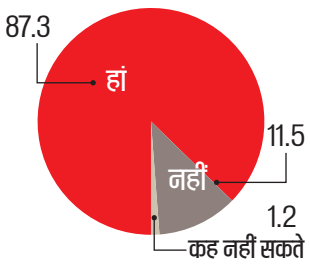

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या यात्री विमान को निशाना बनाने के लिए ईरान की जबावदेही तय की जानी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

धरना दें, अनशन करें, हो भारत बदनाम,
वोटबैंक मजबूत हो सिर्फ यही इक काम।
सिर्फ यही इक काम राम से रक्खें दूरी,
मौलाना का साथ बना उनकी मजबूरी।
सगा वर्ग बस एक उसी का वंदन करना,
ममता जी का रोज होय इस खातिर धरना।
– ओमप्रकाश तिवारी

सद्गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

उत्तर प्रदेश डायरी

प्रियंका की गुरिल्ला शैली व प्रशासन की आफत

प्रियंका वाड्रा के हर बार उत्तर प्रदेश आने की दस्तक सुनते ही प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के हाथ-पांव फूलने लगते हैं। उन्हें मैडम के गुप्त कार्यक्रम पर गहरी नजर रखनी पड़ती है कि वह कब, कहां जाने की प्लानिंग कर रही हैं। पिछले दिनों लखनऊ में वह अचानक पूर्व पुलिस अधिकारी एसआर दारापुरी के घर जाने के लिए निकल पड़ीं। इस घटना में उनकी सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस अधिकारी को जो झेलना पड़ा, उसे देखते हुए पुलिस अधिकारी सचेत हो गए हैं कि मिसेज वाड्रा से दूरी रखकर ही बात करनी है।

लखनऊ के बाद वह एक सुबह अचानक दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए निकल पड़ीं, यद्यपि प्रशासन द्वारा अतिरिक्त एहतियात बरतने से वहां कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। वर्षों बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में फिर सक्रिय हुईं प्रियंका के पास बेशक कोई विधायी या संवैधानिक पद नहीं है, इसके बावजूद उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वह भी अभेद्य सुरक्षा कवच में रहती हैं। जाहिर है कि उनकी गुरिल्ला राजनीतिक शैली स्थानीय शासन-प्रशासन के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों के लिए भी सरदर्द बनती होगी। कोई नहीं भूल सकता कि सुरक्षा संबंधी चूक के चलते इस परिवार की दो बड़ी हस्तियां जान गंवा चुकी हैं। इस पृष्ठभूमि में इस परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सुरक्षा प्राविधानों का उल्लंघन न करें, पर राहुल और प्रियंका अक्सर इसका उल्लंघन करते दिखते हैं। राहुल गांधी द्वारा बीच-बीच में सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर कई दिनों के लिए लापता हो जाने पर संसद में भी चिंता व्यक्त की जा चुकी है। प्रियंका भी उसी राह पर दिखती हैं। उनका यह कहना सही है कि मैं (प्रियंका वाड्रा) कहां जाऊंगी, इसके लिए मुझे यूपी सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

प्रतीकात्मक

बहरहाल, उनकी सुरक्षा का प्रोफाइल देखते हुए घोर अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा उन्हें प्रशासन को अपने भ्रमण कार्यक्रम की पूर्व-जानकारी देनी ही चाहिए। लखनऊ और मुजफ्फरनगर की घटनाओं में कोई आकस्मिकता नहीं थी। ऐसे में आमजन के अलावा कांग्रेसी भी नहीं समझ पा रहे कि दीदी (ज्यादातर कांग्रेसी प्रियंका को इसी रिश्ते से संबोधित करते हैं) गुरिल्ला ढंग से क्यों निकलती हैं। इतने बड़े परिवार की सदस्य को ऐसा करने की क्या जरूरत? इसकी असली वजह तो प्रियंका ही जानती होंगी। लोकसभा चुनाव में अपेक्षानुसार छाप छोड़ने में विफल रहने की निराशा इसकी एक वजह हो सकती है जिससे उबरने के लिए वह कई अवसरों पर अति-आक्रामकता धारण कर लेती हैं। जाहिर है, इससे उन्हें मीडिया में अधिक स्पेस मिल जाता है। यदि यह धारणा सही है तो भी सुरक्षा की अनदेखी बेहद खतरनाक है। देश अपने सभी नेताओं को सुरक्षित देखना चाहता है।

आशावादी सपा : पिछले तीन दशकों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की ही पार्टी रही है, इसके बावजूद जब भी चुनाव आता है, इस पार्टी के बड़े नेता मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह अलग बात है कि जमकर पसीना बहाने के बावजूद पार्टी को कुछ खास हासिल नहीं होता। लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रियंका जिस तरह सक्रिय हैं, उससे कांग्रेसी कितने संतुष्ट हैं, पता नहीं, पर उनकी सक्रियता पर सपाई गदगद हैं। उन्हें 2012 विधानसभा चुनाव से पहले का कालखंड याद आ रहा है, जब इसी तरह राहुल गांधी ने पूरे प्रदेश को मथ डाला था। उनके तेवर प्रियंका की ही तरह आक्रामक थे। जब चुनाव नतीजे आए, तो सपा की लॉटरी निकली। सपाई मानते हैं कि 2012 और 2020 के जमीनी हालात में कोई खास फर्क नहीं है। कांग्रेस की वास्तविक समस्या है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का अकाल। पार्टी के बड़े नेता, खासकर गांधी-नेहरू परिवार के सदस्य खूब मेहनत से राजनीतिक फसल तैयार तो करते हैं, पर जमीनी कार्यकर्ताओं के अभाव में फसल दूसरी पार्टियां काट ले जाती हैं। कांग्रेस नेताओं की मेहनत का प्रभाव भाजपा विरोधी मतदाताओं के संगठित होने की शक्ल में नजर आता है, पर 2012 विधानसभा चुनाव में इसका लाभ अंततः सपा को मिला। पार्टी को उम्मीद है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी सपा ही वास्तविक भाजपा विरोधी चेहरा होगी। बाकी पार्टियां लाख मेहनत कर लें, जब चुनाव की नौबत आएगी, उस वक्त भाजपा विरोधी मतदाताओं का भरोसा सपा पर ही टिकेगा। कहना कठिन है कि सपा की यह धारणा और आशा कितनी सही है, पर यह बात एकदम सही है कि कांग्रेस के पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं बचे। यदि कांग्रेस का लक्ष्य विधानसभा चुनाव है तो पार्टी के पास दो वर्ष का समय है। कांग्रेस के शुभचिंतक चाहते हैं कि नेतृत्व गुरिल्ला राजनीति छोड़ धरातल मजबूत करे अन्यथा कांग्रेस की मेहनत पर सपा की उम्मीदें फलीभूत होने की त्रासदी रोकना असंभव हो जाएगा।

सार्थक पहल

नागरिकता कानून का अवलोकन

डॉ. आशीष कुमार मैसी
पूर्व अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार

सीएए का विरोध औचित्यहीन है। भीड़ को धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम के बहकावे में न आकर इस संशोधित नागरिकता कानून का स्वयं अवलोकन करना चाहिए

प्रख्यात लेखिका सुश्री लैरी मे की रिपोर्ट 'क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी 2019' ने विश्व में उथल-पुथल मचा दी थी। तब से अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों को और अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा। अमेरिका एवं यूरोप के कुछ देशों में हाल में नागरिकता संशोधन कानूनों में धार्मिक उत्पीड़न से ग्रसित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के प्राविधानों में प्राथमिकता दिखने लगी है।

वर्ष 2000 से भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अल्पसंख्यक उत्पीड़न की शिकायतें हद पार कर रही थी। उसका प्रभाव भारत की आंतरिक व्यवस्था पर दिखा था। संयुक्त राष्ट्र की बीते 20 वर्षों की रिपोर्ट के अनुरूप भारत सरकार भी इस हलचल से प्रभावित हुई और मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए पड़ोसी देशों के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की पुरजोर वकालत की थी। मनमोहन सिंह के इस ज्वलंत सवाल की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरवाद से उत्पन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के शिकार लोगों की चिंता थी।

देश के संसदीय इतिहास में वोट बैंक से प्रभावित हमारा तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार मौका देखकर यू-टर्न मारते दिखा है। शाह बानो प्रकरण पर तत्कालीन सरकार का यू-टर्न खासा चर्चा का विषय रहा जिसके चलते भारत की राजनीतिक व विधिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा? ऐसे दलीय नेतृत्व के चलते भारत में आधार, जीएसटी एवं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आया। फिर वोट बैंक से प्रभावित स्पष्ट नीति व नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की सरकार सभी मूल प्रश्नों पर बैक गियर में नजर आई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान व बांग्लादेश में समझदार और संवेदनशील मुसलमान नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। धार्मिक कट्टरवाद के आगे पुलिस व प्रशासन भी फेल है।

भारत में विधि का शासन है। यहां हर समस्या का समाधान व उसका तरीका-सलीका विधि द्वारा निर्धारित है। लोकतंत्र में विपक्ष और विरोध आवश्यक है। भारत गणराज्य में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परिधि के अंदर ही विरोध को न्यायोचित माना जाता है जिसका अर्थ हिंसा, तोड़-फोड़, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कदापि नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में विरोध आंदोलन चला। इस गांधीवादी विरोध में न तो वैमनस्य था, न ही हिंसा के लिए कोई स्थान। इस तर्कसंगत एवं शांतिपूर्ण विरोध ने विदेशी सत्ता की नींव की चूलें हिला दी थी। इमरजेंसी काल का विरोध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1975 में उभरा और इस विरोध ने एक राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया। इस जनांदोलन ने भी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन के संकल्प को साकार किया।

बीते वर्षों के दौरान गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भी 'भ्रष्टाचार हटाओ' का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला। इस आंदोलन ने भी सत्ता परिवर्तन के संकल्प को साकार किया। ऐसे आंदोलनों में ठोस तथ्य थे, तर्क थे, कुतर्क के लिए कोई स्थान न था। भारत का संविधान एक गतिशील संविधान है जो देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालता व बदलता रहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया है। वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इन संशोधन पर गहनता से विचार करने हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन सांसद सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कुछ माह में ही भारत सरकार के मंत्री बनने के कारण 25 दिसंबर 2017 को इस समिति की अध्यक्षता मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को सौंपी गई। इस समिति में कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा व असम से सांसद सुष्मिता देव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मो. सलीम, बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीशचंद्र मिश्रा व सपा नेता जावेद अली खां इस समिति के प्रमुख चेहरे थे।

प्रतिकात्मक

कुल मिलाकर संयुक्त संसदीय समिति में 30 सांसदों के अतिरिक्त भारत सरकार के गृह, न्याय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े खुफिया तंत्र अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) सहित सभी प्रमुख एजेंसियों की उपस्थिति प्रमुखता से दर्ज की गई। इस समिति के पास 9,267 व्यक्तियों के ज्ञापन, 56 गैर सरकारी संगठनों की सूची उपलब्ध है, जिन्होंने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। जेपीसी का दस्तावेज 438 पृष्ठों का तैयार हुआ।

मजे की बात यह है कि जब जेपीसी में आपकी पार्टी की सशक्त उपस्थिति रही, तब क्या आपके सांसद बैठक में अनुपस्थित थे? या संसद में समय नष्ट कर रहे थे। बिल के दस्तावेज बनाने वाले आप कैसे अनुच्छेद 19 को नहीं देख पाए। यह तर्क भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों की गरिमा को धूमिल करने वाला कुतर्क लगता है। सत्य तो यह है कि सड़क पर विरोध और विद्रोह करने वाले नेता राफेल की जेपीसी जांच कराने की वकालत करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ पड़ताल कमेटी घोषित करने में थकते नहीं थे। अब वही नेता जेपीसी को धता बताकर धर्म के आधार पर भ्रम फैलाने में लगे हैं। संसद के दोनों सदनों ने सर्वदलीय समझदारी और संसदीय साझेदारी से बने इस बिल को साझा जिम्मेदारी के साथ पास करके राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस पर अनुमति मुहर लगा दी गई। अब यह देश का कानून बन गया। इसके पश्चात कानून का कोई भी विरोध भारत की संसद की अवमानना नहीं तो क्या कहा जाएगा?

42 दिन तक हिमाचल प्रदेश के मनाली के नौ गांवों में रेडियो व टीवी नहीं चलेंगे। दरअसल, 14 जनवरी से 42 दिन तक आराध्य देव, गौतम-व्यास ऋषि व नाग देवता तपस्या में लीन हो जाएंगे। देवताओं को शांत वातावरण मिले, इसके लिए ग्रामीण गांव में रेडियो व रेडियो नहीं चलाएंगे न ही खतों का रुख करेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 13 जनवरी 2020

बंगाल

विस्फोट कांड से उभरे गंभीर सवाल

बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी में कथित रूप से जब्त पटाखे को पुलिस द्वारा निष्क्रिय करते समय तीन दिन पहले जो धमाका हुआ और जो तस्वीरें मीडिया में आईं वह काफी चिंताजनक है, क्योंकि गंगा नदी के इस पार यानी नैहाटी के रामघाट इलाके में ही नहीं, बल्कि उस पार हुगली जिले के चुंचुड़ा तक दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गंगा किनारे जिस जगह पटाखे को निष्क्रिय किया जा रहा था वहां 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। इसी से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना भयावह था। आखिर पटाखे में ऐसा क्या था कि गंगा के उस पार करीब डेढ़ से दो किलोमीटर दूर तक के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों में दरारें आ गईं। खिड़कियों के कांच टूट गए। मकानों-घरों के एस्बेस्टस वाली छतें तक टूट गईं।

आरोप तो यह लग रहा है कि बिना विशेषज्ञ की मदद से ही पटाखों को निष्क्रिय किया जा रहा था। परंतु यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि जब इतने अधिक मात्रा में पटाखे बरामद किए गए थे तो उसे नष्ट करने के लिए विशेषज्ञों और जानकारों से मदद क्यों नहीं ली गई? क्योंकि इससे सिर्फ लोगों के घरों एवं गाड़ियों का ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वायु भी प्रदूषित हुआ है। कहा जा रहा है कि कई मेटाडोर अवैध पटाखे फैक्ट्रियों से जब्त की गई थी। जिसे पिछले कई दिनों से गंगा किनारे नष्ट किया जा रहा था। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था। पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से पुलिस वाले धमाके होने के बाद वहां से भागे हैं इससे यही लगता है कि बिना विशेषज्ञों की मदद के ही निष्क्रिय किया जा रहा था और जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर चला गया तो वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। यह गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों को चोटें लगीं। खैर 48 घंटे बाद शनिवार को मौके पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम पहुंची और नमूने एकत्रित किए। जिससे यह पता चलेगा कि आखिर इतने तीव्र धमाके की वजह क्या थी? भाजपा ने तो घटना की एनआइए तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विशेषज्ञ एजेंसी जांच कराने की बात कही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्काल जांच और धमाके से जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने का एलान कर दिया है। परंतु इस विस्फोट की वजह क्या थी यह सामने आना चाहिए।

गंगा किनारे जिस जगह पटाखे को निष्क्रिय किया जा रहा था वहां 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना भयावह था।

दरअसल इन पटाखों में जिन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है वे बेहद खतरनाक होते हैं। कॉपर, कैडियम, लेड, मैग्नेशियम, सोडियम, जिंक, नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे रसायन का मिश्रण पटाखों को घातक बना देते हैं। इससे 125 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि होती है। अचानक इन पटाखों से फटने से आदमी कुछ पल के लिए बहरा हो जाता है। कई बार पीड़ित स्थायी रूप से भी बहरा हो जाता है। पटाखों से निकली चिंगारी से हर साल सैंकड़ों लोगों की आंखें और चेहरे जख्मी हो जाते हैं। सांस की बीमारी तो होती ही है। ऐसे समय में दमे के रोगी की परेशानी भी बढ़ जाती है।

उत्तराखंड

वन संपदा पर नजर रखेगी फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स

उत्तराखंड 71 प्रतिशत से ज्यादा वनक्षेत्र वाला राज्य है। स्वाभाविक रूप से इसी अनुपात में उत्तराखंड वन्यजीवों के लिहाज से भी समृद्ध है। अब सरकार राज्य के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर इन पर नजर रखने के लिए नई व्यवस्था अमल में लाई है। यह है फारेस्ट ड्रोन फोर्स। इस आधुनिक तकनीक के जरिये विभाग सभी वन प्रभागों की निगहबानी तो करेगा ही, साथ ही वहां हो रही किसी तरह की गतिविधि भी नजरों से छिपी नहीं रह पाएगी।

सरकारी बजट ठिकाने लगाने की प्रवृत्ति पर इस व्यवस्था से अंकुश लगाया जा सकता है। पौधारोपण की कागजी कार्रवाई इससे आसानी से पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि नई व्यवस्था में जंगलों में पौधारोपण की निरंतर मॉनिटरिंग होगी। पौधारोपण के मामलों में ही गड़बड़झाले की बातें पूर्व में सामने आती रही हैं। यही नहीं, रोपित पौधों का सरवाइवल रेट भी बहुत अच्छा नहीं है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में। ऐसे में ड्रोन से इस पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अलावा विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जहां विभाग के कर्मचारी स्वयं नहीं पहुंच पाते, उन वन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी ड्रोन फोर्स विभाग को उपलब्ध कराएगी। वनों में तस्करों की सक्रियता को देखते हुए वन संपदा और वन्यजीव, दोनों की सुरक्षा सरकार के लिए खासी चुनौतीपूर्ण रहती है।

अब अगर ड्रोन आसमान से नजर रखेगा तो साफ पता चल जाएगा कि किन क्षेत्रों में पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है और कहां अवैध खनन करने वाले सक्रिय हैं। यही नहीं, गर्मियों में जंगलों में आग हर साल वन महकमे के लिए परेशानी का सबब बनती है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब विभाग इस पर काबू पाने का दावा करता है, तब तक करोड़ों की वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी होती है। इस दृष्टिकोण से ड्रोन की भूमिका जंगल की आग पर समय रहते काबू पाने में महत्वपूर्ण रहेगी। वन्यजीवों की गणना में ड्रोन तकनीकी बड़ी मददगार साबित होगी। जंगली जानवरों और प्रवासी परिंदों पर नजर रखने में भी ड्रोन उपयोगी साबित होंगे, इसमें कोई शक नहीं।

प्रतीकात्मक

राज्य में पहली बार मगरमच्छ एवं घड़ियालों की गणना में ड्रोन के उपयोग का खाका खींच लिया गया है और यह गणना इस माह के आखिरी हफ्ते से प्रस्तावित है। उत्तराखंड ड्रोन फोर्स के समन्वयक डॉ.धकाते के अनुसार नदियों, जलाशयों एवं बांधों के क्षेत्र में पानी के बहाव के हिसाब से ड्रोन फिक्स किए जाएंगे। इनकी दूरी तय होगी और इनसे एक ही समय में फोटो एवं वीडियोग्राफी होगी। फिर इनका विश्लेषण कर मगरमच्छ एवं घड़ियालों की संख्या निकाली जाएगी। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक 6370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने मगरमच्छ और घड़ियाल हैं, इसकी सही तस्वीर अब सामने आएगी। नेपाल सीमा पर शारदा नदी से लेकर हरिद्वार तक वन विभाग के चार वृत्तों पश्चिमी, शिवालिक, राजाजी एवं कार्बेट टाइगर रिजर्व में इनकी अच्छी-खासी संख्या है। वर्ष 2016 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ पश्चिमी वृत्त में मगरमच्छों की गणना हुई, जिसमें ड्रोन का प्रयोग किया गया। यहां इनकी संख्या 65 निकली थी, लेकिन राज्य के अन्य क्षेत्रों में मगरमच्छ एवं घड़ियाल की गणना नहीं हो पाई। ऐसे में प्रदेश में इनकी वास्तविक संख्या को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई।

कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों में ड्रोन फोर्स वन एवं वन्यजीव सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ड्रोन फोर्स के जरिये मिले परिणामों के आधार पर सरकार और महकमा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।

झारखंड

निराश करती स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की पिछले दो तिमाही की रिपोर्ट उत्साहजनक नहीं हैं। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित स्वच्छता के मानकों पर सिर्फ जमशेदपुर खरा उतरा है। शेष शहर खुद को स्वच्छ घोषित करने को लेकर मशक्कत करता ही दिखता है। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) शहर भी स्वच्छता के तय पैमाने के ही एक हिस्सा हैं। चौंकाने वाली बात यह कि केंद्र ने दो अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को ओडीएफ करने की परिकल्पना की थी। इससे इतर, झारखंड ने अपने शहरों को निर्धारित समय से दो वर्ष पहले और पूरे राज्य को एक वर्ष पूर्व ही ओडीएफ घोषित कर दिया। इसके लिए पूरे देश में उसे वाहवाही भी मिली, परंतु ओडीएफ शहर और गांव की परिकल्पना आज भी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। और तो और, राजधानी रांची, जहां पूरी की पूरी सरकार बसती है, वह भी कचरे के ढेर पर बसी है।

वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निपटारे के मामले में देवघर को छोड़कर अन्य किसी भी शहर की स्थिति अच्छी नहीं है। डंपिंग यार्ड के लिए भूमि की अनुपलब्धता जहां शहरों की सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग उठाव आज तक संभव नहीं हो सका है। राज्य का हर व्यक्ति रोजाना औसतन 300 ग्राम कचरे का उत्पादन कर रहा है, परंतु न तो उसकी रिसाइक्लिंग हो रही है और न ही उसके निपटारे की कोई अन्य ठोस व्यवस्था है। बहरहाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतिम चरण का सर्वे शुरू हो चुका है। शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय शहरों की सफाई का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से करा रहा है। संबंधित एजेंसी सफाई का फीडबैक कई स्तरों पर ले रही है। यह सिलसिला 31 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद मंत्रालय सफाई के मामले में झारखंड के शहरों की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट जारी करेगा। स्वच्छता के मानकों पर झारखंड सम्मानजनक स्थिति में रहे, इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर तबका अपने हिस्से की जवाबदेही ईमानदारी से निभाए। यह शहर ही नहीं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्रतीकात्मक

स्वच्छता के मानकों पर झारखंड सम्मानजनक स्थिति में रहे, इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर तबका अपने हिस्से की जवाबदेही ईमानदारी से निभाए।

पंजाब

भारी पड़ती प्रशासन की असफलता

पंजाब सरकार ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइनीज डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस डोर से हो रहे हादसों को देखते हुए यह फैसला उचित भी है, लेकिन इसे जागरूकता की कमी कहें या फिर सरकारी स्तर पर इच्छाशक्ति की कमी कि पंजाब में प्रतिबंध होने के बावजूद पतंगों को उड़ाने के लिए चाइनीज डोर इस्तेमाल हो रही हैं। चाइनीज डोर की चपेट में आने से बीते पंद्रह दिनों में कम से कम छह लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। लुधियाना में तो एक युवक के चेहरे पर बारह टांके लगाने पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जानलेवा साबित हो रही चाइनीज डोर को दुकानदार बेच रहे हैं। सवाल उठता है कि यदि सरकार ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है तो यह बाजारों में पहुंचती कैसे है और बिक कैसे रही है?

ऐसा अकसर देखने में आता है कि सरकार आदेश जारी कर देती है, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी इसे लागू करवाने की होती है वे लापरवाह बने रहते हैं। अधिकारियों का यह रवैया कतई उचित नहीं है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब यह डोर दोगुने दाम पर बेची जा रही है। दुकानदारों ने अपने एजेंट बना रखे हैं और कोड वर्ड के जरिये डील कर रहे हैं। खुद का बचाव करने के लिए इस काम में बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यदि इस अवैध कारोबार को नहीं रोक पा रहे हैं तो इससे उनकी नाकामी ही साबित होती है। अधिकारी दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में चाहे राजमार्ग हों या फिर बाजार, चाइनीज डोर लेकर लोग जा रहे हैं और पुलिस रोक नहीं रही है। नाकों पर या तो चेकिंग ही नहीं हो रही है या फिर चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति हो रही है।

सवाल उठता है कि यदि पंजाब की सरकार ने चाइनीज डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है तो यह बाजारों में पहुंचती कैसे है और बिक कैसे रही है?

प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज डोर की बिक्री जारी रहना चिंताजनक है। प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तीखी, मजबूत और मेटल कोटेड होने के कारण अच्छी विद्युत सुचालक चाइनीज डोर के कारण लोग कटते तो हैं ही साथ ही यह बिजली की तारों के साथ छू जाने पर झटका भी देती है। इस डोर पर तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है और सरकार ने भी इस डोर को कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रतिबंधित किया था, परंतु हैरानी की बात है कि इसका चलन बंद नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि वह इस जानलेवा डोर को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की तरफ गंभीरता दिखाए। सिर्फ इसे बेचने वालों पर ही नहीं बल्कि इसका प्रयोग करने वालों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई करे।

कुछ जिलों में बेशक पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की है, लेकिन सरकार जब तक अधिकारियों की जवाबदेही नहीं तय करेगी तब तक इसकी बिक्री रोक पाना मुश्किल है। इसके साथ ही आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस जानलेवा डोर को खरीदने से परहेज करना चाहिए।

उत्तराखंड में बहुरेंगे पलायन से खाली होते गांवों के दिन

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड में पलायन से खाली होते गांवों और रसातल में जाती खेती-किसानी के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। इस कड़ी में 'आइ एम ए विलेज' योजना को सरकार अब धरातल पर उतारने जा रही है। इसमें राज्य के सभी 95 ब्लाकों में एक-एक गांव को कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिहाज से मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए चयनित गांवों को एक से डेढ़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

प्रदेश में घटती कृषि विकास दर और कृषि भूमि के बंजर में तब्दील होने की बढ़ती रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। खुद सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। एक दशक पहले राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी सात फीसद थी, जो घटकर 4.67 फीसद पर आ गई है। 72 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर में तब्दील हुई है। हालांकि, गैर सरकारी आंकड़े ऐसी भूमि का रकबा एक लाख हेक्टेयर बताते हैं। कारणों की पड़ताल हुई तो पता चला कि इसकी मुख्य वजह गांवों से निरंतर हो रहा पलायन है।

इस सबके मद्देनजर खेती-किसानी को संबल देने और किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि को लाभकारी बनाते हुए इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के दृष्टिगत सरकार अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके लिए लाई जा रही है आइ एम ए विलेज योजना, जिसके मसौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इसे जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी है।

प्रतीकात्मक

योजना के मुख्य बिंदु

- पांच साल की योजना में प्रतिवर्ष हर ब्लाक का एक-एक गांव बनेगा मॉडल
- चयनित गांव को बजट से अतिरिक्त मिलेगी एक से डेढ़ करोड़ की राशि
- कृषि व उसके क्षेत्रों को जोड़कर विकसित होंगी कृषि सुविधाएं
- खेती को वन्यजीवों से बचाने को वन सीमा पर होगी सोलर पावर फैंसिंग
- सिंचाई प्रणाली, फार्मर्स मशीनरी बैंक, कलेक्शन कक्ष, शार्टिंग-ग्रेडिंग प्लांट पर फोकस
- पशुपालन, मुर्गी, मछली व मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों पर जोर
- गांवों में उत्पादित कृषि उत्पादों के विपणन की अलग से व्यवस्था
- प्रत्येक चयनित गांव में कार्यों की निगरानी को विशेष प्रकोष्ठ

गांवों को मॉडल के तौर पर विकसित करने को आइ एम ए विलेज योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इसकी लांचिंग की तैयारी है। इस सिलसिले में इसी सप्ताह विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।

- सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री उत्तराखंड

चैट बॉट 'अर्जुन' देगा विद्यार्थियों के सवालों का जवाब

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ : डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के ढाई लाख विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। डिग्री, मार्कशीट और रिजल्ट के स्टेटस के लिए न तो उन्हें कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही एकेटीयू का। विद्यार्थी विवि की वेबसाइट पर जाकर चैट बॉट पर इन सबसे संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। चैट बॉट का नाम अर्जुन है, जो सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लांच किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में इसे एकेटीयू का बड़ा कदम माना जा रहा है।

एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि विवि के छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट में करेक्शन, ऑनलाइन डिग्री व मार्कशीट भी ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा नाम में त्रुटि होने पर उसे भी सही करवा सकते हैं।

प्रो. पाठक ने बताया कि जो छात्र विवि में दाखिला लेना चाह रहे हैं, वह चैट बॉट पर विवि से संबद्ध कॉलेजों में संचालित कोर्सों के बारे में भी चंद जानकारी हासिल कर सकेंगे। चैट बॉट फिलहाल अंग्रेजी भाषा में ही शुरू होगा। जल्द ही अन्य भाषाएं भी शामिल होंगी।

चैट बॉट पर बात करने के लिए विद्यार्थियों को एकेटीयू के वेबपेज पर जाना होगा। वेब पेज पर जाते ही बाईं ओर नीचे की तरह चैट बॉट उपलब्ध होगा। इसके अलावा इसका लिंक छात्रों को ईआरपी पोर्टल और वन व्यू पर भी मिलेगा। अभी इस चैट बॉक्स को बीटा वर्जन में लांच किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेस के तहत अगले छह महीने में इसे लर्निंग फेज में रखा जाएगा। भविष्य में यह छात्रों की सभी समस्याएं खुद हल करेगा।

धनबाद में फर्जी कागज पर बेच दिया 2900 करोड़ रुपये का कोयला

बलवंत कुमार, धनबाद

धनबाद में कोयले की काली कमाई करने वालों ने करीब 2900 करोड़ रुपये का कोयला बेचकर सरकार को सीधे तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगा दिया। कोयला बेचने के बाद न तो जीएसटी अदा किया न ही सेस।

दरअसल, कोयला की खरीद बिक्री पर राज्य वाणिज्य कर विभाग पांच फीसद जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) और प्रति टन चार सौ रुपये सेस की वसूली करता है। जीएसटी संयुक्त आयुक्त शिव सहाय सिंह के अनुसार करीब 145 करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी पकड़ में आई है। यह फर्जी कंपनियों के माध्यम से कोयला बेच कर की गई है। यदि कंपनियां फर्जी थीं, तो कोयला भी चोरी का ही था। चोरी हुई पांच फीसद जीएसटी की मूल राशि 2900 करोड़ रुपये होती है। इस पर 165 करोड़ रुपये सेस का है। यह चोरी कागजातों में हेरफेर कर की गई है।

ऐसे हुआ खेल : कंपनियां जब कोयला खरीदती हैं, तो पांच फीसद जीएसटी का भुगतान करती हैं। यह कोयला दूसरे को बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला जीएसटी कोयला बेचने वाली कंपनी अपने पास रख लेती है।

जीएसटी के प्रपत्र से जानकारी विभाग को दी जाती है। जीएसटी चोरी करने के लिए कोयले की खरीद बिक्री दोनों फर्जी कंपनियों के नाम से किया गया। ऐसे में ना तो खरीदने और न ही बेचने के समय जीएसटी का भुगतान हुआ।

न सेस दिया, न जीएसटी : धनबाद फ्यूल के संचालक योगेंद्र सिंह ने तीन बार में कुल 2.43 करोड़ रुपये का कोयला बेचा। पांच फीसद जीएसटी और प्रति टन 400 रुपये सेस की दर से वाणिज्य कर विभाग को भुगतान किया जाता है।

योगेंद्र सिंह ने इन दोनों राशि का भुगतान नहीं किया। विभाग ने जब कर चोरी और सेस का आकलन किया, तो करीब 26 लाख रुपये की चोरी उजागर हुई।

प्रतीकात्मक

- 19 फर्जी कंपनियों ने खेला जीएसटी चोरी का खेल
- कोयले पर लगता है पांच फीसद जीएसटी और प्रति टन चार सौ रुपये सेस
- फर्जीवाड़ा कर बेचा गया कोयला, जीएसटी के 310 करोड़ डकारे

फर्जी कंपनियों ने 300 करोड़ रुपये से ऊपर जीएसटी की चोरी की है। जांच जारी है। मामला सामने आने के साथ प्राथमिकी दर्ज हो रही है।

-शिव सहाय सिंह, संयुक्त आयुक्त, राज्य जीएसटी, धनबाद

इन 17 कंपनियों पर जीएसटी चोरी की प्राथमिकी

मां गायत्री इंटरप्राइजेज, मां शांति ट्रेडिंग कंपनी, जगत जननी इंटरप्राइजेज, मां भवानी इंटरप्राइजेज, शर्मा एंड संस, आरके इंटरप्राइजेज, राय इंटरप्राइजेज, विकास कोल एजेंसी, राजन कोल ट्रेडिंग, शिव शंकर कोक सप्लायर, शर्मा इंटरप्राइजेज, जानकी कोल ट्रेडिंग, श्री राम कोल ट्रेडिंग, बालाजी इंटरप्राइजेज, सिन्हा इंटरप्राइजेज, पूर्वा इंटरप्राइजेज, भूतनाथ इंटरप्राइजेज।

नहीं दिए जीएसटी मद के 33.30 लाख रुपये

शर्मा एंड संस और आरके इंटरप्राइजेज ने भी कोयला बेचा और जीएसटी की चोरी की। दोनों ने रिटर्न फाइल भी नहीं किया। जांच के दौरान इन दोनों कंपनियों का कोई सुराग तक नहीं मिला। शर्मा एंड संस के संचालक मनोज पांडेय ने 3 .97 लाख और आरके इंटरप्राइजेज के संचालक रवि कुमार ने 3 .7 करोड़ का कारोबार किया था। कुल 33 .30 लाख रुपये जीएसटी की चोरी की। वहीं, झरिया के धर्मशाला रोड की बीएस इंटरप्राइजेज कंपनी का 30 मई 2019 को जीएसटी में विनय कुमार शर्मा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया। जून व जुलाई 2019 में मात्र दो माह में ई-वे बिल (परमिट) निकाल कर 14 .95 करोड़ का कोयला बेचा। कंपनी ने टैक्स नहीं दिया।

उधार की बिजली से रोशन हो रहा हिमाचल

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला : विद्युत राज्य हिमाचल के घरों में उजाला चार राज्यों की उधार यानी बैंकिंग आधार पर ली जा रही बिजली से हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बिजली इन दिनों बैंकिंग पर लेकर प्रदेश के लोगों की जरूरत पूरी की जा रही है। प्रदेश में इन दिनों 310 लाख यूनिट बिजली की प्रतिदिन जरूरत है। सर्दी की वजह से प्रदेश में साठ फीसद तक बिजली उत्पादन गिर गया है। ऐसे में प्रतिदिन केवल अस्सी लाख यूनिट ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में केंद्र से मिलने वाले शेयर और प्रदेश सरकार को विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से मिल रही बिजली और बैंकिंग आधार से काम चलाना पड़ रहा है। प्रदेश के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 161 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली बैंकिग से ली जा रही है। प्रदेश में छोटी विद्युत परियोजनाओं की क्षमता 90 लाख यूनिट प्रतिदिन है।

बैंकिंग पर ली जा रही बिजली (लाख यूनिट प्रतिदिन)

दिल्ली	91
हरियाणा	30
उत्तर प्रदेश	20
पश्चिम बंगाल	20
कुल	161

प्रदेश में लोगों की बिजली की मांग पूरा करने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। बैंकिंग पर अन्य राज्यों से बिजली ली जा रही है, ताकि लोगों की बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकें। सर्दियों में प्रदेश में बिजली उत्पादन कम हो जाता है।

- जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री

पधारो म्हारे....जोधपुर!

द न्यूयॉर्क टाइम्स की वर्ष 2020 की सूची में पर्यटन के लिहाज से पूरे देश से मात्र एक शहर सूर्यनगरी ने बनाई जगह

रंजन दवे, जोधपुर : **द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार वर्ष 2020 में पर्यटन के लिहाज से जोधपुर शहर विश्व के श्रेष्ठ स्थानों में शुमार है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि विभिन्न मापदंडों और पर्यटन के लिहाज से समूचे विश्व के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में पूरे देश से केवल जोधपुर को ही स्थान मिला है।**

जोधपुर को 15वां स्थान

द न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से विश्व के 52 श्रेष्ठ स्थानों को बताया गया है, जिसमें से सूर्यनगरी को 15 वां स्थान मिला है, जो पर्यटन के किसी खिताब से कम नहीं है। इसके साथ ही अब पर्यटन से जुड़े लोगों में आगामी सीजन के बढ़िया होने की उम्मीद भी जगी है।

बची है कला-संस्कृति

इस सूची में शामिल जोधपुर के बारे में लिखा गया है कि जब भारत के कई शहर टेक इंडस्ट्रीज द्वारा बदल दिए गए हैं, ऐसे में इन सबके बीच जोधपुर ने अपने ठेठ देसी अंदाज, कला और संस्कृति को बचाए रखा है। यहां की संस्कृति अब भी जीवंत है। यह अपनी परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, मान मनुहार, खान पान ,रहन सहन व जीवन यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को अब भी सजोए हुए है। पत्थरों से बने मकानों पर नीला रंग, इसे अन्य शहरों से अलग तो करता ही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है।

कई दर्शनीय स्थल

इसके साथ ही यहां के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा, राव जोधा प्राकृतिक उद्यान, मंडोर गार्डन सहित तंग गलियों में बनी बसावट, प्राचीन जल स्रोत, कुएं, बावड़ियां आज भी शहर की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं।

पर्यटकों की संख्या में आई कमी

विगत वर्षों से तुलना करें तो जोधपुर में घरेलू की तुलना में विदेशी सैलानियों की संख्या अधिक है। पर्यटन विभाग के अनुसार, 2018 में अगस्त से नवंबर तक 5,12,664 घरेलू सैलानी आए थे। 2019 में इसी अवधि के दौरान सैलानियों की संख्या 10 फीसद गिरी और 4,62,030 पर आ गई। उम्मीद है कि लोग जोधपुर के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे और 2020 के अपने ट्रेवल प्लान में शामिल करेंगे। जिससे यहां के होटल, रेस्टोरेंट और शोरूम व्यवसायियों को ज्यादा पर्यटकों की मेजबानी का मौका मिलेगा। वहीं हस्तशिल्प के सामान निर्माताओं के साथ गाइड, ट्रेवल एजेंट और लोक कलाकारों को फायदा होगा।

ये है विश्व की टॉप-15 डेस्टिनेशंस

रैंक	डेस्टिनेशंस	देश
1	वाशिंगटन	अमेरिका
2	ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स	ब्रिटेन
3	रूरेनाबेक्यू	बोलीविया
4	ग्रीनलैंड	ग्रीनलैंड
5	किंबरले रिजन	ऑस्ट्रेलिया
6	पासो रोवल्स	अमेरिका
7	सिसिली	इटली
8	सॉजबर्ग	ऑस्ट्रिया
9	टोक्यो	जापान
10	केसेरिया	इजरायल
11	नेशनल पार्क	चीन
12	लेसोथो	लेसोथो
13	कोलोराडो स्प्रिंग्स	अमेरिका
14	कराकोव	पोलैंड
15	जोधपुर	भारत

पर्यटन व्यवसायियों में जगी आस

विश्व के श्रेष्ठ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जोधपुर के शुमार होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी एक नई आस जगी है। मंदी की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई है कि 2020 में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। जोधपुर रेल,सड़क और वायुमार्ग के जरिये देश के अन्य बड़े शहरों से जुड़ा है।

यह खुशी की बात है, इससे सीजन के अच्छा रहने की उम्मीद है। आम जन भी इस विषय पर भागीदारी निभाते हुए शहर के हेरिटेज को सहेजेंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, जिससे विश्व मानचित्र पर जोधपुर का स्थान और ऊपर उठेगा।

ऋषिराज सिंह जोधा, सचिव, जोधपुर गाइड एसोसिएशन, जोधपुर

जोधपुर के लिए यह गौरव का पल है। समूचे भारत से ब्लूसिटी को विश्व पटल पर स्थान मिला है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जोधपुर लोगों की पसंद बना है। ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए।

राजेश सिंघवी, होटल व्यवसायी, फन वर्ल्ड, जोधपुर

1200 करोड़ से कम कर 600 करोड़ रुपये सरकारी भवनों का बिल करने का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। पटना में सरकारी महकमों में अक्टूबर, 2018 की तुलना में अक्टूबर, 2019 के बिजली बिल में 38.89 प्रतिशत की कमी रिकॉर्ड की गई है।

बंजर भूमि और सूखे हलक के लिए एक आस है बूढ़ा-बूढ़ी बांध

नक्सल प्रभावित देव प्रखंड में ग्रामीणों के स्वावलंबन का प्रमाण है बूढ़ा-बूढ़ी बांध, पेयजल के लिए तरसती आबादी को मिला आसरा

मुकेश कुमार, औरंगाबाद

जल संरक्षण

बेशक नाम बूढ़ा-बूढ़ी बांध है, लेकिन अब यह अपनी रवानगी पर है। इसकी बदौलत आसपास के इलाकों की बंजर भूमि लहलहाने लगी है और सूखे हलक तर हो रहे। यह नक्सल प्रभावित देव प्रखंड के लोगों की मेहनत का नतीजा है, जिसकी तारीफ कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं।

कभी नक्सलियों के उपद्रव के कारण औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड की ओर कोई रुख भी नहीं करता था। उसी कारण विकास कार्य भी ठप पड़े रहे। सिंचाई की समस्या के साथ पेयजल के लिए भी हाहाकार मचा रहता। गर्मियों में पलायन की मजबूरी थी। ऐसे में 40 गांवों के बाशिंदों ने तकदीर बदलने की ठानी। गोकुल सामाजिक संस्था के कर्ता-धर्ता संजय सज्जन का साथ मिला और बांध ने अपना वजूद अख्तियार कर लिया।

03 साल से अधिक समय तक रात-दिन एक कर ग्रामीणों ने बनाया बांध

01 करोड़ रुपये खर्च हुए बांध को बनाने में, जिसमें ग्रामीणों का चंदा 12 लाख

बरवासोई पहाड़ी से बूंद-बूंद पानी नीचे टपकता था। बरसात के दिनों में वह पानी एकधार में तब्दील हो जाता। यही से बांध की परिकल्पना बनी। पहाड़ के पानी के साथ बरसात के बर्बाद होने वाले पानी का संग्रह कर नहर निकालने का फैसला हुआ। सरकार का साथ नहीं मिला तो ग्रामीणों ने खुद ही कमर कस ली।

तीन साल के परिश्रम का प्रतिफल : 40 से अधिक गांवों के 25 हजार हजार लोगों ने तकरीबन तीन साल तक पसीना बहाया। पहाड़ को काट कर बांध बनाया। बगलगीर गांव पर नाम दिया गया बूढ़ा-बूढ़ी बांध। उससे 22 फुट गहरी, 17 फुट चौड़ी व दो किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई। उसे रामरेखा नहर कहते हैं। शुरुआती दौर में प्रतिदिन हजार से अधिक लोगों द्वारा 60 से अधिक दिनों तक सुबह से शाम तक श्रमदान किया गया। उसके बाद सौ लोग अगले दो साल तक दिन-रात खटते रहे।

एक करोड़ रुपये हुए खर्च : बांध के निर्माण में तकरीबन एक करोड़ रुपये खर्च हुए। बालूगंज के मोची शंभू राम की जीवन भर की कमाई लग गई। सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर चर्तुगुण पासवान का अनुभव भी खूब काम आया। प्रति बीघा तीन सौ रुपये के हिसाब से ग्रामीणों ने 12 लाख रुपये चंदा में मिले। शेष धन का बंदोबस्त गोकुल सामाजिक संस्था ने किया।

खेतों के साथ पीने के लिए पानी : आज करीब 70 गांवों को इस बांध से पेयजल सुलभ है। उन गांवों में पहले अप्रैल-मई आते-आते चापाकल सूख जाते थे। आज महज 30 से 40 फीट पर शुद्ध पेयजल मिल रहा। बांध के मार्फत भूजल का स्तर इस कदर बढ़ा है। बांध के निकट बसे दर्जन भर से अधिक गांव के लोग पीने के लिए सीधे पानी लेते हैं।

बरबासोई, बूढ़ा-बूढ़ी, बंधनडीह, बरंडा, रामपुर, बलयर, लिलजी, बरनी और बारा समेत 40 गांवों के किसान सिंचाई कर रहे। तकरीबन सात हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही। उन खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। पानी का इंतजाम हुआ तो किसान पशुधन को भी सहेजने लगे।

> इस बांध को बनाने वाले ग्रामीणों को सलाम। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत इसे और विकसित किया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई गई है। इंजीनियरों की टीम निरीक्षण भी कर चुकी है। अभी राज्य सरकार द्वारा पईन का निर्माण कराया जा रहा है। निकट भविष्य में इस बांध के जरिए पूरे इलाके में हरियाली की योजना है।
> – राहुल रंजन महिवाल, जिलाधिकारी, औरंगाबाद

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में बूढ़ा-बूढ़ी बांध से पानी लेती महिलाएं। जागरण

बाबा दरबार में सुबह 11 बजे तक दरस-परस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के बाद से मध्याह्न भोग आरती तक बाबा के दरस-परस यानी दर्शन और स्पर्श सुविधा मिलेगी। धोती-कुर्ताधारी पुरुष व साड़ी पहनी महिलाएं ही यह सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगी। इससे इतर परिधान में सिर्फ दर्शन की ही सुविधा मिलेगी। श्रीकाशी विद्वत परिषद ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को कुछ ऐसे ही सुझाव दिए हैं। धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री नीलकंठ तिवारी ने विधिक प्रक्रिया पूरी कर जल्द लागू करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, मंदिर में दर्शन-पूजन, पूजा पद्धति और कारिडोर क्षेत्र में मिले विग्रहों व मंदिरों के संयोजन के लिहाज से रविवार को कमिश्नरी सभागार में बैठक बुलाई गई थी। अध्यक्षता करते हुए मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने विद्वतजनों के समक्ष विचार के लिए दोनों प्रश्न रखे। विद्वानों ने एक मत से कहा कि बाबा का स्पर्श-दर्शन मध्याह्न आरती से पहले 11 बजे तक किया जा सकता है। इससे अधिक से अधिक श्रद्धालु स्पर्श-दर्शन कर सकेंगे लेकिन किसी विग्रह को स्पर्श करने के लिए एक प्रकार का वस्त्र तय होना आवश्यक है। इसमें पुरुषों को धोती-कुर्ता व महिलाओं को साड़ी पहनने का नियम बनना चाहिए।

जहां मर्ज, वहीं मार करेगा नैनो कैप्सूल

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

जागरण विशेष

- आइआइटी प्रोफेसरों की खोज, अन्य ऊतक को रखेगा सुरक्षित
- कार्सिनोमा कैंसर, टीबी और अल्जाइमर जैसे रोगों के इलाज में होगा कारगर
- नैनो कैप्सूल को यूएस सेफ्टी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मिली मान्यता

जहां मर्ज, वहीं मार। जितनी जरूरत, दवा की उतनी ही डिलीवरी। न दूसरे ऊतक व अंगों को नुकसान और न ही असंतुलित डोज। यह संभव होगा, नैनो पार्टिकल कैप्सूल से, जिसे आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर और यहां से पोस्ट डॉक्टरेट कर रहीं रिसर्च स्कॉलर ने बनाया है। कार्सिनोमा, टीबी और अल्जाइमर जैसे रोगों में कैप्सूल के प्रयोग का परीक्षण सफल रहा है। अब इसे बाजार में उतारने की तैयारी है। यह 2020 के अंत तक बाजार में होगा। इस नैनो कैप्सूल को यूएस सेफ्टी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मान्यता भी दे दी है।

अभी तक कैंसर में कीमोथेरेपी और टीबी और अल्जाइमर में दवा की सीधी डोज दी जाती है। इनके अपने साइड इफेक्ट हैं। कीमो का असर कैंसर से प्रभावित ऊतक के साथ शरीर के अन्य हिस्से पर होता है। टीबी और अल्जाइमर के इलाज में भी यही दिक्कत है। दवाओं की अधिक मात्रा से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ अन्य दुष्प्रभाव सामने आते थे। ऐसे में दवा केवल प्रभावित ऊतक तक ही पहुंचे, इसके लिए दो साल शोध करने के बाद डॉ. अर्चना रायचूर ने ड्रग डिलीवरी सिस्टम तैयार किया। वह यूनिवर्सिटी ऑफ टोकियो, जापान से बायो नैनो साइंसेज में पीएचडी करने के बाद आइआइटी कानपुर से पोस्ट डॉक्टरेट कर रहीं हैं। उनके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ. प्रणव जोशी ने कैप्सूल की डिजाइन, वर्किंग और मैटीरियल पर शोध किया। यह नैनो पार्टिकल कैप्सूल दवाओं को मर्ज वाले स्थान तक ले जाएगा। मर्ज के स्थान पर पहुंचने तक दवाओं का प्रभाव बना रहेगा। शरीर के अन्य मालीक्यूल या एंजाइम से प्रभावित नहीं होगा।

हर उम्र के लिए सुरक्षित : डॉ. रायचूर के अनुसार, अलग-अलग मैटीरियल के कैप्सूल शरीर के आम ऊतकों को प्रभावित करते हैं। यह कैप्सूल ऐसे बायो पॉलीमर से बना है, जो शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जरूरत के अनुसार छोटे से छोटा डोज डिलीवर कर सकता है। बच्चे-बुजुर्ग, सभी के लिए सुरक्षित है। इस कैप्सूल से जटिल रोगों का इलाज करना आसान होगा। चूंकि इन रोगों के इलाज में डोज बढ़ानी पड़ती है, इसलिए दुष्प्रभाव भी अधिक होता है, जबकि यह कैप्सूल दवा को केवल मर्ज वाले स्थान पर ही छोड़ेगा।

डॉ. अर्चना रायचूर (फाइल फोटो)। जागरण

डॉ. प्रणव जोशी। जागरण

कार्सिनोमा कैंसर : यह त्वचा, होंठ, मुंह, मूत्राशय, फेफड़े व गर्भाशय ग्रीवा सहित कई अंगों में हो सकता है। यह शल्की इपिथेलियम का घातक ट्यूमर है। इलाज में हाई डोज की दवाएं और कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी से जुड़े साइड इफेक्ट अधिक होते हैं।

अल्जाइमर : भूलने की बीमारी है। याददाश्त कम होना, असमंजस में रहना, बोलने में दिक्कत आना इसके लक्षण हैं।

ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) : टीबी बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। प्रारंभिक अवस्था में न रोके जाने पर जानलेवा हो सकता है। इसे फेफड़े का रोग मानते हैं। खून के साथ बैक्टीरिया शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। इलाज के दौरान दवाओं का साइड इफेक्ट आमतौर पर घातक नहीं होता लेकिन भूख में कमी, मिचली और त्वचा पर चकत्ते पड़ने की समस्या आ सकती है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

सावधान ! एक लिंक आपको कर सकता है कंगाल

किस्त एक ▸ स्कीमर से कार्ड क्लोनिंग, स्वैपिंग व शोल्डर सर्फिंग के बाद अब क्यूआर कोड स्कैनिंग से खातों में सेंध

साइबर अपराधी बदल रहे ठगी का पैटर्न, जांच एजेंसियां भी हैरान

ज्ञान विहारी मिश्र, लखनऊ

सचेत हो जाइए। साइबर अपराधियों ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा में सेंध लगा रखी है। बैंकों की पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली जालसाजों के सामने बौनी साबित हो रही है। हर रोज लोगों के खातों से लाखों रुपये निकल रहे हैं। एक अंजान लिंक पर क्लिक करने से आपके खाते में जमा रकम चंद मिनट में पार हो सकती है।

दरअसल, साइबर अपराधियों ने अब ठगी का पैटर्न बदल दिया है। स्कीमर लगाकर कार्ड क्लोनिंग के जरिए रकम पार करने के बाद जालसाजों ने नया तरीका इजाद किया है। ठग अब प्रमुख कंपनियों के नाम से मिलती-जुलती वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके निशाने पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग सर्वाधिक हैं। जालसाज अब क्यू आर कोड (क्विक रिस्पांस कोड) लिंक के जरिए बैंक खाते हैक करने लगे हैं। ठग ओएलएक्स और फ्लिपकार्ट समेत अन्य वेबसाइट पर खरीदारी करने वालों को झांसे में ले रहे हैं। इस दौरान वह क्रय-विक्रय की बात फाइनल कर ऑनलाइन पेमेंट की बात कहते हैं। इसके बाद लोगों के वाट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजते हैं। जैसे ही लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं, ठग लोगों के मोबाइल फोन का क्यूआर कोड स्कैन कर खाते में रकम पार कर दे रहे हैं।

बैंककर्मी बनने से क्लोनिंग तक : करीब एक दशक पहले साइबर अपराध अचानक सामने आए थे। पिछले पांच साल में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। पहले खुद को बैंककर्मी बताकर लोगों से खाते की जानकारी लेकर ठगी का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद ठगों ने कार्ड क्लोनिंग शुरू की। अब तो एटीएम कार्ड लोगों की जेब में रहता है और रकम निकाल ली जाती है।

एक्सपर्ट की सलाह : एसटीएफ के एडिशनल एसपी व साइबर विशेषज्ञ विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर जिस लिंक के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसे न खोलें। बैंक की ओर से कभी भी फोन पर खाते की डिटेल नहीं मांगी जाती है।

वाट्सएप को बनाया हथियार

साइबर अपराधी सामान्य कॉल की जगह वाट्सएप कॉल करते हैं। लोगों का भरोसा जीतने के लिए खुद को सैन्यकर्मी होने का झांसा देते हैं। वह प्रोफाइल पर सेना की फोटो भी लगाते हैं। ठगी के बाद जालसाज पीड़ित का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं।

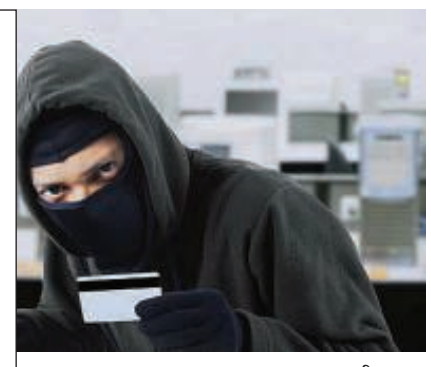

प्रतीकात्मक

ऐसे होता कार्ड का डाटा चोरी

स्कीमर

ठग स्कीमर (डाटा चोरी करने की डिवाइस) का इस्तेमाल एटीएम के कार्ड रीडर स्लॉट में लगाकर डाटा चोरी में करते हैं।

फर्जी कीबोर्ड

एटीएम के कीबोर्ड पर साइबर अपराधी फर्जी कीबोर्ड चिपका देते हैं, जिस पर कार्ड की सारी जानकारी चस्पा हो जाती है।

हिडेन कैमरा

जालसाज एटीएम में हिडेन कैमरे लगाते हैं। इसके जरिए लोगों के एटीएम कार्ड की जानकारी और पिन कोड चोरी कर लेते हैं।

मर्चेंट/प्वाइंट ऑफ सेल

इससे स्वैपिंग मशीन में एटीएम कार्ड डालने के दौरान ठग मैग्नेटिक स्ट्रिप का प्रयोग कर डाटा चोरी कर लेते हैं।

फिशिंग

फिशिंग के जरिए लोगों को स्पैम ई-मेल कर गोपनीय डाटा चोरी की जाती है।

शोल्डर सर्फिंग

इसके जरिए ठग आपको मदद का झांसा देते हैं और फिर कार्ड बदल लेते हैं।

झारखंड में दो साल में 9704 मजदूरों ने किया काम, सभी अंगूठा छाप

उत्कर्ष पांडेय, लातेहार

- विभाग की ओर से जारी मस्टर रोल में सभी 9704 मजदूरों के हस्ताक्षर के बदले लगा है ठेपा
- आरटीआइ से मिली जानकारी में गड़बड़ी के मिल रहे संकेत, साक्षरता अभियानों पर भी सवाल

झारखंड में आकांक्षी जिले में शामिल लातेहार को शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा कार्य के लिए देश भर में तीसरा स्थान मिला है। इसके बावजूद दो साल तक सामाजिक वानिकी वन प्रक्षेत्र लातेहार में विविध स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को विभाग अंगूठा छाप बता रहा है। इसकी जानकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है।

आरटीआइ कार्यकर्ता रविकांत पासवान ने बताया कि उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दो वर्षों में सामाजिक वानिकी वन प्रक्षेत्र लातेहार में विविध स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या, मस्टर रोल की अभिप्रमाणित कॉपी की मांग की थी। इसके जवाब में विभाग की ओर से पत्र जारी कर बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक सामाजिक वानिकी वन प्रक्षेत्र लातेहार में विविध स्थानों पर किए गए कार्यों में कुल 9704 मजदूरों ने काम किया।

> विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जानकारी सूचना अधिकार के तहत मिले जवाब से हो रही है। सभी मामले को एकत्रित कर इस मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आलाधिकारियों को लिखा जाएगा।
> – रविकांत पासवान, केंद्रीय अध्यक्ष भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच।

विभाग की ओर से रविकांत को मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराई गई है। इससे 9704 मजदूरों के काम करने की बात का पता चला। आश्चर्यजनक बात यह है कि काम करने वाले सभी 9704 मजदूर अंगूठा छाप हैं, उन्हें हस्ताक्षर तक करना नहीं आता। मस्टर रोल में सभी मजदूरों के नाम के साथ अंगूठे (ठेपा) का निशान लगा हुआ है। इसमें सवाल यह उठता है कि क्या मजदूरों के गांवों में साक्षरता की दिशा में इतना भी कार्य नहीं हुआ कि लोग अपना नाम लिखना और पढ़ना जान सकें, जबकि जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा कार्य के लिए देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

परत दर परत उजागर हो रहा मामला

सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल लातेहार में बीते दो वर्षों के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मामला निरंतर उजागर हो रहा है। सूचना अधिकार के तहत किए गए आवेदन के जवाब में विभाग की ओर से मुहैया कराए गए जवाब से चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। दो दिन पूर्व ही बिना लॉग बुक एक साल तक वाहनों के चलने और मजदूरों के नाम फर्जी तरीके से मस्टर रोल में जोड़कर राशि निकाले जाने का मामला उजागर हो चुका है।

भदोही की हैंडटफ्टेड कालीन की मुरीद हुई पूरी दुनिया

जर्मनी में चल रहे डोमोटेक्स कालीन मेले में पीएम मोदी के चित्र वाली कालीन बनाते जौनपुर के बुनकर राममूर्ति, साथ में उनकी कारीगरी देखते जीआइ विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. रजनीकांत व विदेशी कालीन आयातक। फोटो जर्मनी गई टीम द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

कैसर परवेज, भदोही

- राममूर्ति ने जर्मनी में बुनी पीएम मोदी की आकृति वाली कारपेट
- अंतरराष्ट्रीय कारपेट मेले के भारतीय पवेलियन में उमड़े निर्यातक

भदोही के कालीन का डंका अब जर्मनी में बज रहा है। हनोवर सिटी में शुरू हो चुके चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला डोमोटेक्स में अबकी भारतीय कारीगरी ने जमकर रिझाया है। भारतीय पवेलियन में केंद्रीय निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) द्वारा भदोही-मीरजापुर समेत देश के कई प्रांतों की कारीगरी दुनियाभर से आए निर्यातकों को लाइव दिखाई जा रही है।

इसमें जौनपुर-भदोही सीमा पर स्थित पचवल गांव के बुनकर राममूर्ति ने बहुतों को आकर्षित किया है। वह वहां पर हैंडटफ्टेड कारपेट बना रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। जो हर खरीदार को अपनी ओर खींच रही है। कोई इस पल को वीडियो में कैद कर रहा है तो कोई घंटों पवेलियन में बैठकर उनसे उनकी कारीगरी सीखने की कोशिश में लगा हुआ है।

जयपुर-श्रीनगर के भी कारीगर : श्रीनगर के गुलजार गनी और जयपुर के मोहम्मद शरीफ शाह भी डोमोटेक्स में भारत की ओर से अपना हुनर दिखाने पहुंचे हैं। वे भी वहां पर कालीन की कारीगरी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारतीय उत्पादों के प्रति आयातकों में विशेष रुचि देखी जा रही है।

भदोही-मीरजापुर परिक्षेत्र के हैंडटफ्टेड कालीन जहां अबकी खूब पसंद किये जा रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर और जयपुर की सिल्क कालीन ग्राहकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत के देशी हुनर का डंका अब विदेशों में भी खूब बज रहा है।

सीईपीसी उत्पादों ने ध्यान खींचा

सीईपीसी भारतीय परंपरागत लूम और बुनाई उपकरणों का प्रदर्शन मेले में कर रहा है। प्रशासनिक समिति के वरिष्ठ सदस्य उमेश कुमार गुप्ता मुन्ना ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि पीएम की फोटो वाली कालीन के कारण भारतीय पवेलियन के प्रति आयातकों में रुचि बढ़ी है।

बाघ संरक्षण

वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 11 जिलों में बढ़ा बाघों का मूवमेंट, भोपाल के आसपास ही 18 बाघों की हरकत

मप्र में बाघों ने बनाए नए ठिकाने, अब कॉरिडोर की जरूरत

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में बाघों की सुरक्षा और उनकी वंशवृद्धि के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित कॉरिडोर की जरूरत महसूस होने लगी है। वन विभाग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के 11 जिलों में बाघों की आवाजाही बढ़ गई है। इनमें कुछ ऐसे जिले भी हैं, जिनमें पहले कभी बाघ नहीं देखे गए। ऐसे हालात में संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। बाघों के प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है।

भोपाल में चार नए, कुल 18 : टाइगर एस्टीमेशन 2018 के तहत प्रदेश में 526 बाघ हैं। यह आंकड़ा पिछले चार साल में बढ़ा है, क्योंकि वर्ष 2014 की गणना में प्रदेश में 308 बाघ पाए गए थे। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र, कान्हा, बांधवगढ़ एवं पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या पार्कों की क्षमता से ज्यादा हो गई है तो सामान्य वनमंडलों में भी बाघ दिखाई देने लगे हैं। भोपाल में ही चार नए बाघ देखे जा रहे हैं। इन्हें मिलाकर भोपाल के आसपास 18 बाघों का मूवमेंट बताया जा रहा है।

इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डेम के आसपास भी दिखे : ऐसे ही बालाघाट के जंगलों में 40 बाघ बताए जा रहे हैं। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के नजदीकी क्षेत्रों में भी बाघों का मूवमेंट देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में दो साल पहले तक बाघ नहीं थे। इन क्षेत्रों में तीन साल पहले चीतल शिफ्ट किए गए थे।

इन क्षेत्रों में बढ़ा मूवमेंट

देवास: पिछले तीन साल से देवास में भी बाघ देखे जा रहे हैं। जबकि इससे पहले इस क्षेत्र में बाघ नहीं देखे गए।

खंडवा, पन्ना, छतरपुर, दमोह, उमरिया, चित्रकूट, मैहर, सारंगपुर, सतना, रीवा, कटनी, शहडोल, ब्यौहारी और जबलपुर के जंगलों में भी बाघों का मूवमेंट है।

प्रतीकात्मक

> प्रदेश में बाघ बढ़े हैं। इसकी मुख्य वजह बाघ प्रबंधन है। जंगलों में खाने और पानी का प्रबंध किया गया। बाघों की संख्या में वृद्धि इसका परिणाम है। आगे भी बेहतर प्रबंधन की रणनीति बनाई जा रही है।
> – जेएस चौहान, एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, वन विभाग मप्र

...ताकि मानव का सामना न हो

वन्यजीव विशेषज्ञ एके खरे बताते हैं कि जंगलों में संख्या बढ़ने के कारण बाघ बाहर आ रहे हैं तो उनके रास्ते का माहौल भी जंगल जैसा ही हो। दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते में जंगल खड़ा करना होगा। ताकि उनके मूवमेंट के दौरान बाघ-मानव का सामना न हो।

उप्र, छग व महाराष्ट्र में भी जा रहे बाघ

सूत्र बताते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व के पांच बाघ इन दिनों संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं। इनमें से एक बाघ नवंबर-दिसंबर में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की सीमा पर देखा गया। ऐसे ही सीधी के रास्ते बाघ छत्तीसगढ़, पेंच के रास्ते महाराष्ट्र और राजस्थान की सीमा में भी जा रहे हैं।

ऑटो उद्योग ने की मजबूत कदम उठाने की मांग

नई दिल्ली : सुस्ती का सामना कर रही ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से आगामी बजट में आक्रमक कदम उठाने की मांग की है। सेक्टर ने जीएसटी दरों में कटौती, लीथियम आयन बैटरी के आयात में शुल्क छूट जैसी मांगें रखी हैं। इसके अलावा सेक्टर नीतिगत सुधारों की मांग भी कर रहा है। इंडस्ट्री ने सरकार से वाहन के दोबारा पंजीकरण फीस में बढ़ोतरी की गुजारिश की है। इससे पुराने वाहनों के प्रयोग में कमी आएगी और नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। (प्रेट्र)

हमारी नजर में चीन के बाजार में असीमित संभावनाएं हैं। हम उन संभावनाओं का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और चीन के बाजार में विस्तार करते रहेंगे।

– विली बॉल्टर, मुख्य वाणिज्य अधिकारी, इंडिगो

रियल एस्टेट को मंदी से उबारने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 20-25 दिनों में आम बजट को लेकर उद्योग जगत और अर्थविदों से अलग-अलग बैठकें की हैं। उनमें सबसे ज्यादा सुझाव रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर दिए गए हैं। शुक्रवार को नीति आयोग के साथ पीएम मोदी ने जब कैबिनेट के कई सदस्यों के साथ अर्थव्यवस्था पर बैठक की तो उसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा गया। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने का लक्ष्य रियल एस्टेट की स्थिति को ठीक किए बगैर पूरा नहीं होगा और यह स्थिति आगामी वित्त वर्ष में ही ठीक करनी होगी। ऐसे में आगामी बजट का मुख्य फोकस रियल एस्टेट सेक्टर की मंदी दूर करने पर होने की उम्मीद है। नीति आयोग पहले ही इस सेक्टर में नई जान फूंकने संबंधी सुझावों को वित्त मंत्रालय भेज चुका है।

सरकार के बीच उच्च स्तर पर हाल के दिनों में बजट को लेकर हुई बैठक में

प्रतीकात्मक

- पीएम की बजट पूर्व बैठकों में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा लगी गुहार
- कंपनियों के लिए पूंजी की कमी दूर करने व ग्राहकों के लिए मासिक किस्त का बोझ घटाने पर हो रहा है काम

रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर दो दिक्कतों को दूर करने पर सबसे ज्यादा विमर्श हुआ है। इसमें एक है कंपनियों की फंड की कमी दूर करना। दूसरा है ब्याज दरों को और नीचे लाना, ताकि आम ग्राहक को मासिक किस्त के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिले। सिर्फ इन दो समस्याओं को दूर करने से उन ग्राहकों को बाजार में लौटाने में मदद मिल सकती है जो जरूरत होने के बावजूद मकान खरीदने से हिचक रहे हैं। सरकार को उच्च स्तर पर यह जानकारी दी गई है कि इस सेक्टर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्ष 2022 तक सभी को आवास देने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। सभी घरों को बिजली देने के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के बाद सरकार चाहती है कि आवास संबंधी लक्ष्य भी समय से पहले पूरा हो।

आगामी आम बजट के लिए रियल एस्टेट सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में सेक्टर के सबसे बड़े संगठन नारेडको के प्रेसिडेंट डॉ. निरंजन हीरानंदनी का कहना है कि यह अकेला ऐसा सेक्टर है जो सीधे या परोक्ष तौर पर 269 उद्योगों की मांग को प्रभावित करता है। यह सेक्टर जरा सी भी अच्छी हालत में होने पर रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा करता है। केंद्र सरकार पिछले एक वर्ष के दौरान इस सेक्टर को थोड़ी-थोड़ी मदद दे ही रही है। लेकिन अब एक समग्र घोषणा करने की जरूरत है। यह घोषणा ना सिर्फ वर्ष 2022 तक हाउसिंग फॉर आल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए होनी चाहिए बल्कि पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए भी जरूरी होगा।

आइबीबीआइ में संशोधन से पुराने प्रमोटर्स की चालबाजी खत्म

नई दिल्ली, प्रेट्र : इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आइबीबीआइ) के नियमों में संशोधन से पुराने प्रमोटर्स उस कंपनी में पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि नियमों में खामियों का फायदा उठाकर पुराने प्रमोटर्स कंपनी की लिक्विडेशन प्रक्रिया में परोक्ष रुप से भाग लेते हैं।

नए नियमों के मुताबिक सेक्योर्ड क्रेडिटर ऐसी कंपनियों या व्यक्तियों को असेट नहीं बेच सकेंगे, जिन्हें इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया हो। लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन एटॉर्नीज के एक्जीक्यूटिव पार्टनर पुनीतदत्त त्यागी के मुताबिक नियमों में संशोधन का मकसद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के कुछ फैसलों को रद करना है, जिनमें कहा गया है कि इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में पुराने प्रमोटर्स के भाग लेने पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है। संशोधन के जरिये ऐसी खामियों को खत्म किया जाएगा और पुराने प्रमोटर्स रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में अवांछित भागीदारी नहीं कर सकेंगे।

दुबई में बजेगा यूपी के उद्योगों का डंका

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के उद्योगों का डंका अब दुबई में भी बजेगा। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) ने पहल कर दी है। संगठन की ओर से पहली बार अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही दुबई में उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने की तिथि तय कर दी जाएगी। उद्यमी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों में अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें ग्लोबल मार्केट प्रत्यक्ष तौर पर मिल सके।

किसी भी उत्पाद के लिए दुबई एक ग्लोबल मार्केट बन गया है। वहां पर भारतीय उत्पादों की बड़ी मांग है। साथ ही वहां से एक्सपोर्ट भी आसान हो जाता है। इसीलिए दुबई को री-एक्सपोर्ट प्वाइंट भी कहा जा रहा है। पिछले माह ही वाराणसी से हरी मिर्च एक्सपोर्ट की गई थी। अब कपड़ा, बर्तन, फुटवियर, फूड एवं अन्य एग्रो उत्पाद को भी व्यापक पैमाने पर एक्सपोर्ट करने की रणनीति बनाई गई है।

प्रतीकात्मक

- इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की देश के बाहर लगेगी प्रदर्शनी
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव
- ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर दुबई के लिए बनाई योजना

संगठन के कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पिछले दिनों यहां आए इंटरनेशनल अफेयर्स (इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) के चेयरमैन एवं नोएडा के प्रमुख उद्यमी अनुज जैन ने बताया कि दुबई में प्रदर्शनी से यूपी के साथ ही पूरे भारत के उद्योग को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। जैन के अनुसार मंत्रालय की ओर से 10 दिन के भीतर प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी। उम्मीद है कि यह आयोजन अप्रैल तक तय हो जाएगा।

विदेशी बाजार के लिए आइआइए का सचिवालय : कारोबारियों का कहना है कि उत्पाद के एक्सपोर्ट के लिए अक्सर ही उद्यमियों को परेशान होना पड़ता है। इसके लिए विभिन्न देशों के दूतावासों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि इस परेशानी को दूर करने लिए आइआइए नोएडा या नई दिल्ली में खुद का सचिवालय बनाने जा रहा है। सचिवालय के बन जाने के बाद उद्यमियों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चेयरमैन अनुज जैन ने बताया कि सचिवालय स्थापित करने के लिए संगठन के सेंट्रल ऑफिस को प्रस्ताव दे दिया गया है। प्रस्ताव के जल्द पास हो जाने की उम्मीद है।

न्यूज गैलरी

सौर ऊर्जा संगठन ने सरकार को लिखा पत्र

नई दिल्ली : सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी ने छोटी और मझोली कंपनियों को अपनी सोलर पावर निविदाओं के लिए अग्रिम जमा में छूट देने से इन्कार कर दिया है। एनटीपीसी के इस फैसले से नाराज नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया सरकार के पास जा पहुंचा है। संगठन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। सौर ऊर्जा कंपनियों के इस संगठन ने एमएसएमई मंत्री से मांग की है कि वे एनटीपीसी को छोटी और मझोली कंपनियों को निविदाओं में अग्रिम भुगतान में छूट का आदेश दें। संगठन का कहना है कि सरकारी नीति के मुताबिक एनटीपीसी को छोटी एवं मझोली कंपनियों को निविदा प्रक्रिया में छूट देनी चाहिए। (प्रेट्र)

फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य मुश्किल

नई दिल्ली : मशहूर अर्थशास्त्री आर. नागराज ने रविवार को कहा कि वर्ष 2024 तक इकोनॉमी को पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव पर लगभग 350 लाख करोड़ रुपये) का आकार दे पाना करीब-करीब असंभव है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के प्रोफेसर नागराज का कहना था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले वित्त वर्ष से उस समय तक लगातार औसतन नौ प्रतिशत विकास दर की दरकार होगी। लेकिन विकास दर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं लग रहा है। (प्रेट्र)

उप्र में गन्ना खेती का बिगड़ा स्वाद

मांग ▸ किसानों ने गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल, बिजली का 100 रुपये प्रति हॉर्सपावर मांगा

मेरठ-सहारनपुर मंडल की चीनी मिलों पर करीब 1,500 करोड़ रुपये बकाया, ब्याज समेत भुगतान की मांग

संतोष शुक्ल, मेरठ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना खेतीबाड़ी ही नहीं, रोजगार और प्रतिष्ठा का भी विषय माना जाता है। इस क्षेत्र में 59 चीनी मिलें चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले दो साल में कई बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया और रमाला समेत कई अन्य मिलों के क्षमता विस्तार में भी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन किसान के मन में कड़वाहट बनी हुई है। गन्ना बेल्ट में किसानों के लिए चीनी उत्पादन का स्वाद कड़वा रहा है। पिछले साल किसानों ने दिल्ली तक प्रदर्शन कर सरकार को झकझोरा तो हाल में गन्ना जलाकर रोष जताया। किसान गन्ने की दर 450 रुपये प्रति क्विंटल मांग रहे हैं, जबकि सरकार 315 रुपये दे रही है। चीनी मिलों पर करोड़ों रुपये बकाया है। ऐसे में, केंद्रीय बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग तेज हो गई है।

ना चीनी का दाम बढ़ा, ना गन्ने की दर : दशकभर से किसानों का आंदोलन नई दिशा पकड़ रहा है। किसान नेता नरेश टिकैत कहते हैं कि गन्ना किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। एक क्विंटन गन्ने से 12 किलो चीनी निकलती है। बाजार में चीनी का रेट घटने-बढ़ने से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। उनकी मांग है कि चीनी की दर 50 रुपये किलोग्राम के आसपास पर तय कर देना चाहिए। टिकैत कहते हैं कि गन्ने की दर 315 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि उत्पादन की लागत ज्यादा है। अगर यह दर 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए तो खेतीबाड़ी का फायदा है। किसानों के सामने व्यावहारिक समस्याएं भी हैं। गन्ने की खेती में बिजली और फसल के लिए दवा की महंगाई ने मुनाफा कम कर दिया, जबकि इसकी तुलना में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। दावा तो यहां तक है कि बड़ी संख्या में लोगों ने दूसरे फसलों की खेती शुरू कर दी। कई बार त्योहारों में भी किसानों को उनके पैसे नहीं मिल पाए। वहीं, लंबे सम से चीनी मिलों में कैद पड़ी बकाया राशि पर किसानों ने ब्याज की दर बढ़ाने की मांग तेज कर दी है।

...बिजली की दर ने भी दिया झटका : बिजली की दर 185 रुपये प्रति हॉर्सपावर है, जिसे 100 रुपये प्रति हॉर्सपावर करने की मांग तेज हो रही है। राज्य के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा का दावा है कि योगी सरकार ने एक साल में गन्ना किसानों का 35 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया, जो किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। सरकार ने 14 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान का दावा किया था, लेकिन दीवाली, होली और ईद जैसे त्योहारी मौकों पर भी पैसे नहीं मिले। किसान सरकार के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। मेरठ-सहारनपुर मंडल में ही किसानों के करीब 1,500 करोड़ रुपये नहीं मिले। किसान एथनॉल बनाने की योजना से संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें उनकी भागीदारी का सरकार को ध्यान रखना होगा। सल्फरलेस चीनी को लेकर भी किसानों का रवैया यही है।

मैं 100 बीघा में गन्ना की खेती करता हूं। हमारा समय पर भुगतान होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसानों को सस्ती बिजली, खाद व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान होना चाहिए। गन्ना आपूर्ति व भुगतान सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए।

–इरशाद अहमद रिजवी, लावड़

मेरठ-सहारनपुर मंडल में गन्ना किसान और पेराई सत्र 2018-19 के बकाए का हाल

जिला	किसानों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ में)
मेरठ	208721	55.96
बागपत	123239	117.95
गाजियाबाद	24454	131.67
बुलंदशहर	96791	42.15
हापुड़	51593	272.35
सहारनपुर	139504	226.65
मुजफ्फरनगर	230064	213.98
शामली	85455	307.66

गन्ना समय से चीनी मिलों पर चला जाए। जिससे अगली फसल के लिए समय रहते तैयारी पूरी कर ली जाए। सोसायटी से लोन, उपकरणों पर छूट मिलनी चाहिए। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपयुक्त दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें।

–नंदकिशोर, आलमगिरपुर

रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर रोक से उछले भाव

महावीर गोयल, पानीपत

रिफाइंड पाम के आयात पर रोक से इसके भाव उछल गए हैं। 90 रुपये तक बिकने वाले रिफाइंड पाम ऑयल के भाव 95 रुपये तक पहुंच गए हैं। केंद्र ने नीतिगत बदलाव के तहत पिछले सप्ताह बुधवार को रिफाइंड पाम ऑयल आयात पर रोक लगा दी थी। मलेशिया समेत कई देशों से रिफाइंड पाम का आयात होता था। अब सिर्फ कच्चा पाम ऑयल ही आयात किया जा सकेगा। यहां की रिफाइनरी में इसे रिफाइन किया जाएगा। क्षमता का दोहन नहीं कर पाने के कारण अधिकतर रिफाइनरीज बंद होने के कगार पर थीं। पूरे विश्व में भारत सबसे अधिक खाद्य तेलों का आयात करता है। घरेलू रिफाइनरी उद्योग रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की कई वर्षों से मांग कर रहा था। हालांकि प्रतिबंध से सोयाबीन, कॉटन सीड लगाने वाले किसानों को बढ़ावा मिलेगा। किसान अधिक मात्रा में सोयाबीन, कॉटन सीड की खेती करेंगे। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

हरियाणा डिस्ट्रीब्यूटर संघ के प्रधान राकेश अग्रवाल ने बताया कि पांच रुपये किलो तक दाम बढ़ चुके हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मलेशिया ने भारत के खिलाफ बयान दिया था। उस समय मलेशिया से आने वाले रिफाइंड को व्यापारियों ने मंगवाना बंद कर दिया था। तब भाव 68 से 90 रुपये तक पहुंच गए थे। मलेशिया के स्थान पर पांच रुपये महंगा रिफाइंड इंडोनेशिया से मंगवाया जा रहा था।

- तीन दिनों के अंदर पांच रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए भाव
- घरेलू रिफाइनरीज की लचर हालत देखते हुए सरकार ने उठाया था कदम

अकेले पानीपत में 1,000 टन से अधिक रिफाइंड खाद्य तेल की हर माह खपत होती है।

द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के आंकड़ों के मुताबिक सालाना 150 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया जाता है, जिसमें 94 लाख टन हिस्सा पाम ऑयल का हिस्सा होता है। आयातित कुल पाम आयल में 27 लाख टन रिफाइंड पाम ऑयल है। क्रूड पाम ऑयल (सीपीओ) पर 41.25 फीसद आयात शुल्क, जबकि रिफाइंड पाम ऑयल पर 49.50 फीसद है। इसके बावजूद रिफाइंड तेल आयात में लगातार वृद्धि हो रही थी। भारत को सर्वाधिक पाम आयल बेचने वाले देशों में इंडोनेशिया और मलेशिया सबसे आगे हैं। मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल का आयात लगातार बढ़ रहा था जो घरेलू रिफाइनरियों के लिए मुश्किलों का सबब बन गया था।

पड़ोसी एशियाई देशों के साथ कारोबारी संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश में भारत को रिफाइंड पाम ऑयल के आयात से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खासतौर पर नेपाल और बांग्लादेश से घरेलू बाजारों में उपभोक्ता पैकिंग में रिफाइंड पाम ऑयल पहुंच रहा है। घरेलू रिफाइन कंपनियों की परेशानी इससे बढ़ी है।

वित्तीय रफ्तार के लिए मनरेगा पर होगा सरकार का भरोसा

बजट से उम्मीदें

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

ग्रामीण क्षेत्र में मांग को बढ़ाने की कोशिश के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पर खास दरियादिली दिखा सकती हैं। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार गारंटी देने वाली इस योजना के लिए आवंटित राशि में ना सिर्फ अच्छी-खासी वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि माना जा रहा है कि इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कई अहम सुधारों का भी एलान किया जाएगा। बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें यह माना गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए बगैर

- मजदूरी और सामग्री के अनुपात में सुधार की सख्त जरूरत
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से रफ्तार पकड़ेगी जीडीपी विकास दर

अर्थव्यवस्था के विकास की मौजूदा सुस्त दर को तेज नहीं किया जा सकता। मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय क्षमता बढ़ाने का सबसे मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत चलने वाली इस योजना का आवंटन हाल के वर्षों में बढ़ा है, फिर भी लोगों की जेब का वजन कम हुआ है। इस बारे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्राध्यापक प्रो. अश्विनी कुमार का कहना है कि मनरेगा का आवंटन बढ़ने के बावजूद गांव से पलायन गंभीर चिंता का विषय है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मनरेगा में निर्माण के पक्के काम बढ़े हैं, जबकि मजदूरी का हिस्सा घटा है। कुमार ने कहा, 'मजदूरी और सामग्री के बीच के 60 और 40 फीसद के अनुपात में अंतर इसकी प्रमुख वजह है।' उनका कहना है कि पहले इस अनुपात का पालन जिला स्तर पर होता था, जिसे घटाकर ग्राम स्तर पर कर दिया गया है। योजना को अपने पुराने रूप में लागू करने की जरूरत है।

योजना में सामग्री और मजदूरी का अनुपात 60 और 40 होता था। हर काम में इस अनुपात का पालन किया जाता था, जिसकी गणना जिला स्तर पर होती थी। लेकिन धीरे-धीरे उसे गांव का स्तर पर ला दिया गया है। इससे मनरेगा में मजदूरी पर कम और सामग्री पर ज्यादा खर्च होने लगा है।

मझोले उद्योगों को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन लाने की मांग

नई दिल्ली, आइएएनएस : मझोले उद्योगों से भेदभाव का आरोप लगाकर इनका प्रशासनिक नियंत्रण बदलने की मांग की जा रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एफआइएसएमई) ने कहा है कि एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत इन उद्योगों के साथ भेदभाव होता है। इसलिए इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिए।

एफआइएसएमई ने वित्त मंत्री को दी गई बजट संबंधी सलाह में मझोले उद्योगों की बेहतरी के उपाय सुझाए हैं। फेडरेशन ने कहा है कि मझोले उद्योगों को नीतिगत स्तर पर पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है। एफआइएसएमई के मुताबिक मझोले उद्योगों को समाजिक खरीद नीति से बाहर रखा गया है। यह लघु और अतिलघु उद्योगों की खरीद में 25 परसेंट हिस्सेदारी रखती है।

खेल इंडस्ट्री के निर्यात में बड़ी गिरावट

जागरण संवाददाता, जालंधर

दुनियाभर को खेल उत्पाद निर्यात करने वाली पंजाब खेल इंडस्ट्री के सकल निर्यात में कमी आई है। हालांकि, कुछ उत्पादों में इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। ज्यादा निर्यात हुए उत्पादों ने इंडस्ट्री को संभाल कर रखा है। यही स्थिति इंडस्ट्री को स्थिर रखे हुए है। स्थिति यह है कि वित्त वर्ष 2018-19 में अप्रैल से सितंबर तक निर्यात 371.72 करोड़ रुपये मूल्य का था, जो चालू वित्त वर्ष की इसी अवधि में घटकर 320.76 करोड़ रुपये मूल्य का रह गया।

उद्योग के जानकारों का कहना है कि निर्यात कम होने का कारण केंद्र सरकार की ओर से कम इनसेंटिव मिलना है। निर्यातकों का कहना है कि इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के सीएओ मेंबर अजय महाजन ने कहा कि निर्यात कम होने का कारण सरकार की ओर से

प्रतीकात्मक

- ड्रॉ बैक ड्यूटी कम किए जाने से पड़ी उद्योगपतियों पर मार
- क्रिकेट बैट का निर्यात बढ़ा, लेकिन नहीं के बराबर मिल रही सब्सिडी

एक्सपोर्ट्स के इनसेंटिव में भारी कटौती करना है। इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए। वहीं, नोवा फिटनेस के एमडी सुमित शर्मा ने कहा कि निर्यात कम होने का कारण ड्रॉ बैक ड्यूटी में कटौती करना है। काउंसिल की ओर से लगने वाले स्पोर्ट्स फेयर में सब्सिडी कम मिलना भी अहम कारण है। चीन व ताइवान के उत्पाद ने इंडस्ट्री के कारोबार को प्रभावित किया है।

निर्यात कम होने के तीन कारण

- केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली ड्रॉ बैक ड्यूटी (इन्सेंटिव) कम होना।
- केंद्र सरकार प्रोडक्ट उत्पाद इनसेंटिव बंद करने जा रही है।
- खेल उत्पादों को सब्सिडी न मिलना।

कुछ वस्तुओं में इसलिए बढ़ा

- यूरोपीय देशों में खेले जाने वाले फुटबॉल के चलते निर्यात बढ़ा
- इस वर्ष होने वाले टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप को लेकर बैट इक्विपमेंट की मांग बढ़ी
- एशियन देशों में क्रिकेट का बोलबाला

संकेत

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे दिग्गजों के तिमाही नतीजे प्रस्तावित, इस सप्ताह निवेशकों को खुदरा और थोक महंगाई दर के आंकड़ों का इंतजार, विदेशी घटनाक्रमों का भी रहेगा दबाव

बाजार को कुछ तिमाही नतीजों और कुछ विदेशी घटनाक्रमों से उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह अमेरिका-ईरान तनातनी के साए में सहमे रहे शेयर बाजारों का मनोबल इस सप्ताह थोड़ा ऊंचा रहने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि इस सप्ताह आरआइएल, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंडसइंड बैंक जैसे दिग्गजों के सितंबर-दिसंबर, 2019 तिमाही के नतीजे आने हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन में इसी सप्ताह कारोबारी वार्ता पर पहले चरण की सौदेबाजी पर हस्ताक्षर होने हैं। ऐसे में विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस सप्ताह शेयर बाजारों का मूड सकारात्मक रहने वाला है।

बीएसई के 30 शेयरों वाले प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स ने पिछले सप्ताह सहमे होने के बावजूद 135.11 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की थी। ट्रेडिंगबेल्स के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट संतोष मीणा मानते हैं कि बजट-पूर्व घटनाक्रमों और कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर इस सप्ताह शेयर बाजारों के मूड का दारोमदार टिका रहेगा। इसके अलावा इन्फोसिस के शेयरों में सकारात्मक बदलाव दिख सकता है। इसके अलावा सोमवार को खुदरा और मंगलवार को थोक महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। जानकारों का कहना है कि बाजार इन दोनों बड़े आंकड़ों पर सधी प्रतिक्रिया दे सकता है।

इन्फोसिस के शेयरों में संभावित सकारात्मक बदलाव की दो वड़ी वजहें हैं। पहली यह कि कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जाहिर किए। इसके मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा करीब 24 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के शेयरों में सकारात्मक बदलाव की दूसरी बड़ी वजह यह है कि उसकी ऑडिट कमेटी ने प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी इन्फोसिस ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को कहा था कि उसकी ऑडिट कमेटी ने कंपनी के शीर्ष प्रबंधन पर व्हिसलब्लोअर्स द्वारा लगाए आरोपों की जांच पूरी कर ली है। ऑडिट कमेटी ने आरोपों को निराधार पाया है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा का भी कहना था कि इस सप्ताह सोमवार को बाजार खुलते ही निवेशक पहली प्रतिक्रिया इन्फोसिस पर ही दे सकते हैं। हालांकि चुनिंदा सेक्टर के शेयर कुछ विशिष्ट घरेलू और विदेशी अनिश्चितताओं के चलते दबाव में या उछाल में दिख सकते हैं। जहां तक विदेशी संकेतों का सवाल है, तो अमेरिका और ईरान की तनातनी में कमी आती दिख रही है। अब निवेशकों का फोकस फिर से अमेरिका-चीन ट्रेड वार पर चला गया है, जहां दोनों देश इसी सप्ताह पहले चरण के कारोबारी सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले हैं।

प्रतीकात्मक

एफपीआइ ने निकाले 2,415 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस महीने अब तक एफपीआइ ने भारतीय पूंजी बाजारों से 2,415 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। पश्चिम एशिया के तनाव से चिंतित विदेशी निवेशकों ने पिछले कुछ दिनों में काफी सतर्कता दिखाई है। डिपॉजिटरी से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 10 जनवरी तक एफपीआइ ने इक्विटी में कुल 777 करोड़ रुपये का निवेश किया और डेट सेग्मेंट से 3,192.7 करोड़ रुपये निकाल लिए। इस तरह से समीक्षाधीन अवधि में इन निवेशकों ने पूंजी बाजारों से 2,415.7 करोड़ रुपये निकाले। पिछले चार महीनों से एफपीआइ लगातार शुद्ध खरीदार बने हुए थे। लेकिन इस महीने अब तक इन निवेशकों ने घरेलू पूंजी बाजारों से निवेश वापस खींचा है। जानकारों के मुताबिक ईरान-अमेरिका में नए सिरे से तनाव बढ़ने से विदेशी निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ। भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। इससे विदेशी निवेशक खरीदारी करने से बचते नजर आए।

सात कंपनियों का एम-कैप 32 हजार करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों के एम-कैप में पिछले सप्ताह 32,020.12 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इस दौरान एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के बाजार पूंजीकरण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा टीसीएस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचयूएल, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी ब्लूचिप कंपनियों के एम-कैप में बढोतरी दर्ज की गई। समीक्षाधीन अवधि में एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 8,270.31 करोड़ रुपये बढ़कर 7,02,812.11 करोड़ पर पहुंच गया। आरआइएल के एम-कैप में 6,624.47 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। पिछले सप्ताह के आखिर में यह 9,81,118.53 करोड़ रुपये रहा। इन्फोसिस का एम-कैप 3,336.45 करोड़ रुपये गिरकर 3,14,393.82 करोड़ रुपये पर स्थिर हुआ। इस दौरान एसबीआइ और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में भी गिरावट देखी गई।

852 सऊदी सैनिक अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे हैं पेंटागन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत। यह संख्या 153 देशों के प्रशिक्षणरत 5181 सैनिकों का 16 फीसद है।

महारानी ने बुलाई शाही परिवार की आपात बैठक

लंदन, एजेंसियां : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने शाही परिवार की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में शाही भूमिकाओं से खुद को अलग करने वाले प्रिंस हैरी को भी भविष्य की उनकी योजनाओं पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। सोमवार को होने वाली इस बैठक में हैरी के पिता व राज सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और उनके बड़े भाई प्रिंस विलियम भी उपस्थित रहेंगे।

प्रिंस हैरी और उनकी अमेरिकी पत्नी मेगन ने पिछले बुधवार को यह एलान कर शाही परिवार को हैरान कर दिया था कि वह शाही भूमिकाओं से अलग होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। हैरी और मेगन की मई, 2018 में शादी हुई थी। पिछले साल मई में उनकी पहली संतान आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर का जन्म हुआ था।

बकिंघम पैलेस के सूत्रों के अनुसार, यह आपात बैठक पूर्वी इंग्लैंड स्थित नोफोर्क काउंटी की सैंडरिंघम स्टेट में होगी। कनाडा में अपने बच्चे आर्ची के पास रह रहीं पूर्व अमेरिकी अभिनेत्री मेगन फोन के जरिये इस बातचीत में मौजूद रहेंगी। ब्रिटिश राजपरिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हैरी और मेगन ने शाही भूमिकाओं से खुद को अलग करने की घोषणा से पहले ना तो 93 वर्षीय महारानी से सलाह ली और ना ही शाही परिवार के किसी सदस्य से कोई बात की। उनके इस कदम से शाही परिवार के कई सदस्य आहत हैं।

प्रिंस हैरी और डचेज ऑफ सक्सेस मेगन मर्केल।

- शाही भूमिकाओं से खुद को अलग करने वाले प्रिंस हैरी भी होंगे शामिल
- पिछले सप्ताह हैरी और उनकी पत्नी ने किया था एलान
- फोन के जरिये इस बातचीत का हिस्सा बनेंगी मेगन

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। दोनों फाइल/रायटर

अफगानिस्तान में बम धमाके में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शनिवार को बम धमाके में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में तैनात नाटो सेना की संयुक्त कमान ने बताया कि कंधार के बाहरी इलाके में स्थित एयरबेस के पास अमेरिकी सैनिकों का वाहन आइईडी की चपेट में आ गया। इस धमाके में दो अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। अमेरिकी सेना ने अभी इस धमाके में जान गंवाने वाले सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

आतंकी संगठन तालिबान ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि सड़क किनारे यह आइईडी तालिबान ने लगाया था। अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिशों के बीच अफगान और अमेरिकी सेना पर तालिबान के हमले जारी हैं। हाल के महीनों में अफगानिस्तान में संयुक्त सैन्य कार्रवाई में तालिबानी आतंकियों को बड़ा नुकसान हुआ है।

जीत के बाद अमेरिकी राजनयिक से मिलीं ताइवान की राष्ट्रपति

- साई इंग-वेन ने कहा-वैश्विक मुद्दों पर संबंधों को रखेंगे मजबूत

ताइपे, एपी : ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने चुनाव जीतने के बाद यहां अमेरिकी राजनयिक विलियम ब्रेंट क्रिस्टेंसेन से मुलाकात की। ताइवान में अमेरिकी इंस्टीट्यूट के निदेशक क्रिस्टेंसेन ने उन्हें जीत की बधाई दी जबकि साई ने समर्थन देने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया।

साई ने इस मुलाकात के दौरान कहा, ताइवान और अमेरिका की भागीदारी द्विपक्षीय स्तर से बढ़कर वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। भविष्य में हम वैश्विक मुद्दों पर अपने संबंधों को मजबूत करने का काम जारी रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने भाषण में साई ने चीन से बिना पूर्व शर्त के वार्ता फिर शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'आज मैं बीजिंग के अधिकारियों को फिर याद दिलाना चाहती हूं कि शांति, समता, लोकतंत्र और संवाद स्थिरता की कुंजी है। बीजिंग के अधिकारी इस बात को जान लें कि लोकतांत्रिक ताइवान और उसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार कभी खतरों को स्वीकार नहीं करेगी।'

आर्थिक मंदी और हांगकांग में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच साई की जीत चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए झटका मानी जा रही है। वर्ष 1949 में गृहयुद्ध के दौरान चीन से अलग होने के बाद से ताइवान ने अपनी अलग पहचान बनाई है लेकिन कभी औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। चीन अब भी 2.3 करोड़ की आबादी वाले ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की धमकी देता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा, हमारा पूरा विश्वास है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक चीन सिद्धांत का पालन करना जारी रखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताइवान में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव होंगे।

न्यूज गैलरी

लंदन में इलाज करा रहे शरीफ से मिलने पहुंचे करजई

लंदन : अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने लंदन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से शनिवार को भेंट की। उन्होंने शरीफ से मिलकर उनका हालचाल पूछा। लंदन स्थित शरीफ के आवास पर भेंट के दौरान उनकी मुलाकात पीएमएल-एन के प्रमुख शहबाज शरीफ से भी हुई। इस दौरान नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन नवाज भी मौजूद थे। (आइएएनएस)

अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी से 16 की मौत

हेरात : अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात व दक्षिणी प्रांत कंधार में भारी बर्फबारी से 16 लोगों की मौत हो गई है। भारी बर्फबारी व बारिश के कारण कई घरों की छतें धंस गईं, जिसके नीचे दबकर कई लोगों की मौत हो गई। इस बर्फबारी से दोनों प्रांत से आठ-आठ लोगों के मरने की खबर है। (एएनआइ)

अमेरिका में तूफान से 11 लोगों की हुई मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के दक्षिणी और मध्य हिस्से में शनिवार को आए तूफान से 11 लोगों की मौत हो गई। तूफान में फंसकर जान गंवाने वालों में टेक्सास के लुबॉक में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलधार बारिश के कारण ओक्लाहोमा में अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति बह गया। तूफान ने लुसियाना प्रांत में भी जमकर कहर बरपाया। प्रांत में तूफान से तहस-नहस हुए एक घर में वृद्ध युगल को मृत पाया गया। आयोवा प्रांत में ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। प्राकृतिक आपदा के कारण टेक्सास से लेकर ओहायो तक लाखों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। तूफान से यातायात भी प्रभावित है। (आइएएनएस)

लीबिया के दोनों धड़े संघर्ष विराम को राजी

बेनगाजी : उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया के दोनों धड़े संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की युद्धविराम की अपील पर अमल करते हुए जनरल खलीफा हफ्तार ने शनिवार को संघर्ष विराम की घोषणा की थी। लीबिया की सरकार गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड (जीएनए) के प्रमुख फयाज अल-सराज ने भी इसका स्वागत किया है। वर्ष 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद से लीबिया में जीएनए और हफ्तार के नेतृत्व वाले विद्रोही धड़े के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। रूस और तुर्की के अलावा जर्मनी और इटली भी इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। तेल संपन्न देश में शांति के लिए लीबिया मसले पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष दूत घसन सलामी की अगुआई में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जल्द ही बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। (एएफपी)

इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर फिर दागे गए आठ रॉकेट

खाड़ी में तनाव ▶ 'अल-बलाड' पर हमले में चार इराकी सैनिक घायल

सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इसी अड्डे पर किया था हमला

बगदाद, एजेंसियां : खाड़ी में युद्ध जैसे बनते हालात के बीच इराक में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे पर फिर आठ रॉकेट दागे गए हैं। हमले में चार इराकी वायु सेना के दो अधिकारी और दो सैनिक घायल हुए हैं। इराकी सेना ने रविवार को यह जानकारी दी।

सेना ने एक बयान में कहा कि बगदाद से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित अल-बलाड एयरबेस पर कत्यूशा श्रेणी के आठ रॉकेट गिरे। अल-बलाड अड्डा इराक में अमेरिकी वायु सेना का प्रमुख अड्डा है। इराक अपने एफ-16 लड़ाकू विमानों को भी यहीं रखता है। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों को किसी तरह का नुकसान की खबर नहीं है। वैसे भी पिछले दो हफ्ते के दौरान ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बाद यहां से ज्यादातर अमेरिकी सैनिक चले गए हैं।

अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि रॉकेट कहां से दागे गए थे। बता दें कि ईरान ने अपने शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद पिछले हफ्ते इसी सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमला किया था। अमेरिका ने इराक में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सुलेमानी को मार गिराया था। उसके बाद से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

हाल के दिनों में इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की घटनाएं तेज हुई हैं। हालांकि, ज्यादातर हमले में इराकी सैनिक ही घायल होते हैं। इसी तरह के एक हमले में एक अमेरिकी कांट्रैक्टर की मौत हुई थी।

अमेरिकी दूतावासों पर हमले की योजना बना रहे थे सुलेमानी : वहीं, वाशिंगटन में एक टीवी शो में अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनकी टीम का मानना है कि ईरान खाड़ी देशों में चार अमेरिकी दूतावासों पर हमले की योजना बना रहा था। हालांकि, एस्पर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई ठोस खुफिया जानकारी नहीं देखी है। वह सिर्फ राष्ट्रपति और उनकी टीम के विचार को रख रहे हैं।

ट्रंप ने पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में कहा था कि मारे जाने से पहले ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी चार अमेरिकी दूतावासों पर हमले की योजना बना रहे थे। उन्होंने इस संबंध में खुफिया जानकारी होने का दावा भी किया था।

ईरान में खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

दुबई, एजेंसियां : ईरानी सेना द्वारा यूक्रेनी विमान को गलती से मार गिराए जाने की स्वीकारोक्ति के बाद तेहरान में रविवार को दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हैं। इस बीच, अमेरिका ने कहा है कि वह बिना पूर्व शर्त के ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो में तेहरान स्थित एक विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है कि हमारा दुश्मन अमेरिका है, वास्तव में हमारा दुश्मन यहीं मौजूद है। इस पोस्ट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन सरकारी मीडिया ने शनिवार को हुए विरोध-प्रदर्शनों की पुष्टि की है। तेहरान में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। उधर, रविवार को ईरान के उदारवादी समाचार पत्र एत्माद की बैनर हेडलाइन माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए लगाई है।

शीर्ष सैन्य कमांडर ने संसद को दी जानकारी : विमान हादसे पर बढ़ते विरोध के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के शीर्ष कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने संसद को जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, बदले में ईरान की कार्रवाई और यूक्रेनी विमान को मार गिराने की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्पीकर ने संसद के सुरक्षा और विदेशी मामलों के आयोग से इस मामले की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो उसके उपाय सुझाने को कहा है।

ट्रंप ने दी चेतावनी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ईरान को चेतावनी दी कि वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की हत्या कराने की गलती ना करे। उन्होंने कहा कि पहले ही वह बहुत लोगों को मरवा चुका और हजारों को लोगों को हिरासत में ले रखा है, लेकिन इस बार दुनिया की उस पर नजर है।

श्रद्धांजलि देने गए ब्रिटिश राजदूत को ईरान ने किया गिरफ्तार, बाद में छोड़ा

- राजदूत बोले-किसी तरह के प्रदर्शन में नहीं लिया हिस्सा
- ईरान बोला, पहचान होने के 15 मिनट बाद ही छोड़ दिया गया

तेहरान, एएफपी : यूक्रेन विमान हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने गए ब्रिटेन के राजदूत रोब मकायर को ईरान में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह लगभग आधा घंटे तक पुलिस की गिरफ्त में रहे। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि पहचान होने के 15 मिनट के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया था। राजदूत ने प्रदर्शन में शामिल होने से इन्कार किया है। वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को राजदूत को समन किया और अवैध रैली में उनके शामिल होने पर शिकायत दर्ज कराई। वहीं, अमेरिका ने कहा है कि ईरान इसके लिए ब्रिटेन से माफी मांगे।

दरअसल, ईरान द्वारा यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराए जाने की स्वीकारोक्ति के बाद शनिवार शाम को छात्रों ने मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान के अमीर कबीर विश्वविद्यालय में एक सभा आयोजित की थी। ईरानी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक राजदूत विश्वविद्यालय में आयोजित इस सभा में मृतकों को श्रद्धांजलि देने गए थे। पुलिस ने उन्हें लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रविवार को ट्विटर पर रोब मकायर ने कहा, मैंने किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनका कहना था कि मृतकों में कुछ ब्रिटिश नागरिक भी थे, जिसके चलते वह भी श्रद्धांजलि देने वहां गए थे। हालांकि जब लोग नारेबाजी करने लगे तो पांच मिनट बाद ही मैं वहां से चला आया। मकायर ने कहा कि राजनयिकों को गिरफ्तार करना सभी देशों में अवैध है। ब्रिटिश सरकार ने मकायर की गिरफ्तारी को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।

ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि ब्रिटिश राजदूत को अवैध रैली में अनजान विदेशी होने के नाते गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब उनकी पहचान प्रमाणित हो गई तो उन्हें 15 मिनट के भीतर रिहा कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोब मकायर को रविवार को समन किया गया है और अवैध रैली में उनके शामिल को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई।

तेहरान में यूक्रेन के विमान हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने गए ब्रिटेन के राजदूत रोब मकायर (मध्य में कैप पहने)। रायटर

भारत और चीन को नुकसान पहुंचाने वाले एनजीओ को रोकेगा नेपाल

- दोनों देशों से संबंध सामान्य बनाए रखने के लिए तैयार कर रहा है मसौदा
- भारत को तेजी से बन रहे मदरसों और चीन को तिब्बतियों से है आपत्ति

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से संबंधित एक नीतिगत मसौदा तैयार कर रहा है। इस मसौदे में विदेशी एनजीओ को नेपाल में काम करने से रोकने का प्रावधान होगा। ये वे एनजीओ हैं जिनके कामकाज पर भारत और चीन को एतराज है। नेपाल दोनों बड़े पड़ोसी देशों से संबंध सामान्य बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रहा है।

भारत और चीन के लिए सीमापार से आने वाले आतंकी और अपराधी बड़ी समस्या रहे हैं। भारत को पाकिस्तान द्वारा पोषित इस्लामिक आतंकवाद से खतरा बना रहता है तो चीन को नेपाल के जरिये तिब्बतियों के अवैध रूप से आने-जाने पर समस्या रहती है। नेपाल के भीतर सीमा के नजदीक तेजी से बने मदरसे भी भारत के लिए चिंता का विषय रहे हैं। ये मदरसे कतर, सऊदी अरब और तुर्की की आर्थिक सहायता से बने हैं और भारत में धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं।

प्रतीकात्मक

नेपाल की विदेश नीति में दो बड़े पड़ोसियों से संबंधों का संतुलन बनाए रखने की चुनौती रहती है। काठमांडू पोस्ट अखबार के मुताबिक नेपाल के उत्तर और दक्षिण में विशाल जनसंख्या वाले दो देश हैं। दोनों का नेपाल की जनता पर कई तरह का प्रभाव भी है। इसलिए नेपाल किसी भी विदेशी संगठन को ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा जिससे भारत और चीन के साथ उसके संबंधों पर असर पड़े।

नेपाल की समाज कल्याण परिषद द्वारा तैयार किए जा रहे इस मसौदे को सरकार अंतिम रूप देगी और इसके बाद उसे संसद में रखा जाएगा। वहां से पारित होने पर यह कानून का रूप लेगा। परिषद के सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराई के अनुसार प्रस्तावित मसौदे में पड़ोसी देशों की चिंताओं का ध्यान रखा गया है। इसमें सीमावर्ती इलाकों में कार्य करने वाले एनजीओ पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य रणनीतिक कारणों से चलाए जा रहे एनजीओ की गतिविधियां रोकना है। उनसे होने वाले विदेशी संबंधों के नुकसान से खुद को बचाना है।

बांग्लादेश में इज्तिमा के लिए जोखिम भरी यात्रा

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास टोंगी में आयोजित तीन दिन दिवसीय विश्व इज्तिमा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से भारी अफरा-तफरी का माहौल रहा। ट्रेन में जगह न मिलने पर लोगों ने छत और खिड़कियों पर लटककर यात्रा करने का जोखिम उठाया। मुस्लिमों के लिए हज के बाद इज्तिमा दूसरा सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, जहां भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। भारत में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और पाकिस्तान के लाहौर शहर के समीप होने वाला 'रायविंड इज्तिमा' ऐसे ही बड़े आयोजन हैं। रायटर

थाइलैंड में सेना समर्थित सरकार के विरोध में सड़कों पर लोग

- दस हजार लोगों ने मार्च कर सरकार से मांगा इस्तीफा
- 2014 के सैन्य तख्तापलट के बाद देश का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन

थाइलैंड में रविवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतर कर तानाशाही के खिलाफ मार्च निकाला। इस मार्च को 'रन अंगेस्ट डिक्टेटरशिप' नाम दिया गया। रायटर

बैंकॉक, एएफपी : थाइलैंड में रविवार को करीब दस हजार लोगों ने सड़क पर आकर तानाशाही के खिलाफ तेज कदमों से मार्च किया। उन्होंने इस मार्च का नाम 'रन अंगेस्ट डिक्टेटरशिप' दिया। तेज आवाज में नारे लगाते हुए ये लोग तीन अंगुलियों वाला सैल्यूट करते हुए सड़कों से निकले। इस तरह का सैल्यूट हंगर गेम्स फिल्म में व्यवस्था विरोधी करते दिखाए गए हैं। 2014 के सैन्य तख्तापलट के बाद थाइलैंड में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था।

प्रदर्शनकारी पहले बैंकॉक पार्क में एकत्रित हुए और उसके बाद वे सड़क पर आए। प्रदर्शन का नेतृत्व अरबपति राजनेता थानाथॉर्न जुआंगरूग्रंकित कर रहे थे। उनकी पार्टी को सेना विरोधी राजनीतिक दल माना जाता है। उनकी पार्टी भंग किए जाने की धमकी का सामना कर रही है। यह प्रदर्शन पूर्व जुंटा प्रमुख प्रयूत चान-ओ-चान की सरकार के खिलाफ था। थानाथॉर्न पर कई तरह के आरोप लगाकर उनका सांसद का ओहदा छीना जा चुका है। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए मीडिया से कहा, आप सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। थाइलैंड में बदलाव की दिशा में यह पहला कदम है। मार्च शुरू होने से पहले प्रदर्शनकारियों ने जोर का नारा लगाया- प्रयूत, बाहर जाओ। उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में भी कई नारे लगाए।

प्रदर्शन में टैंक की तस्वीर वाली कमीज पहने शख्स ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार जनता की सुविधाओं की ओर ध्यान दे। उसके लिए धन खर्च करे। पर्यावरण में सुधार के लिए कार्य करे। न कि टैंक और पनडुब्बियां खरीदने में धन खर्च करे। प्रदर्शन में शामिल 68 वर्ष के वासुचार्ट ने कहा, हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम उस सरकार को प्यार करते हैं जो हमारे देश को हर तरह से सुरक्षित रखे। सेना की नियुक्त संसद के समर्थन में प्रयूत ने 2018 में देश की सत्ता संभाली थी। संसद में उनके पास मामूली बहुमत है। कमजोर होती अर्थव्यवस्था के दौर में सरकार का जन विरोध बढ़ रहा है। इससे प्रयूत सरकार की हालत और पतली हो रही है।

दर्जन भर सऊदी सैन्य प्रशिक्षुओं को निष्कासित करेगा अमेरिका

- नौसेना अड्डे पर गोलीबारी की घटना के चलते लिया फैसला
- गत दिसंबर में हुए हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की चली गई थी जान

वाशिंगटन, एएफपी : चरमपंथियों से संपर्क और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में अमेरिका अपने यहां प्रशिक्षण ले रहे एक दर्जन सऊदी सैन्यकर्मियों को निष्कासित करने जा रहा है। गत दिसंबर में फ्लोरिडा स्थित नौसेना अड्डे में सऊदी सैनिक द्वारा की गई गोलीबारी के मामले की जांच-पड़ताल के बाद यह निर्णय लिया गया है। गत छह दिसंबर को 21 साल के सऊदी लेफ्टिनेंट मुहम्मद अल शमरानी ने पेंसाकोला नौसेना अड्डे में गोलीबारी कर तीन अमेरिकी नौसैनिकों की जान ले ली थी और आठ को घायल कर दिया था। बाद में वह भी मारा गया था।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिन सैन्य प्रशिक्षुओं को निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है, उन पर शमरानी के समर्थन का आरोप साबित नहीं हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी (एफबीआइ) की जांच में यह भी पता चला है कि इस हमले से पहले शमरानी के व्यवहार में आए बदलाव की अन्य प्रशिक्षुओं ने कोई सूचना नहीं दी थी। एफबीआइ ने फोन निर्माता कंपनी एपल से शमरानी के दो आइफोन का डाटा हासिल करने में मदद मांगी थी। लेकिन कंपनी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए इससे इन्कार किया है। एपल का कहना है कि उसने पहले ही क्लाउड स्टोरेज में मौजूद डाटा जांच एजेंसी के साथ साझा कर दिया है। इस हमले के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा था कि देश में प्रशिक्षण ले रहे सभी सऊदी सैन्य प्रशिक्षुओं की पृष्ठभूमि की जांच की गई है और उनसे किसी तरह के खतरे की बात पता नहीं चली है। पेंटागन ने हमले के बाद अमेरिका में सऊदी अरब के सैन्यकर्मियों के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी थी।

अगले माह भारत आएंगे श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे फरवरी की शुरुआत में भारत दौरे पर आएंगे। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नवंबर में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद महिंदा राजपक्षे की यह पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले उनके भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने चुनाव जीतने के बाद अपना पहला आधिकारिक दौरा भारत का ही किया था।

पिछले हफ्ते श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने ने भारत में अपने समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों के बीच अन्य मुद्दों के अलावा व्यापार और निवेश के जरिये आपसी संबंधों को प्रगाढ़ता देने पर चर्चा हुई थी। पीएम राजपक्षे की भारत यात्रा ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब श्रीलंका में तमिल मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए जोर दिया जा रहा है। दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

ये भी जानिए

पिछले एक वर्ष के अंतराल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौ वनडे मुकाबले खेले गए हैं। भारत ने पांच जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चार मैच जीते हैं।

एक नजर में

आनंद ने खेला ड्रॉ

विज्क आन जी (नीदरलैंड्स): पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को रविवार को यहां टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में रूसी ग्रैंडमास्टर व्लादिस्लाव आर्टेमिएव से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। आनंद इस टूर्नामेंट में 18वीं बार शिरकत कर रहे हैं। 31 चाल के बाद दोनों खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं था और दोनों ने अंक बांटने का फैसला किया। मौजूदा विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को भी अपने चिर प्रतिद्वंद्वी नीदरलैंड्स के अनीश गिरी से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। (प्रेट्र)

संयुक्त छठे स्थान पर राशिद

हांगकांग: राशिद खान रविवार को यहां हांगकांग ओपन में भारतीय गोल्फरों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के वेड ओर्मसबे ने अंतिम दौर में चार अंडर 66 के स्कोर से कुल 17 अंडर 263 के स्कोर से खिताब जीता। राशिद ने अंतिम दौर में 70 के स्कोर से कुल नौ अंडर 271 का स्कोर बनाया। भारत के एसएसपी चौरसिया संयुक्त 22वें, जबकि शिव कपूर संयुक्त 18वें स्थान पर रहे। अजितेश संधू संयुक्त 41वें, राहिल गंगजी (72) और एस चिकारंगप्पा (72) संयुक्त 47वें स्थान पर रहे। अमन राज (74) ने संयुक्त 60वां स्थान हासिल किया। (प्रेट्र)

शीर्ष पर रहा भारत

नई दिल्ली: भारत ने 2019 में चीन और अमेरिका को पछाड़ते हुए साल 2019 का अंत दुनिया के शीर्ष निशानेबाजी देश के तौर पर किया। भारत ने 21 स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते जिससे देश सभी राइफल-पिस्टल विश्व कप और फाइनल्स में अव्वल रहा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) के अध्यक्ष रनिंदर सिंह ने आइएसएसएफ) की 2019 की रैंकिंग का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, 'बहुत बढ़िया टीम इंडिया।' तालिका में भारत 30 पदक से शीर्ष पर है। (प्रेट्र)

ऑस्ट्रेलिया की ओस में 'बॉस' बनने की तैयारी

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कंगारू टीम ने ओस में बिताई रात शनिवार रात को कोच मैकडोनाल्ड ने लगाया स्टेडियम के बाहर शिविर

मुंबई, प्रेट्र: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने कहा कि कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने यह जानने के लिए शनिवार रात को वानखेड़े स्टेडियम में बाहर शिविर लगाया कि ओस किस समय पड़ती है। यही नहीं, टीम ने रविवार को गीली गेंद से गेंदबाजी का अभ्यास भी किया।

रिचर्डसन ने कहा कि एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने यहां बीती रात शिविर लगाया, ताकि वह जान सकें कि किस समय ओस पड़ती है, हर कोई बस अनुमान लगा रहा है। मुझे लगता है कि हर कोई तैयार है। हमें मैच के दिन का इंतजार करना और देखना होगा। यह नया नहीं है, हमारे यहां घरेलू मैदानों पर भी ओस पड़ती है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली की अगुआई वाली भारतीय टीम मंगलवार से यहां शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज में घरेलू मैदान पर प्रबल दावेदर है, लेकिन कहा कि उनकी टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।

दूसरा वनडे राजकोट (17 जनवरी) और तीसरा (19 जनवरी) बेंगलुरु में खेला जाएगा। रिचर्डसन ने कहा कि मुझे लगता है कि घरेलू टीम हमेशा प्रबल दावेदार होती है। मुझे लगता है कि फिंची (आरोन फिंच) ने कहा था कि किसी भी टीम ने यहां लगातार सीरीज नहीं जीती हैं, तो यह मुश्किल होने वाला है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने भारत में सीमित ओवरों की सीरीज में 0-2 से पिछड़कर वापसी करते हुए 3-2 से जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ उसकी सरजमीं पर खेलना हमेशा ही बड़ी चुनौती है और पिछले साल जो हुआ वे इसके लिए तैयार होंगे। मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन घरेलू टीम हमेशा प्रबल दावेदार होती है। हम छुपे रुस्तम हैं। हमने इस बारे में काफी बात की है। मुझे लगता है कि टीम का प्रत्येक सदस्य यहां पहले खेल चुका है, यह नया नहीं है। हमारी रणनीति उनके कुछ बल्लेबाजों को रोकने की होगी। हमारे बीच बड़े स्कोर के मुकाबले जरूर होंगे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम में चार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और रिचर्डसन हैं। रिचर्डसन ने कहा कि तीनों के साथ मैदान पर रहना काफी सुखद अहसास है। मुझे नहीं पता कि कौन अंतिम-11 में जगह बनाएगा। अगर मैंने उनके साथ मैदान पर जगह बनाई तो इससे मुझे काफी आत्मविश्वास मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं गेंदबाजी करने आऊंगा तो भारत के दो या तीन विकेट गिर चुके होंगे। विश्व कप में रिचर्डसन अंतिम-11 से अंदर-बाहर होते रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके टीम में जगह बनाई थी।

जोंस बोले, रनों के भूखे हैं रोहित और वार्नर: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोंस का मानना है कि डेविड वार्नर और रोहित शर्मा रनों के बेहद भूखे हैं और वह आगामी वनडे सीरीज में दोनों की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित हैं। भारत ने अपनी पिछली सीरीज में टी-20 में श्रीलंका को 2-0 से, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को टेस्ट में 3-0 से मात दी है।

जोंस ने कहा कि रोहित और वार्नर मैदान के दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप मैदान का एक साइड ब्लॉक कर देते हैं तो वे दूसरी साइड से रन निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी ना केवल शारीरिक रूप से फिट हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी फिट हैं और वे रनों के काफी भूखे हैं। मैं उन्हें इस लड़ाई को जीतते देखना चाहता हूं। जोंस का मानना है कि टीम आजकल ऐसे गेंदबाज को रखना पसंद करती है जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकें, ताकि उनके खिलाफ अगर बल्लेबाज कोई भी गलती करे तो विकेट मिल सके।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि 140 किमी या उससे अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के साथ भी यही बात है। जब वे 140 किमी से भी अधिक गति से गेंदबाजी करते हैं तो आप गलती करते हैं और आपके पास समय नहीं होता है तथा आप बोल्ड या एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इसीलिए टीमें 140 किमी या उससे अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के साथ रहती हैं।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ● एएनआइ

स्टीव वॉ की मानसिक शक्ति का कायल रहा हूं : अजिंक्य रहाणे

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का कहना है कि वह हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ की मानसिक शक्ति के कायल रहे हैं। रहाणे जब हाल ही में वॉ से मिले तो वह अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ की तस्वीर साझा करने से खुद को नहीं रोक सके। वॉ के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए रहाणे ने लिखा है कि स्टीव वॉ के साथ सार्थक बातचीत हुई। मैंने हमेशा से एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर वॉ की मानसिक शक्ति को सराहा है। 54 साल के स्टीव वॉ विश्व कप विजेता कप्तान रहे हैं और इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 168 टेस्ट और 325 वनडे मैच खेल चुके हैं।

सलामी बल्लेबाजी संयोजन में दुविधा टीम के लिए अच्छी : राठौर

मुंबई, प्रेट्र: भारतीय सलामी बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और शिखर धवन के लय में होने से चयन को लेकर टीम प्रबंधन के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने रविवार को कहा कि यह अच्छी दुविधा है। रोहित के लिए साल 2019 शानदार रहा था, जहां उन्होंने विश्व कप में पांच शतक लगाए थे। धवन ने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में वापसी करते हुए रन बनाकर लय में होने का संकेत दिया। राहुल भी पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि यह दुविधा की स्थिति हमारे लिए अच्छी है। रोहित जाहिर तौर पर इसके लिए सबसे मजबूत विकल्प हैं। वे दोनों (शिखर और राहुल) भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिखर ने वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है और राहुल शानदार लय में हैं। जब जरूरत होगी हम इससे निपटेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां खेले जाने वाले शुरुआती वनडे मैच से पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने में अभी दो दिनों का समय बचा है। प्रबंधन इस पर फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 14 जनवरी से यहां शुरू होगी। इस साल टी-20 विश्व कप खेला जाना है, ऐसे में इस वनडे सीरीज के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर राठौड़ ने कहा कि यह अलग प्रारूप है और क्रिकेट आत्मविश्वास का खेल है। एक बल्लेबाज और गेंदबाज के तौर पर जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो आपका प्रदर्शन मायने रखता है। उनकी टीम बेहतर है और उससे मनोबल बढ़ता है। बल्लेबाजी कोच ने कहा कि हम इसे किसी अन्य सीरीज की तरह ले रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक के खिलाफ जब आप खेलते हैं तो टीम के तौर पर अच्छा करने की सोचते हैं।

विक्रम राठौर ● फाइल फोटो, प्रेट्र

साइना को अकादमी छोड़ने के लिए पादुकोण ने उकसाया : गोपी

मुख्य कोच पुलेला ने अपनी किताब 'ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन : इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स' में खोला राज

नई दिल्ली, प्रेट्र: पुलेला गोपीचंद हालांकि अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, लेकिन इस राष्ट्रीय कोच ने उस दर्द को साझा किया जो उन्हें स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के उनकी अकादमी छोड़कर प्रकाश पादुकोण की अकादमी में जाने के बाद हुआ था और अब तक उन्हें यह बात बेहद परेशान करती है।

गोपीचंद ने अपनी आगामी किताब 'ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन : इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स' में इस बात का जिक्र किया है और इसमें उन्होंने लिखा कि वह इस बात से भी हैरान थे कि महान खिलाड़ी और भारत के पहले बैडमिंटन सुपरस्टार पादुकोण ने कभी भी उनके बारे में कोई भी सकारात्मक बात नहीं की है। पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन और राष्ट्रीय मुख्य कोच गोपीचंद ने इसमें मुश्किल समय का भी जिक्र किया।

गोपीचंद की किताब के 'बिटर राइवलरी' टाइटल के पन्ने में उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि जब साइना ने 2014 विश्व चैंपियनशिप के बाद बेंगलुरु में पादुकोण की अकादमी से जुड़ने और विमल कुमार के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करने का फैसला किया था तो वह कितने दुखी हुए थे। साइना के पति और कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप ने भी इसकी पुष्टि की है। किताब में उनके सह लेखक खेल इतिहासकार बोरिया मजूमदार और वरिष्ठ पत्रकार नलिन मेहता हैं। इसमें गोपीचंद ने रहस्योद्घाटन किया, 'यह कुछ इस तरह का था कि मेरे किसी करीबी को मुझसे दूर कर दिया गया हो। पहले मैंने साइना से अपनी अकादमी छोड़कर कहीं और नहीं जाने के लिए मिन्नत की। लेकिन, तब तक वह किसी अन्य के प्रभाव में आ चुकी थीं और अपना मन बना चुकी थीं, जबकि मैं उन्हें रोककर उनकी प्रगति नहीं रोकना चाहता था। मैं जानता था कि यह हमारे में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता।'

तब ऐसी बातें चल रही थीं कि साइना को लगता था कि गोपीचंद ज्यादा ध्यान पीवी सिंधू पर लगा रहे थे। गोपीचंद ने कहा, 'हां, मेरे पास देखरेख के लिए अन्य खिलाड़ी भी थे और सिंधू ने 2012 और 2014 के बीच दो वर्षों में काफी प्रगति की थी। लेकिन, मेरी इच्छा कभी भी साइना की अनदेखी करने की नहीं थी। शायद यह बात मैं उन्हें समझा नहीं सका।'

दूसरी पारी में हरियाणा को 148 की बढ़त

जागरण संवाददाता, रोहतक: रणजी ट्रॉफी मैच में ओडिशा के खिलाफ दूसरे दिन हरियाणा की टीम ने मैच में कुछ पकड़ बनाई है। पहली पारी में 70 रनों से पिछड़ने के बाद हरियाणा की टीम ने दूसरे दिन 148 रनों की बढ़त बना ली है, जबकि अभी टीम के पांच बल्लेबाज सुरक्षित हैं।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा की पहली पारी 90 रनों पर सिमट गई थी, जबकि ओडिशा की टीम ने 160 रन बनाए थे। पहली पारी में ओडिशा की ओर से बिप्लब ने सबसे अधिक 52 रनों की पारी खेली थी। हरियाणा की ओर से टीनू कुंडू ने पांच और कप्तान हर्षल पटेल ने तीन विकेट लिए थे। रविवार को मैच के दूसरे दिन ओडिशा की टीम हरियाणा के गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सकी और मात्र 70 रनों की बढ़त हासिल कर पूरी टीम आउट हो गई। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा की टीम के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दी। इस दौरान शुभम रोहिल्ला ने 48 और अंकित कुमार ने 46 रनों की पारी खेलते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। हालांकि इसके बाद हरियाणा की टीम को ओडिशा के गेंदबाजों ने लगातार झटके दिए और 139 रनों पर चार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दूसरे दिन की समाप्ति तक हरियाणा ने पांच विकेट पर 218 का स्कोर किया।

सीएसी में मदन लाल का साथ देंगे गौतम गंभीर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और मदन लाल की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य के तौर पर नियुक्ति लगभग तय है। यह सीएसी 2020 से चार साल के कार्यकाल के दौरान चयन समितियों को चुनेगी। मदन के सीएसी प्रमुख बनने की खबर दैनिक जागरण ने शुक्रवार के अंक में पहले ही प्रकाशित कर दी थी।

इस समिति की तीसरी सदस्य मुंबई की पूर्व महिला क्रिकेटर सुलक्षणा नाइक हो सकती हैं। सुलक्षणा ने करियर में भारत के लिए 46 वनडे और दो टेस्ट मैच खेले हैं। बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मदन लाल और गौतम गंभीर सीएसी के सदस्य बनने को तैयार हैं और उनकी नियुक्ति तय है। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे 68 वर्षीय मदन लाल सबसे सीनियर सदस्य होने के तौर पर इस समिति का नेतृत्व करेंगे। वहीं, 2011 विश्व कप चैंपियन टीम इंडिया के हीरो गंभीर तीसरे सदस्य के साथ मदन लाल का साथ देंगे।

माना जा रहा है कि यह कमिटी सीनियर चयन समिति में दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए केवल एक ही बार बैठक करेगी क्योंकि सीनियर चयन समिति में कार्यकाल पूरा कर चुके दो सदस्यों की जगह लेने वालों को चुनना होगा। सीनियर चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद (दक्षिण क्षेत्र) और गगन खोड़ा (मध्य क्षेत्र) के विकल्प तलाशने को समिति की बैठक होगी। सरनदीप सिंह (उत्तर क्षेत्र), देवांग गांधी (पूर्व क्षेत्र) और जतिन परांजपे (पश्चिम क्षेत्र) का अभी चार साल के कार्यकाल में एक साल बचा है। जूनियर चयन समिति में भी बदलाव होंगे। गंभीर ने करियर में 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी-20 मैच खेले।

फैसला

- तीसरी सदस्य के तौर पर सुलक्षणा का नाम
- सीएसी प्रमुख मदन लाल के बाद दोनों के नाम आए सामने

भारतीय महिला टीम में रिचा नया चेहरा

मुंबई, प्रेट्र: भारत ने 21 फरवरी से शुरू होने वाले आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की और हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम में बंगाल की बल्लेबाज रिचा घोष एकमात्र नया चेहरा हैं। टीम में और किसी नए चेहरे को शामिल नहीं किया गया है।

वहीं, हरियाणा की 15 साल की शेफाली वर्मा भी अपने पहले सत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद पहली वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेंगी। रिचा को हाल ही में महिला चैलेंजर ट्रॉफी में उनके अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला, जिन्होंने 26 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से 36 रन बनाए थे। चयनकर्ताओं ने टी-20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए भी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें नुजहत परवीन को 16 वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह टूर्नामेंट 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और जिसमें तीसरी टीम इंग्लैंड है।

टी 20 विश्व के लिए टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, रिचा घोष, तानिया भाटिया, पूनम यादव, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, शिखा पांडे, पूजा वस्त्राकर और अरुंधति रेड्डी।

एंसी ने दो स्वर्ण पदक जीतकर बिखेरी चमक

खेलो इंडिया

- केरल की एथलीट सोजन ने झटके दो स्वर्ण पदक
- अंडर-21 लंबी कूद स्पर्धा व 100 मीटर दौड़ में जीता सोना

गुवाहाटी, प्रेट्र: केरल की एथलीट एंसी सोजन ने यहां ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा के अंडर-21 वर्ग में दो स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन रविवार को चमक बिखेरी। सोजन ने महिलाओं की अंडर-21 लंबी कूद स्पर्धा में 6.36 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पहले वह 100 मीटर की दौड़ को 12.21 सेकेंड में पूरा कर शीर्ष स्थान पर रही थीं

18 वर्षीय सोजन ने इसके साथ ही लंबी कूद में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मीट रिकॉर्ड भी बनाया। तमिलनाडु की शीरिन अब्दुल गफूर ने 6.30 मीटर की कूद के साथ रजत पदक हासिल किया। हरियाणा के नुजरत अली ने अंडर-21 की 100 मीटर स्पर्धा को 10.77 सेकेंड में पूरा कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेलंगाना की जीवनजी दीप्ति और तमिलनाडु की रूतिका सरवनन ने लड़कियों की अंडर-17 की 100 मीटर की दौड़ में क्रमशः स्वर्ण और रजत जीता। दोनों ने 12.26 सेकेंड का समय लिया। जीवनदीप ने सेकेंड से भी कम समय से रूतिका को पीछे छोड़ा।

झारखंड के सदानंद कुमार ने लड़कों की अंडर-17 की 100 मीटर दौड़ को 10.95 सेकेंड में पूरा कर स्वर्ण जीता, जबकि महाराष्ट्र के आकाश सिंह इस स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश के इकराम अली ने पुरुषों के अंडर-21 वर्ग में चक्का फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 53.82 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर हरियाणा के अभय गुप्ता को एक मीटर से पीछे छोड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के पोल वाल्टर संदीप कुमार ने लड़कों के अंडर-17 वर्ग में सुनहरी सफलता हासिल की। साइकिलिंग में महाराष्ट्र के मधुरा वायकर (अंडर-21 और पूजा डानोले (अंडर-17) ने व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में खिताब जीतकर अपने राज्य का तालिका में दबदबा बनाए रखा। ओडिशा के दिनेश कुमार और राजस्थान के मुकेश कुमार कास्वान ने क्रमशः लड़कों के अंडर-21 और अंडर-17 का खिताब जीता।

टेनिस विलियम्स ने पेगुला को हराकर ऑकलैंड खिताब अपने नाम किया

सेरेना ने तीन साल बाद जीता कोई खिताब

ऑकलैंड, एएफपी: अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स ने रविवार को डब्ल्यूटीए ऑकलैंड क्लासिक फाइनल में हमवतन खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराकर खिताब अपने नाम किया। सेरेना ने इस तरह तीन साल के खिताबी सूखे को समाप्त किया और इस महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए उम्मीदें बढ़ा दीं, जिसमें वह मारगेट कोर्ट के 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी करने का प्रयास करेंगी। सेरेना ने पेगुला को 6-3, 6-4 से शिकस्त देकर 2017 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन में हासिल किए गए खिताब के बाद पहली डब्ल्यूटीए ट्रॉफी जीती और मां बनने के बाद यह उनका पहला खिताब है। सेरेना ने कैरोलाइन वोज्नियाकी के साथ डबल्स के फाइनल में भी प्रवेश किया था, लेकिन उन्हें अमेरिका की आसिया मुहम्मद और टेलर टाउनसेंड से 4-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा।

पुरस्कार राशि राहत कोष में: खिताब को जीतने के बाद सेरेना को 43000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 31 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि का चेक मिला, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दान में देने का फैसला किया। सेरेना ने ऑकलैंड में पहले राउंड में पहनी गई अपनी जर्सी पर ऑटोग्राफ दिया और उसे आग पीड़ितों के लिए धन जुटाने के मकसद से नीलाम करने का फैसला किया।

होबार्ट में नादिया के साथ खेलेंगी सानिया: भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार नादिया किचेनोक होबार्ट अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के पहले दौर में जॉर्जिया की ओकसाना कलाशनिकोवा और जापान की मियू केटो की जोड़ी से भिड़ेंगी।

38 साल की सेरेना का करियर का 73वां डब्ल्यूटीए खिताब है। वह 2018 और 2019 में विंबलडन और अमेरिकी ओपन के फाइनल में हार गई थीं, जबकि 2019 के रोजर्स कप फाइनल से वह रिटायर हो गई थीं

1999 में सेरेना ने पहला डब्ल्यूटीए खिताब फ्रांस की अमीली माउरेस्मो को हराकर जीता था

2017 में सेरेना ने मेलबर्न में जब अपना पिछला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था तो वह आठ महीने की गर्भवती थी

डब्ल्यूटीए ऑकलैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ अमेरिका की सेरेना विलियम्स ● एएफपी

प्लिस्कोवा ने जीती ब्रिसबेन की विजेता ट्रॉफी

ब्रिसबेन, एएफपी: चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने रविवार को ब्रिसबेन अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में मेडिसन कीज पर तीन सेट तक चले मुकाबले में जीत हासिल की। इस तरह दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी की अगले सप्ताह शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए यह अच्छी तरह तैयार है। प्लिसकोवा ने दो घंटे तक चले मुकाबले में कीज को 6-4, 4-6, 7-5 से हराया। पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ने अभी तक एक भी ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब अपने नाम नहीं किया है, लेकिन वह पिछले साल मेलबर्न में सेमीफाइनल तक पहुंची थीं। पिछले साल मेलबर्न में फाइनल में नाओमी ओसाका ने फाइनल में प्लिसकोवा को हराकर उनका सपना तोड़ दिया था। शनिवार को उन्होंने ओसाका को हराया था।

अंडर-19 विश्व कप से पहले कार्तिक की हैट्रिक

निखिल शर्मा, नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका में अंडर-19 विश्व कप से पहले रविवार को हुए अभ्यास मैच में तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेकर भारतीय क्रिकेट के भविष्य की बड़ी उम्मीद बनने की दस्तक दी है।

कार्तिक ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन ओवर में 10 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने पारी की दूसरी गेंद पर फरहान जखील, तीसरी पर सेदिकउल्लाह अटल व चौथी गेंद पर रहमानुल्लाह को चलता भेजा। इससे अफगानिस्तान की टीम मात्र 44 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 211 रनों से जीता। इससे पहले भारत ने यशस्वी जायसवाल के 69 रन की बदौलत 50 ओवर में आठ विकेट पर 255 रन बनाए थे।

कार्तिक का उदय: कार्तिक ने 2016 में 16 साल की उम्र में अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 50 विकेट लिए थे। इस प्रदर्शन ने उन्हें सीधे उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में जगह दिला दी थी। तब उत्तर प्रदेश टीम के कप्तान सुरेश रैना कार्तिक की गेंदबाजी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में उन्हें सीनियर टीम में जगह दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी।

बुमराह को मिला पॉली उमरीगर पुरस्कार

श्रीकांत कर्नल सीके नायुडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हुए सम्मानित

मुंबई, प्रेट्र: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रविवार को बीसीसीआइ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में पॉली उमरीगर पुरस्कार (साल का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर 2018-19) से सम्मानित किया। इसके साथ उन्हें 15 लाख रुपये का चेक भी दिया गया। इस बीच, अर्जुन अवॉर्डी महिला क्रिकेटर पूनम यादव को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) का पुरस्कार दिया गया। यह महिला वर्ग में बीसीसीआइ की ओर से दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है।

मयंक को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण (पुरुष) और शेफाली वर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण (महिला) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार के साथ-साथ 2018-19 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए दिलीप सरदेसाई पुरस्कार भी मिला।

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को क्रमशः कर्नल सीके नायुडू लाइफ टाइम अचीवमेंट और बीसीसीआइ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंजुम 100 महिला वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय हैं। वहीं, 72 साल के दिलीप दोषी को विशेष पुरस्कार दिया गया। नंबर-1 वनडे गेंदबाज बुमराह ने पिछले साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

सचिव जय शाह से पॉली उमरीगर पुरस्कार लेते जसप्रीत बुमराह ● प्रेट्र

सचिन तेंदुलकर मेरे लिए कृष्ण की तरह हैं और मैं उनका सुदामा हूं।
– मुहम्मद कैफ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

हैदराबाद एफसी ने रोका को नया कोच नियुक्त किया

नई दिल्ली, आइएएनएस : इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के छठे सत्र में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैदराबाद एफसी ने अल्बर्ट रोका को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की रविवार को घोषणा की। बेंगलुरू एफसी के पूर्व कोच रोका अब फिल ब्राउन की जगह लेंगे। हैदराबाद ने शनिवार को ही ब्राउन को बर्खास्त कर दिया था। रोका हालांकि 2020-21 सत्र से हैदराबाद के कोचिंग का पदभार संभालेंगे।

लिवरपूल ने बरकरार रखी अपनी लय

फुटबॉल डायरी ▶ ईपीएल में फर्मिनो के गोल से लिवरपूल को 1-0 से हराया

लंदन, एएफपी : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) की अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज लिवरपूल ने शनिवार देर रात खेले गए मुकाबले में टॉटनहम को 1-0 से हराकर अपनी लय को बरकरार रखा।

टॉटनहम हॉट्सपर स्टेडियम में खेल के 37वें मिनट में रॉबर्टो फर्मिनो ने लिवरपूल के लिए इकलौता गोल दागा, जिसकी बदौलत मैनेजर जुर्जेन क्लोप की लिवरपूल टीम ने मौजूदा सत्र के अपने 21वें ईपीएल मुकाबले में 20वीं जीत दर्ज की। आखिरी 15 मिनट के खेल में टॉटनहम के सोन ह्यून मिन और गिवानी लो सेल्सो को गोल करने के अच्छे मौके मिले, लेकिन वे लक्ष्य को भेद नहीं पाए। इस जीत के साथ यूरोपियन चैंपियन लिवरपूल के 61 अंक को हो गए हैं। यह यूरोप के शीर्ष पांच लीगों में एक सत्र में 21 मुकाबलों के बाद किसी भी क्लब द्वारा हासिल सर्वाधिक अंक हैं। इस रिकॉर्ड को लेकर क्लोप ने कहा कि यह खास है। इतने सारे मैच जीतना और हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहना।

बार्सिलोना के मैनेजर बनने की तैयारी में जाबी

दोहा, एएफपी : स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी जाबी अपने पूर्व क्लब बार्सिलोना के मैनेजर की नौकरी के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसकी जानकारी जाबी के मौजूदा कतरी क्लब अल साद ने दी। स्पेनिश मीडिया ने इससे पहले जानकारी दी थी कि बार्सिलोना ने दबाव में चल रहे अपने मौजूदा मैनेजर ईर्नेस्टो वाल्वर्डे की जगह लेने के लिए जाबी से संपर्क किया था। अल साद के खेल निदेशक मुहम्मद गुलाम अल बालुशी ने कहा, मैं इससे इन्कार नहीं करूंगा। जाबी को लेकर बातचीत चल रही है और सभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अभी जाबी अल साद में हैं। अल साद और बार्सिलोना के टीम प्रबंधन के अलावा मैनेजर को इस पर अंतिम फैसला करना है।

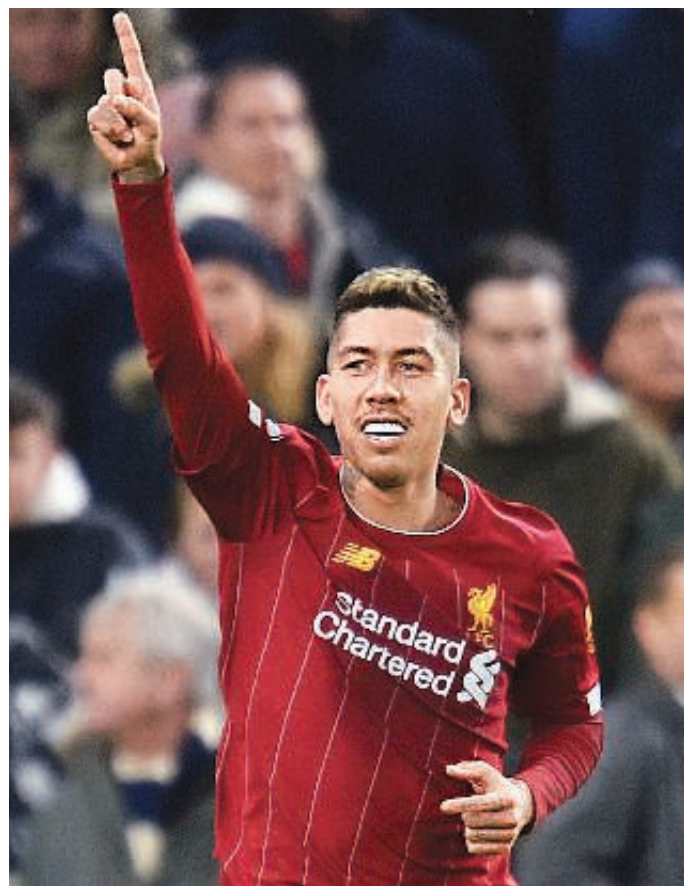

ईपीएल में टॉटनहम के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाते लिवरपूल के रॉबर्टो फर्मिनो। एएफपी

वापसी के बाद इब्राहिमोविक ने दागा पहला गोल

मिलान, एएफपी : इटालियन फुटबॉल लीग सीरी-ए में एसी मिलान ने शनिवार को काग्लियरी को 2-0 से हरा दिया। इस दौरान एसी मिलान में वापसी करने वाले ज्लाटन इब्राहिमोविक को पहली बार शुरुआती लाइन-अप में शामिल किया गया और उन्होंने इसका जश्न एक शानदार गोल के जरिये मनाया। एसी मिलान के लिए राफेल लियो ने 46वें मिनट में पहला गोल किया। वहीं आठ साल बाद एसी मिलान में वापसी करने वाले इब्राहिमोविक ने 64वें मिनट में वापसी के बाद पहला गोल दागा।

टेस्ट क्रिकेट काफी समय तक बने रहने वाला प्रारूप है : चेतेश्वर पुजारा

राजकोट, प्रेट्र : भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा यह बात स्वीकार करते हैं कि टी-20 क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि पारंपरिक टेस्ट प्रारूप भी काफी समय तक बना रहेगा। पुजारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि समय बदल रहा है और सफेद गेंद का क्रिकेट लोकप्रिय बन गया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमेशा विशेष है और यह हमेशा विशेष रहेगा। साथ ही हम उम्मीद लगाते हैं कि यह जितना संभव हो, उतने समय तक जारी रहे।

आइसीसी ने हाल में प्रस्ताव दिया कि 2023 से टेस्ट क्रिकेट को चार दिवसीय कर दिया जाए, लेकिन इसे खेल के कुछ महान खिलाड़ियों जैसे सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पुजारा ने कहा कि उनके 50वें प्रथम श्रेणी शतक से भारत के आगामी टेस्ट दौरे से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दो मैचों की यह सीरीज इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि वहां एक जीत से भारत शुरुआती विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2021 में होने वाले फाइनल के करीब पहुंच जाएगा।

शनिवार को यहां कर्नाटक के खिलाफ सौराष्ट्र के रणजी ट्रॉफी ग्रुप-बी मैच में पुजारा उन चुनिंदा महान क्रिकेटरों की जमात में शामिल हो गए, जिन्होंने प्रथम श्रेणी में 50 शतक जड़े हैं जिसमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे दौरों से पहले इस तरह की उपलब्धि हासिल करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने खेल पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर देते हो।

पुजारा ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप विदेश जाते हो तो आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेलते हो और आपको अपने खेल पर भरोसा करना होता है और अपनी तैयारियों पर विश्वास रखना होता है।

तैयारी

- भारतीय टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा विशेष रहेगा
- न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज को बताया अहम

चेतेश्वर पुजारा। फाइल फोटो, प्रेट्र

सीम गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर न्यूजीलैंड में अहम होगा : बांगर

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर को लगता है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टेस्ट टीम के लिए सीम गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर की मौजूदगी आदर्श होगी। नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली टीम के ज्यादातर सदस्यों को वह शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऑलराउंडर विजय शंकर को दो टेस्ट वाली सीरीज के लिए टीम में होना चाहिए। शंकर भारत की विश्व कप टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण वह बाहर हो गए। बांगर ने कहा कि अगर वे 17 खिलाड़ियों के साथ जाते हैं तो एक रिजर्व बल्लेबाज और ऑलराउंडर के लिए जगह होगी। न्यूजीलैंड की परिस्थितियां सीम गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि आप देखो कि कोलिन डि ग्रैंडहोम की मौजूदगी से न्यूजीलैंड टीम पर कैसा प्रभाव पड़ा। इसलिए विजय शंकर जैसा खिलाड़ी इस जगह के लिए आदर्श उम्मीदवार हो सकता है। इसके लिए उन्हें फिट होना चाहिए अगर वह छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं।

स्टोइनिस ने बीबीएल में बनाया सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर

मेलबर्न, प्रेट्र : मार्कस स्टोइनिस ने रविवार को यहां मेलबर्न स्टार्स के लिए 79 गेंद में 147 रन की पारी खेलकर बिग बैश लीग (बीबीएल) के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। उनकी इस आक्रामक पारी से मेलबर्न स्टार्स ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर सिडनी सिक्सर्स पर 44 रन से जीत हासिल की। स्टोइनिस ने इस विस्फोटकीय पारी के दौरन 13 चौके और आठ छक्के जमाए।

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर ने 2020 सत्र की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया था और फिर दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में उन्हें खरीद लिया। वह भारत में आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं हैं। स्टोइनिस ने इस तरह दो साल पहले बनाए गए डि आर्ची शॉर्ट के रिकॉर्ड को तोड़ा जिसमें उन्होंने 69 गेंद में नाबाद 122 रन की पारी खेली थी। स्टोइनिस और हिल्टन कार्टराइट (59) ने मेलबर्न स्टार्स को निर्धारित 20 ओवर में एक विकेट पर 219 रन बनाने में मदद की। इसके जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम सात विकेट पर 175 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी इस पारी को बेहतरीन करार दिया। स्टोइनिस आठ पारियों में 331 रन बनाकर बीबीएल के इस सत्र की सूची में शीर्ष पर चल रहे हैं।

पहली पारी में संभला असम, गंवाए तीन विकेट

नईदुनिया, रायपुर : एसीएस स्टेडियम गुवाहाटी में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के मैच में दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की पहली पारी 318 रन पर सिमटी। इसके बाद खेलने उतरी असम टीम की पहली पारी में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद टीम ने संभल कर खेलना शुरू किया और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट खोकर 209 रन बना लिए।

पहली पारी के आधार पर अभी भी असम छत्तीसगढ़ से 109 रन पीछे है। असम के ऋषभ दास ने 99 रनों की पारी खेली। कप्तान गोकुल शर्मा 50 और रियान पराग 24 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले रविवार को मैच के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ ने सात विकेट पर 276 रनों से आगे खेलना शुरू किया और टीम 105.3 ओवर में 318 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

सत्ता बदलने के बाद बदल गया दिल्ली की टीमों का प्रदर्शन

योगेश शर्मा, नई दिल्ली

- डीडीसीए की टीमों के प्रदर्शन में आ रहा है बदलाव
- 2017/18 के सत्र में दिल्ली की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता बनी

विवादों के गढ़ दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में भले ही टीमों के चयन पर सवाल उठ रहे हों लेकिन सत्ता बदलने के बाद दिल्ली की टीमों के प्रदर्शन में सुधार दिख रहा है।

2017/18 के सत्र में दिल्ली की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता रही थी जबकि अंडर-23 टीम ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अपने नाम की थी। अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। 2018/19 के सत्र में दिल्ली रणजी टीम ग्रुप चरण तक खेल पाई थी जबकि अंडर-23 टीम ने भी ग्रुप चरण तक का सफर तय किया था। यही, प्रदर्शन अंडर-19 टीम का भी रहा। हालांकि अंडर-16 टीम प्री-क्वार्टर फाइनल तक खेली थी।

वर्तमान सत्र में दिल्ली की टीमों का शुरुआती प्रदर्शन खराब रहा। रजत शर्मा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले साल 16 दिसंबर के बाद से तिहारा गुट डीडीसीए को चला रहा है। 16 दिसंबर से पहले दिल्ली रणजी टीम ने दो मैचों में एक मुकाबला ड्रॉ खेला तो एक में उसे हार मिली। वहीं, अंडर-23 टीम एकमात्र मैच को ड्रॉ खेलने पर मजबूर हुई। अंडर-19 टीम ने तीन मैच खेले और इसमें एक मैच ड्रॉ रहा और एक मैच टीम हार गई। एक मैच बेनतीजा रहा। अंडर-16 टीम ग्रुप चरण तक खेली थी। हालांकि पिछले साल 16 दिसंबर के बाद रणजी टीम ने दो मैचों में एक ड्रॉ खेला तो एक में जीत हासिल की। यहीं, प्रदर्शन अंडर-23 टीम का रहा था। अंडर-19 टीम ने तीन मैचों में एक जीत दर्ज की, एक मैच ड्रॉ खेला, एक मैच बेनतीजा रहा।

इसके अलावा 2017/18 के सत्र में दिल्ली की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता बनी तो विजय हजारे के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। टीम नॉर्थ जोन से वीनू मांकड की चैंपियन भी बनी थीं। 2018/19 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम ग्रुप चरण तक खेल पाई थी। विजय हजारे और अंडर-23 में टीम उप विजेता रही जबकि वीनू मांकड में टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। वर्तमान सत्र में टीम विजय हजारे के क्वार्टर फाइनल तक खेली थी जबकि सैयद मुश्ताक, अंडर-23 और वीनू मांकड में टीम सिर्फ ग्रुप चरण तक ही खेल पाई।

डीडीसीए के शीर्ष परिषद के संयोजक दिनेश शर्मा ने कहा कि जिन क्रिकेटरों के बीसीसीआइ से रजिस्ट्रेशन हो गए हैं हमने उन्हें टीम में शामिल किया और यहीं खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। जो भी खिलाड़ी उन्होंने चुने थे तो हम उन्हीं मैं से खिला रहे हैं। हमने बाहर से कोई बच्चे नहीं लिए हैं। 16 दिसंबर को हमने कार्यभार संभाला है और हमारी जो भी टीम खेल रही है, उनमें उन्हीं के खिलाड़ी हैं, बस चयनकर्ता, सीएसी और चेयरमैन बदले हैं। उन्हीं टीमों को हरा रहे हैं जो अपने ग्रुप में किसी टीम से नहीं हारी थीं।

विविध

गाजियाबाद में लूट के विरोध में महिला की हत्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : दिल्ली एनसीआर में बदमाशों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा में रीजनल मैनेजर से लूट और हत्या का मामला अभी गर्म है, इस बीच बदमाशों ने गाजियाबाद के लोनी में बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। शनिवार रात लोनी में चार बदमाशों ने घर में घुसकर लूट के विरोध में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर डेढ़ लाख रुपये और गहने लूट लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मूलरूप से मेरठ के जानी कस्बा निवासी आसिफ लोनी के बेहटा हाजीपुर गांव स्थित मकान में रहते हैं। मकान के ग्राउंड फ्लोर में वह मोबाइल चार्जर बनाने का काम करते हैं। प्रथम और द्वितीय तल पर परिवार रहता है। दो दिन पूर्व उनका साला जुनैद उनके घर आया था। शनिवार रात आसिफ, उनकी 34 वर्षीय पत्नी समरीन, तीन बच्चे तैमूर, उजमा और नमीरन प्रथम तल पर सोए हुए थे। उनका एक बेटा आतिफ अपने मामा जुनैद के साथ मकान के द्वितीय तल पर सोया था। आसिफ के मुताबिक रात करीब दो बजे चार बदमाश उनके घर में घुस आए। बदमाशों ने उन्हें गनप्वाइंट पर लेकर बंधक बना लिया। शोर सुनकर उनकी पत्नी जागी तो एक बदमाश ने उन्हें गनप्वाइंट पर ले लिया। अन्य दो बदमाशों ने दूसरी मंजिल पर जाकर जुनैद, आतिफ के हाथ पैर बांध दिए। बदमाशों ने अलमारी में रखे डेढ़ लाख रुपये और गहने निकाल लिए। बदमाशों ने समरीन से कानों के कुंडल और गले की चेन मांगी, इसका उन्होंने विरोध किया जिस पर बदमाशों ने समरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। बदमाशों के जाने पर आसिफ ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। पड़ोसियों ने पहुंचकर उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को बंधन मुक्त किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय का कहना है कि सीसीटीवी, पोस्टमार्टम, डॉग स्क्वॉड और फारेंसिक टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की पूछताछ में पीड़ित ने चार बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम देना बताया। जांच के दौरान गली एक ओर से बंद मिली। पुलिस ने पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। तीन बदमाशों की फुटेज पुलिस को मिली है।

गौरव हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतरे लोग

पीड़ित परिजनों को एक करोड़ मुआवजे की मांग, घटना का पर्दाफाश न होने को लेकर जताया आक्रोश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

गौरव चंदेल की हत्या के एक हफ्ते बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। गौरव को न्याय दिलाने को हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। पदयात्रा निकाल कर वे ग्रेटर नोएडा स्थित किसान चौक पर धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोग करीब ढाई घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। इस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान पुलिस को वाहनों का रूट डायवर्जन भी करना पड़ा। करीब ढाई घंटे बाद उन्होंने गौर सिटी पहुंच कर मृतक को श्रद्धांजलि दी।

गौरव चंदेल के हत्यारों की गिरफ्तारी व मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की मांग को लेकर सुबह हजारों लोग एक मूर्ति गोलचक्कर पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर एक करोड़ रुपये का मुआवजा व मृतक की पत्नी प्रीति चंदेल को सरकारी नौकरी की मांग की। लोगों ने कहा कि जब तक गौरव के हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते और उन्हें सजा नहीं मिल जाती, अभियान जारी रहेगा।

हत्याकांड का पर्दाफाश न होने पर लोगों में दिखा गुस्सा : गौरव चंदेल की हत्या के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही व हत्याकांड का पर्दाफाश न होने को लेकर लोगों में गुस्सा था। लोगों ने कहा कि यदि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज गौरव जिंदा होते।

पीड़ित परिवार पदयात्रा में नहीं हुआ शामिल : पद यात्रा में गौरव चंदेल के परिजन भी शामिल होने वाले थे, लेकिन अंतिम समय पर परिवार के लोग पदयात्रा में शामिल नहीं हो सके। सोसायटी के एक पार्क में आयोजित शांति सभा में भी पीड़ित परिवार के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि पुलिस के लचर रवैये के खिलाफ गौरव के परिवारवालों ने पदयात्रा करने का फैसला किया था।

प्रियंका ने ट्वीट कर सुरक्षा पर उठाए सवाल : गौरव चंदेल हत्याकांड मामले में रविवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रबंधक के पद पर काम करने वाले गौरव चंदेल की नोएडा में अपराधियों ने हत्या कर दी थी। लूटपाट के बाद हुई हत्या में सरकार की कार्रवाई अभी तक ढीली-ढाली है। नोएडा जैसे लोकेशन पर अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी। उन्होंने लिखा कि गौरव चंदेल के परिवार को न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए।

गौरव चंदेल की हत्या के विरोध में रविवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित किसान चौक पर रोड जाम कर धरना-प्रदर्शन करते आक्रोशित लोग। राजेश गौतम

मुख्यमंत्री के आदेश पर 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। स्वजन ने कुछ और मांगे भी रखी हैं। उन पर विचार किया जा रहा है।
– बीएन सिंह, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

डीएम ने पीड़िता को सौंपा 20 लाख का चेक

जिलाधिकारी बीएन सिंह रविवार देर शाम गौरव चंदेल के परिवार से मिलने गौर सिटी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये का चेक सौंपा। यह चेक गौरव की पत्नी प्रीति चंदेल को शासन की ओर से आर्थिक मदद के रूप में सौंपा गया। जिलाधिकारी के सामने प्रीति चंदेल फूट-फूट कर रोने लगीं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने प्रीति चंदेल व गौरव की मां प्रेमलता को हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया है।

देश भर को हुनर से रोजगार का संदेश देंगे हिमाचल के शिल्पी

अनिल बेताब, फरीदाबाद

34वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला एक तरफ देश-विदेश की कला-संस्कृति को बढ़ावा देगा, तो वहीं हिमाचल की परंपरागत शिल्पकला के कद्रदान मिलने से हिमाचल के शिल्पियों को बड़ा बाजार भी मिलेगा। हिमाचल पर्यटन विभाग स्वयं सहायता समूहों क माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। 1 से 16 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले में हिमाचल के 300 से ज्यादा कलाकार रोजाना मुख्य चौपाल पर सांस्कृतिक रंग बिखेरेंगे और 80 से ज्यादा शिल्पियों के उत्पादों के स्टाल होंगे। हिमाचल कला और शिल्प के मामले में विश्व प्रसिद्ध है। यहां के कालीन, चमड़े का काम, शॉल, पेंटिंग, मेटलवेयर, लकड़ी की पेंटिंग तथा रंगीन हिमाचली टोपियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से कुल्लू तो शॉल डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है।

इन सब पर केंद्रित करते हुए हिमाचल में स्वयं सहायता समूह बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल सरकार इन समूहों के माध्यम से रोजगार को बढ़ाने में लगी है। मेला परिसर में रविवार को हिमाचल पर्यटन विभाग के निदेशक युनूस ने सूरजकुंड मेला के नोडल अधिकारी से मिल कर तैयारियों को लेकर विस्तृत बातचीत भी की। मेले में पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान है, तो थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है।

मेले में पहली बार शिरकत करेगा इंग्लैंड : सूरजकुंड मेले में पहली बार इंग्लैंड की संस्कृति व कला के दर्शन होंगे। इंग्लैंड के कलाकार मुख्य चौपाल पर कार्यक्रम प्रस्तुति करेंगे, तो वहां की शिल्पियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेश सरकार की पहल पर इंग्लैंड को मेले में आमंत्रित किया गया है। अभी यह तय किया जाना है कि इंग्लैंड के कितने कलाकार और शिल्पी आएंगे। मेले में आने वाले लोगों के लिए इंग्लैंड की कला देखना अलग अनुभव होगा।

सूरजकुंड मेला

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परंपरागत कला को मिलेगा बढ़ावा

हमारा प्रयास है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हिमाचल की परंपरागत कला को ऐसे बढ़ाया जाए, जिससे रोजगार के अवसर मिलें। कला विकसित होगी, तो शिल्पियों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। हमें विश्वास है कि मेला हिमाचल की परंपरागत कला को बढ़ाने में सहायक साबित होगा।
– युनूस, हिमाचल पर्यटन विभाग

मेले में जिस तरह हिमाचल के स्वयं सहायता समूह होंगे, ठीक वैसे ही हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों के भी कई स्टाल होंगे। इस तरह मेला रोजगार के लिहाज से बेहद उपयोगी रहेगा। इस बार मेले में इंग्लैंड की शिरकत से कुछ नयापन होगा। इंग्लैंड से एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। अभी तक 30 देशों ने मेले में शिरकत करने को मंजूरी दी है।
– राजेश जून, नोडल अधिकारी, सूरजकुंड मेला

बारह साल के अब्दुल हई ने कराया निकाह

जागरण संवाददाता, लखनऊ

खानदान-ए-फरंगी महल के चिराग अब्दुल हई रशीद फरंगी महली ने निकाह का खुतबा पढ़ाकर अनोखा रिकार्ड बनाया। इतनी छोटी उम्र में अब्दुल हई को निकाह की रस्म अदा करते देख शादी में शामिल हर कोई दंग रह गया। दूल्हा-दुल्हन के साथ रिश्तेदारों ने 12 वर्षीय अब्दुल हई को निकाह पढ़ाने की मुबारकबाद दी। बेटे को मिल रही मुबारकबाद से पिता ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद को चेहरा भी खिल उठा।

दरअसल, बीती रात ऐशबाग ईदगाह में कामिल उमर जिलानी और अलीना मिर्जा का निकाह था। दूल्हे की तरफ से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली को निकाह पढ़ाना था। मौलाना अपने बेटे अब्दुल हई रशीद फरंगी महली को लेकर पहुंचे थे। जब निकाह का समय हुआ तो दूल्हे के वालिद खालिद जिलानी ने मौलाना से अपने बेटे अब्दुल हई से निकाह का खुतबा पढ़ाने की फरमाइश की, जिसको कुबूल कर मौलाना ने अब्दुल हई को आगे कर दिया।

पहले तो दूल्हा-दुल्हन के परिवार को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन जब अब्दुल हई ने खुतबा पढ़ा तो वहां मौजूद मेहमान दंग रह गए। इसके बाद मौलाना खालिद रशीद ने दूल्हा-दुल्हन के कबूलनामे के बाद निकाह को मुकम्मल कराया। मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि निकाह का खुतबा पढ़ाने में बालिग होना शर्त नहीं है, इसलिए उन्होंने फरमाइश को कुबूल कर बेटे से निकाह का खुतबा पढ़ाया।

इन्होंने भी दिया था खुतबा

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि उनके बड़े भाई मौलाना तारिक रशीद फरंगी महली भी छोटी सी उम्र में निकाह का खुतबा पढ़ चुके हैं।

कर रहे कुरान हिफ्ज

अब्दुल हई लॉमार्टिनियर कॉलेज में कक्षा पांच के छात्र हैं। इन दिनों वह कुरआन शरीफ को हिफ्ज (याद) कर रहे हैं। वह रोज मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। पिछले वर्ष 2019 में उन्होंने पहली बार कनाडा में निकाह का खुतबा पढ़ा था।

कर्नल के फ्लैट की ग्रिल काटकर आठ लाख की चोरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : साकेत थानाक्षेत्र के गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में कर्नल के फ्लैट से बृहस्पतिवार रात चोर करीब आठ लाख माल चुराकर ले गए। चोर खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल काटकर फ्लैट के अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार सुबह सेना के जवान के आने पर ग्रिल काटे जाने की सूचना मिली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

साकेत के गोल्फ व्यू अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में सत्यजीत पुजारी, पत्नी तन्मइ पुजारी व बेटे रिची के साथ रहते हैं। सत्यजीत पुजारी सेना में कर्नल हैं। बीते करीब सात माह से ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए हुए थे। गत 28 दिसंबर को उनकी पत्नी उनसे मिलने हैदराबाद गई थीं।

मौसम विशेष

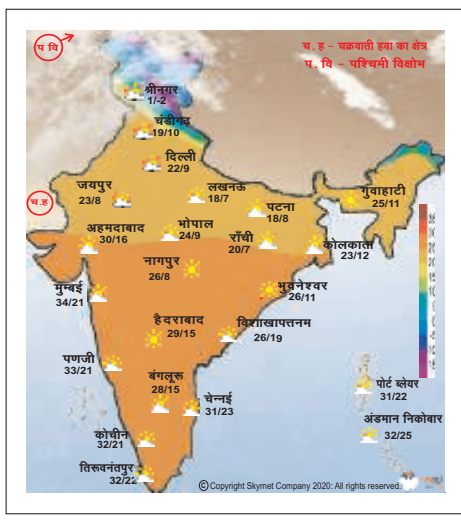

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में मध्यम वर्षा तथा भारी बर्फबारी जारी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान में गरज के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि संभव है। ठंडी सुबह में मध्यम कोहरा छाया रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/आंबा	अहमदाबाद	25/07/आंबा
कोलकाता	23/12/आंबा	बड़ौदा	25/12/सा
चेन्नई	31/22/आंबा	नागपुर	26/09/आंबा
हैदराबाद	30/16/आंबा	इन्दौर	25/12/वि
बंगलूरू	29/16/आंबा	रांची	29/14/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/23/वि	पटना	29/13/वि
गुवाहाटी	26/17/सा	जमशेदपुर	32/17/आंबा
गंगटोक	10/-6/ आंबा	पुणे	30/16/सा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 13 जनवरी 2020
आजकल
16
www.jagran.com

मिकी माउस कार्टून स्ट्रिप का प्रकाशन प्रारंभ हुआ

आज ही के दिन सुप्रसिद्ध मिकी माउस कार्टून स्ट्रिप का प्रकाशन 1930 में प्रारंभ हुआ। इसे इतनी लोकप्रियता मिली कि 1931 में अमेरिका के 60 अखबारों ने प्रकाशित किया। उसी साल 20 से ज्यादा अन्य देशों में भी छपा।

सांप्रदायिक सद्भाव के लिए महात्मा गांधी का अंतिम आमरण अनशन

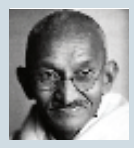

आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी ने अपना आखिरी आमरण अनशन दिल्ली में शुरू किया था। यह किसी पार्टी या संगठन के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के विवेक के लिए था। उस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हो रही थी। दंगाइयों पर नैतिक दबाव बनाने के लिए शुरू यह अनशन 18 जनवरी को समाप्त हुआ।

अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा

आज ही के दिन 1949 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म पटियाला में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे एयरफोर्स में शामिल हो गए। सितंबर 1982 में उनका चयन अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए हुआ। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट सोयूज टी-11 के जरिये अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और सेल्यूट -7 अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। जहां उन्होंने करीब आठ दिन बिताए। उन्हें भारत सरकार ने अशोक चक्र और सोवियत संघ ने हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन सम्मान से नवाजा।

इधर-उधर की

दुल्हन के लिए दूल्हे ने दी अंग्रेजी की परीक्षा

बीजिंग, एजेंसी : चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक दूल्हे को अपनी दुल्हन ले जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुल्हन के परिवार के लोगों के सामने दूल्हे को अंग्रेजी परीक्षा पास करनी थी। दरअसल, दुल्हन के परिवार के लोग दूल्हे के साथ अंग्रेजी में बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहते थे। इस परीक्षा में दूल्हे को अंग्रेजी सुननी थी और सवालों के सौ फीसद सही जवाब देने थे। तीन साल विदेश में रहे दूल्हे के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह झट से इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन अफसोस आवाज सुनने के बाद उसने दो सवालों के गलत जवाब दिए। दूल्हे का कहना था कि आवाज काफी कर्कश थी और उसे डेढ गुना तेज गति से सुनाया गया था। अपनी हार से दूल्हा काफी निराश था। हालांकि दूल्हे के साथ अक्सर ऐसी शरारतें की जाती हैं। हार के बाद दूल्हे को रुपयों से भरे लाल पैकेट को दुल्हन को थमाना होता है। दूल्हा और दुल्हन गुआंगडोंग प्रांत स्थित विश्वविद्यालय से विदेशी अध्ययन में स्नातक हैं।

नया प्रोटीन भी कम कर सकता है मोटापा

- शरीर में 'आइआरएचओएम2' के स्तर में कमी लाने से घटने लगती है वसा
- मोटापे की समस्या से जूझ रही है पुर्तगाल की आधी आबादी

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : मोटापा कम करने के लिए आप लोगों को अक्सर जिम में खूब पसीना बहाते या फिर खूब दौड़-भाग करते देखते होंगे। इसके बावजूद भी कई लोगों पर इन सब प्रयासों का कोई खास असर होता नहीं दिखता है। मोटापे से शरीर गंभीर व्याधियों से घिर जाता है और कई लोगों की मौत का कारण भी बनता है। इस समस्या से बचने के लिए अब शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका सुझाया है। उन्होंने मोटापे से जुड़े एक नए प्रोटीन की पहचान की है, जो शरीर से वसा कम करने में मदद कर सकता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि आइआरएचओएम2 नामक प्रोटीन में कमी लाए जाने से मोटापा कम किया जा सकता है। उन्होंने यह निष्कर्ष चूहों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है।

मोटापा पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती के तौर पर उभर रहा है। इस समस्या के चलते हृदय रोग से लेकर डायबिटीज रोग का खतरा बढ़ रहा है। मोटापे के मामले में पुर्तगाल के हालात सबसे खराब हैं। यहां लगभग आधी आबादी मोटापे की समस्या से ग्रस्त है और लगभग 10 लाख वयस्क भी इसकी चपेट में हैं।

मॉलीक्यूलर मेटाबोलिज्म जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में प्रमुख शोधकर्ता कोलिन एड्रेन ने कहा, 'शोध के दौरान मेटाबोलिक टिश्यू और अंगों में आइआरएचओएम 2 प्रोटीन की व्यापक मौजूदगी पाई गई है। इस आधार पर हमने मोटापे में इस प्रोटीन की भूमिका पर विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया है।'

ऐसे किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने माउस मॉडल का प्रयोग किया और उन्हें दो समूहों में बांटा और उनके आइआरएचओएम2 नामक प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित किया। साथ ही, एक समूह के चूहों को सामान्य भोजन दिया गया, जबकि दूसरे समूह को हाई-फैट वाले खाद्य पदार्थ दिए गए। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिस समूह के चूहों को हाई-फैट वाले खाद्य पदार्थ दिए गए थे उनमें दूसरे समूह के चूहों के मुकाबले कई ज्यादा मोटे हो गए थे।

अभी परीक्षण की है जरूरत : शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि मनुष्यों में भी 'आइआरएचओएम2' के स्तर को नियंत्रित किया जाए तो मोटापे का जोखिम बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले कई दौर के परीक्षणों की आवश्यकता है।

नासा के अंतरिक्ष अभियान में ईरानी मूल की जैस्मीन भी

स्पेक्ट्रम

नासा के अगले अभियान के लिए चुनी गईं ईरानी मूल की हेलीकॉप्टर पायलट जैस्मीन मोगबेली। एएफपी

ह्यूस्टन, एएफपी : अंतरिक्ष में नासा के अगले अभियान के लिए चुनी गईं जैस्मीन मोगबेली ईरानी मूल की पहली अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिकी मरीन कोर की मेजर जैस्मीन हेलीकॉप्टर गनशिप पायलट के तौर पर अफगानिस्तान में 150 से ज्यादा अभियानों में हिस्सा ले चुकी हैं। एमआइटी यूनिवर्सिटी से स्नातक जैस्मीन बास्केटबॉल की भी अच्छी खिलाड़ी हैं। जैस्मीन का चयन ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिकी हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है।

जैस्मीन (36) के माता-पिता ईरानी थे। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद वे ईरान छोड़कर जर्मनी चले गए थे, जहां जैस्मीन और उनके भाई का जन्म हुआ। न्यूयॉर्क के बाल्डविन में पली-बढ़ीं जैस्मीन उसे ही अपना घर मानती हैं। मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक जैस्मीन ने जब सैन्य पायलट बनने की इच्छा जताई थी तो उनके माता-पिता हैरान रह गए थे। लेकिन जब वह सेना में शामिल हो गईं तो माता-पिता ने उनका पूरा साथ दिया। वह 2005 में अमेरिकी सेना में शामिल हुई थीं। अपनी सभी सफलताओं के लिए माता-पिता और अपने पार्टनर सैम को श्रेय देने वाली जैस्मीन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस सफलता से सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग प्रभावित होंगे। जैस्मीन तीन माह पहले ही अपने पार्टनर सैम के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं।

नासा ने खोज निकाला रहने योग्य ग्रह

रहस्यमय ब्रह्मांड ▶ वैज्ञानिकों का दावा, पृथ्वी के आकार का है 'टीओआइ 700डी'

स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ग्रह मिलने के दावे की अंतरिक्ष एजेंसी ने की पुष्टि

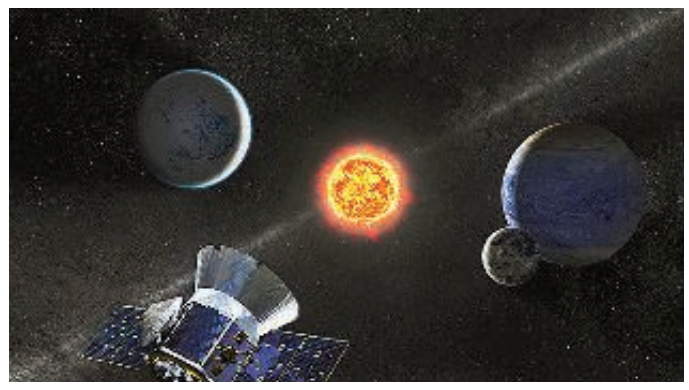

एम ड्वार्फ सिस्टम का अवलोकन करता टीइइएस। साभार : नासा

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (टीइइएस)ने एक जीवन के अनुकूल यानी रहने योग्य ग्रह की खोज की है और सबसे बड़ी बात कि यह पृथ्वी के आकार का है। यह ग्रह अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में मिला है, जहां उसकी सतह पर पानी के अस्तित्व के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने नासा के स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से टीओआइ 700डी नामक ग्रह खोज निकालने के दावे की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित जानकारियों को हासिल करने के लिए इस ग्रह के संभावित वायुमंडल का नमूना तैयार किया। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए पृथ्वी की आकार का ग्रह टीओआइ 700डी उन चुनिंदा ग्रहों में एक है, जो तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है।

नासा के एस्ट्रोफिजिक्स विभाग के निदेशक पॉस हट्र्ज ने बताया, 'टीइइएस को विशेष रूप से पृथ्वी के आकार के ग्रहों को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे तारों के आसपास के ग्रह को अंतरिक्ष में देखना आसान होता है। टीओआइ 700डी को खोजना टीइइएस की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज है। इसका आकार पृथ्वी जैसा ही है और यह रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। स्पित्जर की मदद से यह पता लगाना इसकी दूसरी सबसे बड़ी सफलता है।' टीइइएस आकाश के बड़े हिस्से की मॉनिटरिंग करता है। आकाश के इस बड़े हिस्से को सेक्टर कहते हैं। यह उपग्रह को तारों की चमक में बदलाव का पता लगाने मदद करता है। बता दें कि तारों में यह चमक तारों की परिक्रमा के दौरान बदलती है।

क्या है इस ग्रह की खूबी : टीओआइ 700डी एक छोटा ग्रह है, जो दक्षिणी नक्षत्र डोराडो में 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य के द्रव्यमान और आकार का एक-चौथाई है। वहीं, इसकी सतह का तापमान सूर्य का आधा है। यह टीईएसएस डाटाबेस में हमारे सूर्य के समान था, जिसका मतलब है कि ये ग्रह जैसे हैं, उससे अधिक बड़े और गर्म दिखाई देते हैं। टीइएसएस टीम के साथ काम करने वाले हाईस्कूल के छात्र एल्टन स्पेंसर सहित कई शोधकर्ताओं ने इस त्रुटि की पहचान की। शोधकर्ता एमिली गिल्बर्ट ने बताया, 'जब हमने तारे के मापदंडों को सही किया, तो इसके ग्रहों के आकार छोटे हो गए और हमें लगा कि इसके बाहरी हिस्से में स्थित ग्रह पृथ्वी के आकार का है और साथ ही रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है।'

10 दिन में तारे की परिक्रमा पूरी करता है टीओआइ700 बी : गिल्बर्ट ने बताया कि टीओआइ700 बी तारे के केंद्र के पास स्थित है और इसका आकार पृथ्वी के आसपास है। यह चट्टानों वाला है और हर 10 दिन में अपनी कक्षा की परिक्रमा पूरी कर लेता है। वहीं, टीओआइ700 सी मध्यम प्रकार का ग्रह है, जो पृथ्वी से 2.6 गुना अधिक बड़ा है। यह हर 16 दिन पर अपनी कक्षा की परिक्रमा पूरी कर लेता है और माना जाता है कि इस ग्रह पर गैस की बहुतायात मात्रा है।

सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में है स्थित : टीओआइ700 डी इस सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित है और यही एकमात्र ग्रह है, जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी से 20 फीसदी अधिक बड़ा है और हर 37 दिन पर अपनी कक्षा की परिक्रमा पूरी कर लेता है।

सटीक वायुमंडलीय स्थिति का अनुमान लगाना शेष : शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य के मिशन से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि इन ग्रहों पर वायुमंडल हैं या नहीं। अगर है, तो इसके क्या-क्या घटक हैं। अभी टीओआइ 700डी के वायुमंडल की सटीक स्थिति का पता नहीं चल सका है, फिर भी वैज्ञानिक इसके आकार और कक्षा की परिक्रमा जैसी मौजूदा सूचनाओं का प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं।

तेजी से घट रहा है मंगल ग्रह का पानी

- एग्जोमार्स मिशन के डाटा का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने किया दावा
- सूर्य की किरणों और रसायन शास्त्र के कारण अलग हो रहे हैं पानी के अणु

प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : मंगल ग्रह पर पानी पुराने अवलोकनों के मुकाबले बहुत तेजी से घट रहा है। एक नए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है जिसमें एग्जोमार्स मिशन के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएनआरएस) के शोधकर्ताओं ने कहा कि लाल ग्रह यानी मंगल के ऊपरी वातावरण से पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सूर्य की रोशनी और रसायन शास्त्र पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में अलग-अलग कर देते हैं, जिन्हें मंगल ग्रह का कमजोर गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में जाने से नहीं रोक सकता है।

यह अध्ययन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह के वातावरण से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलवाष्प बड़ी मात्रा में और अप्रत्याशित अनुपात में जमा हो रहा है।

अध्ययन बताते हैं कि बड़े वायुमंडलीय पॉकेट्स में सूखे की स्थिति भी बनने लगी है। इनके वातावरण में मौजूद पानी वाष्प बनकर उड़ गया है, जबकि सैद्धांतिक रूप इनका तामपान कम होना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने कहा कि कुछ विशेष इन क्षेत्रों से पानी के वाष्प बनने की प्रक्रिया में काफी तेजी आ सकती है। इस परिणामों को एक्जोमार्स मिशन के ट्रेस गैस ऑर्बिटर उपकरण की मदद से हासिल किया गया था। इस मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने वित्तीय मदद दी थी।

शोध अनुसंधान

एक रात की नींद में खलल से भी हो सकता है अल्जाइमर

हाल में हुए एक अध्ययन से इस बात का पता चला है कि सिर्फ एक रात की नींद में खलल पड़ने से भी अल्जाइमर रोग का खतरा पैदा हो सकता है। शोध के मुताबिक नींद में व्यवधान किसी भी स्वस्थ पुरुष के शरीर में तेऊ प्रोटीन को बढ़ा देता है, जिससे भूलने की बीमारी अल्जाइमर की संभावना बढ़ जाती है। मेडिकल जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक यह प्रोटीन मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को एकजुट रखने में मदद करता है। अगर किसी के शरीर में असामान्य रूप से तेऊ प्रोटीन बनता है तो आंतरिक कोशिकाएं अलग हो सकती हैं, जिससे अल्जाइमर हो सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉ डॉन डेक्स्टर ने कहा, जब हमें सामान्य नींद आती है और असामान्य प्रोटीन की निकासी में सुधार होता है तो हमें अच्छा लगता है। -एएनआइ

धूमपान और मोटापे जितना ही खतरनाक है अकेलापन

बुजुर्गों के लिए अकेलापन उतना ही खतरनाक है, जितना धूमपान और मोटापा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने इस माहौल में खुद को अकेला महसूस करने वाले लोगों के सामान्य कारकों की पहचान की है। एजिंग एंड मेंटल हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में कहा गया है कि अकेलेपन की प्रमुख वजह व्यक्तिगत और पर्यावरणीय है। कुछ लोगों ने अकेलेपन की वजह जीवनसाथी, भाई-बहन की मौत को बताया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नए दोस्त पुरानों की कमी पूरी नहीं कर सकते। उद्देश्य की कमी भी इसकी वजह हो सकती है। -आइएएनएस

ज्वालामुखी फटा

फिलीपीस के कैविटी प्रांत में लूजन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी में रविवार को विस्फोट हो गया। इससे 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक लावा और धुआं फैल गया। इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्कनोलॉजी एवं सिस्मोलॉजी ने अलर्ट जारी किया है और आसपास के इलाकों को खाली कराने का सरकार से अनुरोध किया है। यह फिलीपीस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अब तक 33 विस्फोट हो चुके हैं। आखिरी बार वर्ष 1977 में यहां विस्फोट हुआ था। एपी

अच्छे स्वास्थ्य के लिए बर्फ के पानी में स्नान

जापान की राजधानी टोक्यो स्थित प्रमुख इनारी मंदिर में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग आत्मशुद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए बर्फ के पानी में बैठकर प्रार्थना करते हैं। इस दौरान लोगों को बर्फ का टुकड़ा भी पकड़ना होता है। इसे बेहद कठिन साधना माना जाता है और यह एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। इस वर्ष इस समारोह में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। रायटर

स्क्रीन शॉट

कोई भावुक होकर काम नहीं देता : नीना गुप्ता

सात सवाल

काम न मिलने की शिकायत के बाद लगातार फिल्में कर रहीं अभिनेत्री नीना गुप्ता अब 'पंगा' और 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में नजर आएंगी। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑडिबल सुनो पर वह 'ए दिल है कॉम्प्लिकेटेड' में प्यार और रिलेशनशिप से संबंधित कहानी सुना रही हैं। उनसे बातचीत :

आपने शिकायत की थी कि काम नहीं मिल रहा है, वह शिकायत अब दूर हो गई है?

- थोड़ी-सी शिकायत दूर हुई है। मैं बहुत लालची हूं। अभी और शिकायतें बाकी हैं।

'सांड की आंख' फिल्म की रिलीज के दौरान आपने कहा था कि उम्रदराज किरदार युवा अभिनेत्रियों की बजाय उम्रदराज अभिनेत्रियों को दिए जाने चाहिए...

- मैंने जो कहा था, उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। फिल्में बनाना एक बिजनेस है। जो कलाकार डिमांड में होता है, उसे लेना पड़ता है। अनुराग कश्यप से मैंने कहा था कि 'सांड की आंख' में मुझे वह किरदार क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्रदराज किरदार के बारे में ही सोचा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माताओं को युवा कलाकार चाहिए थे। हो सकता है कल मेरी डिमांड बढ़ जाए, तो निर्माता मुझे तवज्जो देने लगें। यह इस पर निर्भर करता है कि बतौर कलाकार आप बिक रहे हैं या नहीं। यहां कोई भावुक होकर काम नहीं देता है। अगर मैं फिल्म के लिए सही हूं, बजट में फिट हूं, बिकने वाली कलाकार हूं, तो काम मिलेगा।

ऑडिबल सुनो पर कहानियां सुनाने का अनुभव कैसा रहा? लगता है कहानियां सुनने का दौर अब भी है?

- जो कहानियां मैंने सुनाई हैं, उनमें से कुछ कहानियां मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी, कुछ भावुक करने वाली थीं। उन कहानियों के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कहानियां मुझे सुनानी थीं। अब कहानियां पढ़ने का दौर खत्म हो गया है। अब लोगों के पास पढ़ने का वक्त नहीं है, इसलिए कहानियां सुनने लगे हैं।

पर्दे पर आप लगातार मां की भूमिका निभा रही हैं। मां की भूमिकाएं पहले के मुकाबले कितनी बदली हैं?

- कुछ नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही है। जब निजी जिंदगी में ही मांएं सशक्त नहीं हैं, तो पर्दे पर उनके किरदार कहां से सशक्त नजर आएंगे।

सोशल मीडिया पर आप अक्सर अपनी दिल की बातें साझा करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर 'सच कहूं तो' सीरीज शुरू करने के पीछे क्या वजह रही?

- मुझसे लोग मेरे जीवन को लेकर सवाल पूछते हैं। मुझे लगा, जो मेरे मन में है, वह लोगों से साझा करना चाहिए। मुझे लोगों से बहुत-सी बातें कहनी हैं। खासकर महिलाओं से। हमारे देश की महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, वह देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। उन्हें हिम्मत देने के लिए मैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के जरिए बात करती हूं।

महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए शुरुआत कहां से करनी होगी?

- महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें पढ़ाना जरूरी है। बेटी जब पढ़ेगी तो वह अपने निर्णय खुद ले पाएगी। शिक्षा हर समस्या का हल है। लोग जब शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, तब दूसरी गलत बातों की ओर ध्यान नहीं जाएगा। वे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचेंगे।

आपकी फिल्म 'ग्वालियर' और 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' की कहानी क्या होगी?

-'ग्वालियर' में संजय मिश्रा और मैं दंपती बने हैं। दंपती के जीवन में कुछ घटता है, जिससे उनका जीवन बदल जाता है। 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में मैं आयुष्मान खुराना के दोस्त की मां का किरदार निभा रही हूं। इस फिल्म में मां का किरदार बहुत ही अलग होगा।

प्रियंका सिंह

'मिमी' के लिए पंद्रह किलो वजन बढ़ाएंगी कृति

पिछले साल कृति की फिल्में 'हाउसफुल 4' और 'पानीपत' सफल रहीं। साल 2020 की शुरुआत भी वह खास फिल्म के साथ करने वाली हैं। कृति फिल्म 'मिमी' में अपने एक अलग ही रूप में सामने आने वाली हैं। कृति को भी अपनी आने वाली इस फिल्म के लिए 15 किलो वजन बढ़ाने का मुश्किल काम करना होगा। कृति हमेशा से दुबली-पतली और फिट दिखने वाली अभिनेत्री हैं। सरोगेसी पर आधारित इस फिल्म में कृति नए अवतार में होंगी। कृति कहती हैं, 'इतना वजन बढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह मेरे लिए नया अनुभव होगा। कम समय में ज्यादा वजन बढ़ाने के लिए मुझे अपने मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन लाना होगा। कैलारी लेने की मात्रा को बढ़ाना होगा। लेकिन मैं इस परिवर्तन को देखने के लिए काफी उत्सुक हूं। यह किरदार मेरे दिल के बेहद करीब है और मैं इसके लिए जो भी कर सकती हूं, करने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि मैं इस बीच कोई दूसरा काम भी स्वीकार नहीं करूंगी।' वजन बढ़ाने के लिए कृति अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रही हैं। उन्होंने अपने खाने की मात्रा को भी और बढ़ा दिया है। कई बार भूख नहीं होने पर भी उन्हें खाना पड़ता है। फिल्म 'मिमी' में कृति सैनन के साथ अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी हैं। लक्ष्मण उतरेकर निर्देशित यह हिंदी फिल्म मराठी फिल्म 'माला आई वोहिचाई' पर आधारित है, जिसे साल 2011 में सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके अलावा कृति अक्षय कुमार के अपोजिट 'बच्चन पांडे' में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। यह भी खबर है कि सलमान खान की फिल्म 'कभी ईद कभी दीवाली' में सलमान की हीरोइन कृति सैनन ही होने वाली हैं, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

अध्ययन

गणितीय मॉडल से थम सकती हैं सड़क दुर्घटनाएं

आइआइटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा- नए मॉडल से दुर्घटना संभावित चौराहों की पहचान होगी आसान, कम की जा सकती है जान-माल की क्षति

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा गणितीय मॉडल विकसित किया है, जिससे चौक-चाराहों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नए मॉडल से दुर्घटना संभावित चौराहों की पहचान करने के साथ ही व्यापक स्तर पर उनमें सुधार करने में मदद मिल सकती है और लोगों की जान बचाई जा सकती है।

यह अध्ययन सड़क पर चलने वाले लोगों की धारणा और उनकी प्रतिक्रिया में लगने वाले समय पर भी आधारित है। तकनीकी भाषा में इसे पर्सेप्शन-रिएक्शन टाइम कहते हैं, जो दुर्घटना के क्षणों में लोगों की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। खराब सड़क या किसी अन्य आपात स्थिति में वाहन धीमा करना या फिर अचानक ब्रेक मारना सड़क पर चलने वाले लोगों की प्रतिक्रिया के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही, शोधकर्ताओं ने पोस्ट एंक्रोचमेंट टाइम (पीईटी) के आधार पर भी वाहनों के टकराने की घटनाओं का अध्ययन किया है। सड़क पर दुर्घटना की आशंका वाले बिंदु से होकर गुजरने वाले वाहनों के बीच समय के अंतर को पीईटी कहते हैं।

ऐसे किया अध्ययन : शोध पत्रिका एडवांसेज इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ऐसे सिग्नल रहित चौराहों को शामिल किया गया है, जहां पिछले पांच वर्षों में दाएं मुड़ने के दौरान वाहनों के टकराने की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। चौराहों पर लगे वीडियो कैमरों की मदद से ट्रैफिक संबंधी आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और फिर उनका विश्लेषण किया गया है। रिकॉर्ड किए गए वीडियो की मदद से बड़ी और छोटी सड़कों से गुजरने वाले वाहनों के विस्तार, सड़क पर उनके संयोजन और इंटरैक्शन के बारे में वाहनों की जानकारी एकत्र की गई है।

दोपहिया और हल्के वाहनों से होती हैं सर्वाधिक दुर्घटनाएं : अध्ययन से पता चला है कि चौराहों पर वाहनों के टकराने की अधिकतर घटनाएं दोपहिया और हल्के व्यावसायिक वाहनों के गुजरने के दौरान देखी गई हैं। दोपहिया वाहनों का आकार छोटा होने के कारण अन्य वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करते उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण चौराहों पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं।

ज्यामितीय डिजाइन में संशोधन से फायदा : शोधकर्ताओं ने कहा नए मॉडल के जरिये दुर्घटना संभावित चौराहों के ज्यामितीय डिजाइन में संशोधन जैसे इंजीनियरिंग उपाय, ट्रैफिक नियंत्रण एवं प्रबंधन तकनीकों के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

1.5 लाख लोग गंवा देते हैं जान : भारत में हर साल होने वाले सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ती है। इन दुर्घटनाओं में से करीब 1.4 लाख सड़क हादसे राजमार्गों पर होते हैं। वर्ष 2018 में 54 हजार लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।